{ विश्वास वही रफ्तार नई }

बालाघाट
शनिवार 18 जुलाई 2026
आषाढ शुक्ल 04 विक्रम सम्वत 2083
वर्ष 16, अंक 294
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

PMG पद्मेश मीडिया समूह का प्रकाशन

बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

सेंसेक्स	-	78,151.45
निफ्टी	-	24,334.30
सोना	-	1,50,718
चांदी	-	2,30,000
डॉलर	-	96.28

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

खास खबर

आईपीएस अनुराग बने नए कमिश्नर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया है। उन्होंने सतीश गोलचा की जगह ली है, जो अगस्त 2025 से दिल्ली के पुलिस प्रमुख थे। अनुराग कुमार 1994 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और इस शीर्ष पद को संभालने से पहले वे इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं। इस नियुक्ति से ठीक एक दिन पहले, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अनुराग कुमार को उनके मूल एजीएमयूटी कैडर में वापस भेजने (रिपेट्रिएशन) की मंजूरी दी थी। बता दें कि उन्हें अपने अच्छे कामों के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुके हैं। साल 2010 में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 2016 में उन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस भी मिला। ये सम्मान उनके उत्कृष्ट कार्य, अनुशासन और पुलिस सेवा में शानदार योगदान का प्रमाण माने जाते हैं।

लालू यादव की तबीयत बिगड़ी

पटना। राजद अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत शुक्रवार को अचानक बिगड़ गई। वह नियमित नेत्र परीक्षण के लिए शाम को आइजीआइएमएस पहुंचे थे। इसी दौरान जांच में उनके रक्तचाप (बीपी) में उतार-चढ़ाव पाया गया। बीपी में असामान्य बदलाव के बाद डॉक्टरों ने एहतियातन उनका ईसीजी कराया। जांच में कुछ बदलाव सामने आने पर चिकित्सकों ने उन्हें निगरानी में रखने का निर्णय लिया। इसके बाद लालू प्रसाद को अस्पताल में भर्ती कर करीब दो घंटे तक डॉक्टरों की टीम की निगरानी में रखा गया।

सर गैरी सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन

स्पोर्ट्स डेस्क। वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स का 89 साल की आयु में निधन हो गया है। एक ओवर की सभी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। उन्होंने यह कारनामा फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में किया था। उन्होंने 1968 में नॉटिंघमशायर की तरफ से खेलते हुए ग्लेमोर्गन के खिलाफ सेंट हेलेन्स मैदान पर एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे। सोबर्स ने साल 1953 में 16 साल की उम्र में बारबाडोस के लिए अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था। इसके अगले ही साल 1954 में उन्हें वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया। साल 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया और नाबाद 365 रन की पारी खेली। यह टेस्ट मैच की एक पारी में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था, जिसे 1994 में वेस्टइंडीज के ही ब्रायन लारा ने तोड़ा।

कुछ ना कहना

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू

जापान और इंग्लैंड के मुकाबले सस्ता किराया : 70 किलोमीटर का किराया मात्र 26 रुपये

नई दिल्ली। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुक्रवार को जींद और सोनीपत के बीच सफल उद्घाटन हो गया है। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही इसके किराए को लेकर चल रही उत्सुकता पर विराम लग गया है। भारतीय रेलवे द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, जींद से सोनीपत के बीच 70 किलोमीटर के पूरे सफर के लिए यात्रियों को मात्र 26 रुपये चुकाना होगा। इसका मतलब है कि यात्रियों को प्रति किलोमीटर सफर के लिए केवल 36 पैसे का खर्च आएगा, जो वैश्विक स्तर पर चल रही अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में बेहद सस्ता है।

अगर दुनिया के अन्य देशों से तुलना करने पर विदेशों में हाइड्रोजन ट्रेन का सफर भारतीय यात्रियों के मुकाबले काफी महंगा है। वर्तमान में जर्मनी, जापान, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों में हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। जर्मनी में ट्रेन का औसत किराया 7 से 10 रुपये प्रति किलोमीटर है, जबकि जापान के योकोहामा-कावासाकी मार्ग पर 10 से 15 रुपये प्रति किलोमीटर तक बैठता है। वहीं, इंग्लैंड में शुरू होने वाली प्रस्तावित हाइड्रोजन ट्रेन का अनुमानित किराया 12 से 15 रुपये प्रति किलोमीटर के बीच रहने की उम्मीद है। शून्य कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण अनुकूल होने के कारण इन ट्रेनों को काफी पसंद किया जा रहा है। भारतीय रेलवे की योजना हाइड्रोजन हेरिटेज पहल के तहत देश के हेरिटेज और हिल रूट्स पर ऐसी 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की है। इस परियोजना में प्रति ट्रेन लगभग 80 करोड़ रुपये और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 70 करोड़ की लागत आने का अनुमान है।

अमृत भारत स्टेशन योजना को नई रफ्तार

भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत देश के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया। मध्य प्रदेश में विदिशा, सांची, अशोकनगर, शिवपुरी, ब्यौहारी, भिंड, हरपालपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, जुन्नारदेव, बालाघाट, छिंदवाड़ा और नैनपुर स्टेशन इस योजना के तहत तैयार किए गए हैं।

यात्रियों को होंगे ये बड़े फायदे

- टिकट, प्रतीक्षालय और प्लेटफॉर्म तक पहुंच पहले से आसान होगी।
- दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
- डिजिटल सूचना प्रणाली से ट्रेनों की जानकारी तुरंत मिलेगी।
- स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में यात्रा का अनुभव बेहतर होगा।
- पार्किंग और स्टेशन परिसर के सुव्यवस्थित होने से जाम की समस्या कम होगी।
- स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार और व्यापार बढ़ेगा।
- पर्यटन स्थलों तक पहुंचने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।

मानसून सत्र में 7 बिल लाएगी सरकार

वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदे पर सख्ती की तैयारी

नई दिल्ली। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने एजेंडा तय कर लिया है। लोकसभा में 7 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदा कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं। बिलों की अस्थायी सूची में अभी किसी भी संविधान संशोधन बिल जैसे परिसीमन या नारी संशोधन का जिक्र नहीं है।

13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दल नीट-यूजी पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, ई20 ईंधन और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। सात में से दो विधेयक फॉरेन कंट्रीब्यूशन और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान पुराने हैं। विदेशी चंदे से जुड़ा विधेयक 25 मार्च 2026 को और शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। शिक्षा से जुड़े बिल को जॉइंट कमेटी के पास भेज दिया गया था। इनकम टैक्स बिल, 2026 और सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाने वाले बिल अध्यादेशों का स्थान लेंगे। जबकि जन्म-मृत्यु, वंदे मातरम के अपमान और एमएसएमई से जुड़े तीन बिल पहली बार पेश किए जाएंगे।

मानसून सत्र से पहले एनडीए की बैठक

मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों तक चलने वाले मानसून सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। दिल्ली के कर्तव्य भवन में शुक्रवार को एनडीए नेताओं की बैठक हो रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और ललन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। इसमें सरकार के एजेंडे और सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी।

एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं

नई दिल्ली। नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग का अधिकार केवल वोटर लिस्ट के नियंत्रण और देश में चुनाव कराने तक ही है। ये टिप्पणी देश के शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने की है। पश्चिम बंगाल एसआईआर विवाद पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार केवल मतदाता सूची के नियंत्रण और पर्यवेक्षण तक सीमित है। इसलिए कानून की स्थिति में कोई भ्रम नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

दरअसल चुनाव आयोग देश में इस वक्त वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन करवा रहा है। स्पेशल रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के बाद लोगों ने नागरिकता को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। 17 जुलाई को सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से नागरिकता अपने आप खत्म नहीं हो जाती। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने दलील दी। अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि नागरिकता तय करना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक अधिकार नहीं है। आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची के नियंत्रण और पर्यवेक्षण तक सीमित है, इसलिए कानून की स्थिति में कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि 19 अपीलीय ट्रिब्यूनलों के काम करने के तरीके से व्यावहारिक स्तर पर असंगतियां और देरी पैदा हो रही है। वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनलों के कामकाज में बाधाएं हैं और इससे मामलों के निस्तारण पर असर पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला नजीर साबित होगा

नो बॉडी, नो मर्डर दलील खारिज, लाश न मिलने पर भी होगी हत्या की सजा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में साफ किया है कि किसी हत्या के मामले में यदि पीड़ित की लाश बरामद नहीं होती है, तब भी आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने इस पुरानी धारणा को खारिज किया है कि लाश नहीं.....मर्डर नहीं, यह कहते हुए कि कानून के तहत अपराध का साबित होना आवश्यक है, न कि लाश का पेश होना। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर लाश की बरामदगी को सजा के लिए अनिवार्य शर्त बनाया गया, तब इसतरह के हत्यारे बच जाएंगे, जो साक्ष्य मिटाने में सफल हो जाते हैं।

यह ऐतिहासिक फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने असम के एक व्यक्ति की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखकर सुनाया। उस व्यक्ति को 10 साल की एक गोद ली हुई बच्ची की हत्या का दोषी ठहराया गया था, जिसका शव नदी में फेंका गया था और वह कभी नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक जैसे फैसलों को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शव न मिलने के बावजूद, अभियोजन पक्ष ने विश्वसनीय सबूतों के जरिए अपराध को सफलतापूर्वक साबित किया था।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में साफ किया कि कॉर्पस डेलिक्टी का मतलब यह है कि अपराध हुआ है, न कि यह कि मारे गए व्यक्ति का शव बरामद हो गया है। यह फैसला देबोजित पंकीका की अपील पर आया, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत अपनी सजा को चुनौती दी थी।

यह मामला एक मासूम बच्ची की हत्या से जुड़ा था, जो अपीलकर्ता और उसकी मां के साथ रहती थी। मां के इलाज के लिए घर से बाहर जाने के बाद बच्ची पूरी तरह अपीलकर्ता की देखरेख में थी और तभी वह गायब हो गई। बाद में हुई जांच में शव बरामद नहीं हुआ। गवाहों के बयानों और अन्य अहम सबूतों के आधार पर शीर्ष अदालत ने बचाव पक्ष की दलील को खारिज किया कि शव न मिलने से अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि हत्या के मामले में कॉर्पस डेलिक्टी सिद्धांत के दो पहलू होते हैं- मौत का सबूत और इस बात का सबूत कि मौत किसी दूसरे व्यक्ति के आपराधिक कृत्य के कारण हुई। इनमें से एक पहलू को सीधे तौर पर और दूसरे को परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर स्थापित किया जा सकता है।

एसआईटी ने अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए मांगा अतिरिक्त समय

लखनऊ। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम अंतरिम रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी. एसआईटी ने अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त समय मांगा है. सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करेगी. यह मामला मंदिर को मिले चढ़ावा और दान की चोरी से जुड़ा हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद मामले की आगे की दिशा स्पष्ट हो सकेगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस मामले में दोषी पाए गए लोग किसी भी हालत में नहीं छोड़े जाएंगे. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अभी अपनी जांच पूरी नहीं की है. अब तक की जानकारी के अनुसार जांच में चढ़ावे की गिनती, प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं. इसमें एसओपी का उल्लंघन और सीसीटीवी फुटेज की कमी शामिल है. इसके आधार पर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा समेत कुछ बैंक कर्मी भी शामिल हैं।

भाजपा नेता अशोक चांडक के ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई

श्रीगंगानगर। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेता और शराब कारोबारी अशोक चांडक के श्रीगंगानगर और जयपुर स्थित ठिकानों पर शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। सुबह 5 बजे से शुरू हुई कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामले में बताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

चांडक का राजनीतिक प्रभाव भी रहा है। उन्होंने साल 2018 में कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उनके परिवार का राजनीति में दखल रहा है, उनकी पत्नी और भाई भी श्रीगंगानगर नगर परिषद के चेयरमैन पद पर रह चुके हैं।

सूत्रों के अनुसार, ईडी की कई टीमों ने एक साथ चांडक के घर, ऑफिस और उनसे संबंधित अन्य ठिकानों पर दबिश दी। श्रीगंगानगर में शिवा वाइन, चंद्रकला चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालयों सहित उनके निकुंज विहार और जवाहर नगर स्थित रिश्तेदारों के घरों पर भी जांच की जा रही है। जयपुर में वैशाली नगर स्थित उनके रिश्तेदारों के यहां भी ईडी ने कारोबार से जुड़े दस्तावेजों की छानबीन की।

यह कार्रवाई तब हुई है जब चांडक परिवार हाल ही में चर्चा में आया था। उन्होंने गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के खिलाफ 30 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि फिरौती न देने पर उनके बिजनेस पार्टनर आशीष गुप्ता पर फायरिंग की गई और परिवार को जान से मारने की धमकी मिली थी।

नीट विवाद : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हुई तेज

नई दिल्ली। नीट प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्रों के देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को शिक्षा मंत्री को हटाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इसका श्रेय उन लाखों छात्रों को मिलना चाहिए जिन्होंने अपने और देश के भविष्य के लिए आवाज उठाई है। शिवसेना यूबीटी नेता चतुर्वेदी ने चेतावनी दी कि जवाबदेही से बचना और असंतोष को बढ़ने देना सरकार के हित में नहीं होगा।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 6 से शुरू हुए और 20 जून से अनिश्चितकालीन धरने में बदले आंदोलन में अब कई प्रमुख हस्तियां और राजनीतिक दल भी शामिल हुए हैं। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक छात्रों की मांगों के समर्थन में बीते 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, जिससे आंदोलन को और अधिक बल मिला है। गुरुवार को विपक्ष के कई बड़े नेता वांगचुक का हाल जानने और उन्हें समर्थन देने जंतर-मंतर पहुंचे।

इस कड़ी में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग कर कहा कि वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी केंद्र से वांगचुक और प्रदर्शनकारी समूहों के साथ बातचीत कर उनकी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी छात्रों को समर्थन देकर कहा कि युवाओं को तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि वे ही देश की ताकत हैं।

सोनम वांगचुक का जंतर-मंतर से भावुक संदेश

संसद मार्च सफल नहीं हुआ तो भूत बनकर लौटूंगा

नई दिल्ली। शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को कहा कि वह 20 जुलाई तक अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे ताकि उसी दिन प्रस्तावित संसद चलो मार्च में खुद शामिल होकर उसका नेतृत्व कर सकें। उन्होंने समर्थकों के बीच हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि अगर 20 जुलाई की यह मार्च उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुआ तो वह भूत बनकर लौटेंगे। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वांगचुक ने कहा कि मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, ताकि आप सभी के साथ संसद तक मार्च कर सकूं। अगर यह मार्च सफल नहीं हुआ, तो मैं भूत बनकर वापस आऊंगा।

उनके इस बयान पर वहां मौजूद लोगों ने तालियों और नारों के साथ प्रतिक्रिया दी। वांगचुक पिछले 20 दिनों से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के विरोध में आमरण अनशन पर हैं। दूसरी ओर, कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर चल रहा प्रदर्शन भी अब 28वें दिन में पहुंच गया है। आंदोलन का अगला बड़ा पड़ाव 20 जुलाई को होने वाली संसद चलो मार्च है, जो संसद के मानसून सत्र के पहले दिन निकाली जाएगी।

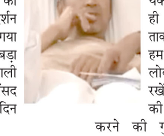

वांगचुक की लोगों से 20 जुलाई को आने की अपील

लगातार कमजोर होती सेहत के बावजूद सोनम वांगचुक ने समर्थकों से कहा कि अब समय सिर्फ उनके लिए चिंता जताने का नहीं, बल्कि आंदोलन को मजबूत करने का है। उन्होंने कहा कि मैं बाहर से भले ही कमजोर दिख रहा हूं, लेकिन अंदर से पूरी तरह मजबूत हूं। मुझे यकीन है कि आप सब भी उतने ही मजबूत हैं। अब हमें यही ताकत 20 जुलाई को दिखानी है। हम शांतिपूर्वक संसद जाएंगे और लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात रखेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उनसे अनशन खत्म करने की गुजारिश करने के बजाय संसद मार्च में शामिल हों। उनका कहना है कि किसी ठोस सरकारी जवाब के बिना अनशन तोडना इस आंदोलन के उद्देश्य को कमजोर कर देगा।

वांगचुक के अनशन ने आंदोलन को दी नई पहचान

उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर रोजाना नजर रखी जाए और जरूरत पडने पर तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। शुरुआत में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन छात्रों का एक व्यंग्यात्मक विरोध प्रदर्शन माना जा रहा था, लेकिन सोनम वांगचुक के आमरण अनशन ने इसे एक बड़े जनआंदोलन का रूप दे दिया। उनके अनशन के बाद विपक्षी नेताओं, लेखकों, कलाकारों और नागरिक समाज के कई लोग जंतर-मंतर पहुंचने लगे और आंदोलन को व्यापक समर्थन मिलने लगा।

जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल के 5 और संदिग्ध पकड़े

पाटन। गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को पाटन जिले के सिद्धपुर तालुका के खाडियाल गांव से पकड़ा गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिलाल आबिदभाई शेरा, मोहम्मद अयूब कादीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खाली अयूब सुनसारा, शफिया रईस मुख्ती और मोहम्मद हसन कार्डिया के रूप में हुई है। इन्हें मेहसाणा जिले के कढ़ी कस्बे में न्यायिक मजिस्ट्रेट आरएम भाटिया के सामने पेश किया गया, जहां से इन्हें 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले 3 जुलाई को जैश से जुड़े 8 संदिग्धों को पकड़ा गया था। इनसे पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की गई और इन पांचों को पकड़ा।

पकड़े गए आतंकी बम बनाने की कोशिश में थे

सरकारी वकील पीआर दंतनी ने बताया कि एटीएस ने कोर्ट को जानकारी दी कि आरोपियों में से एक ने टाइम बम बनाने की कोशिश की थी। हालांकि, उनका यह प्रयोग असफल रहा। पुलिस को अभी बम बनाने का सामान और उर्दू में लिखी जैश-ए-मोहम्मद की लिटरेचर बरामद करनी है। दंतनी के अनुसार, एटीएस यह पता लगाना चाहती है कि बम बनाने का सामान कहां से लाया गया और उसे कहां छिपाया गया था। साथ ही, जिहादी किताबें कहां से मिलीं। उन्हें कहां रखा गया है।

नोटिस -नोटिस खेल रहे अधिकारी, नहीं हो रही सुनवाई

नोटिस पर 13 जुलाई को उपस्थित होने के बावजूद दर्ज कर दी गई अनुपस्थित

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। नगर के वार्ड नंबर 23 पावर हाउस परिसर में झुग्गी झोपड़ी व मकान बनाकर वर्षों से निवास करने वाले लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है।जहां नवीन तहसील कार्यालय व अन्य व्यवस्थाएं बनाने के लिए प्रशासन द्वारा झुग्गी-झोपडी को हटाने की प्रक्रिया के बीच वार्ड वासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है।जिसके विरोध में जगह-जगह आवेदन निवेदन ज्ञापन देने के बाद भी कहीं कोई सुनवाई न होने पर अपनी नाराजगी जताते हुए वार्ड वासियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में रह वासियों के लिए अलग से व्यवस्था बनाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर सकारात्मक हल निकालते हुए उनके आवास खाली कराए जाने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के निर्देशन पर तहसील कार्यालय से वार्ड नंबर 23 पावर हाउस के निवासियों को नोटिस जारी कर बैठक में सकारात्मक निर्णय लेने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन इस बैठक में कोई हल नहीं निकल रहा है।ऐसा आरोप लगाते हुए वार्ड वासियों ने पुन: अपनी नाराजगी का इजहार किया है। वार्ड वासियों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी बैठक के नाम पर

नोटिस नोटिस खेल रहे हैं लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। वार्ड वासियों ने बताया कि हाईकोर्ट के उक्त आदेश के अनुसार उन्हें नोटिस जारी कर 13 जुलाई को तहसील कार्यालय बुलाया गया था।उक्त नोटिस पर वार्ड वासी तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार के साथ बैठक भी की, लेकिन उस बैठक में कोई निर्णय नहीं निकला, वार्डवासियों का आरोप है कि 13 जुलाई की बैठक में वे तहसील कार्यालय में उपस्थित हुए थे, संबंधित विषय पर चर्चा भी हुई बावजूद उसके भी उनकी अनुपस्थिति नए नोटिस में दर्शायी गई है और पुन: उन्हें नोटिस जारी कर 17 जुलाई को बुलाया गया था, लेकिन 17 जुलाई को भी इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं निकला है। वार्डवासियों ने बताया कि वे अपने कब्जे छोड़ने तैयार है, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था प्रशासन ने अब तक नहीं की है, वार्ड वासियों की मांग है कि या तो उन्हें बूढ़ी में बनाए गए प्रधानमंत्री आवास निःशुल्क प्रदान किए जाएं या फिर भूखंड आवंटित कर दिया जाए जिसमें वह अपने मकान या झोपड़ी बनाकर उसमें निवास कर सके।

महीने के 5 हजार रु कमाते हैं, 10, हजार रु महीना कहां से देंगे- वाजिश तिवारी

पावर हाउस कॉलोनी निवासी वाजिश तिवारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के तहत हमें 13 जुलाई को पेशी में बुलाया गया था,हमे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बूढ़ी में मकान देने की तहसीलदार मैडम ने बात कही थी, लेकिन उस मकान के लिए हमसे 2 लाख रु जमा करने कहे जा रहे हैं।बैठक में उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई हमने कहा कि पैसे नहीं है, कहीं खाली जमीन ही दे दो तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मकान के लिए अगर हमारे पास 2 लाख रु होते, तो हम झोपड़ी में क्यों रहते। फिर उन्होंने विकल्प दिया कि पहले 20 हजार रु जमा करके मकान बुक कर लो और फिर 10, हजार रु महीना देते रहना, लेकिन हम 5 हजार रु महीना कमाते हैं तो आगामी 20 महीनों तक हम 10, हजार रु महीना इन्हें कहां से देंगे। हमारी मांग है कि हमें निःशुल्क आवास दिया जाए।

प्रशासन चाहे तो हमारी संपत्ति की जांच करा सकती है- संतोष मालवीय

वार्डवासी संतोष मालवीय ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देशन पर 13 जुलाई को हमारी पेशी रखी गई थी हम 13 जुलाई को आए थे, तहसीलदार मैडम ने हमारी एक नहीं सुनी, सिर्फ अपनी सुनाती रही और बोली की दस्त ?त कर दो, लेकिन जब हमारी सुनवाई ही नहीं हुई तो हम दस्तक कैसे करते, इसीलिए हम वापस आ गए। अब दूसरा नोटिस जारी कर हमें बुलाया गया है पूछा गया है कि 13 जुलाई की बैठक में क्यों अनुपस्थित रहे, जबकि हम 13 जुलाई की बैठक में आए थे।हमारी मांग है कि हमें निःशुल्क जमीन दे या फिर बूढ़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना का निःशुल्क लाभ दिया जाए. हम पैसे वाले नहीं है हम इतना पैसा नहीं दे सकते। चाहे तो प्रशासन हमारी संपत्ति की जांच करा सकती हैं।

करोड़ों की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरनापुर में बारिश के पानी की निकासी के नहीं हैं प्रबंध

पद्मेश न्यूज। किरनापुर। करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) किरनापुर में मूलभूत सुविधाओं की कमी अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। बरसात के मौसम में अस्पताल परिसर और मुख्य प्रवेश द्वार के सामने जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी जमा होकर तालाब जैसा दृश्य प्रस्तुत करता है।

वही अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और उनके परिजनों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इससे न केवल आवागमन में कठिनाई होती है, बल्कि फिसलने और दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है। दोपहिया एवं चारपहिया वाहन चालकों को भी अस्पताल तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध मे स्थानीय नागरिकों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च कर आधुनिक भवन तो बना दिया गया, लेकिन बारिश के पानी की निकासी के लिए प्रभावी नाली व्यवस्था नहीं की गई। परिणामस्वरूप हर वर्ष बरसात के दौरान अस्पताल के सामने पानी भर जाता है और मरीजों को भारी असुविधा झेलनी पड़ती है।क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से मांग की है कि अस्पताल परिसर में जल निकासी की स्थायी व्यवस्था शीघ्र कराई जाए, ताकि मरीजों और आमजन को होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके। तथा लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवा से जुड़े संस्थान में इस प्रकार की लापरवाही उचित नहीं है और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी जल निकासी व्यवस्था कराने की मांग की है।

उकवा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता अभियान-साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और नशामुक्ति का दिया संदेश

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। प्रदेशभर में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान 2.0 के तहत थाना रुपझर पुलिस द्वारा उकवा स्थित शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को साइबर फ्रॉड, महिला संबंधी अपराधों, नशे के दुष्प्रभावों तथा कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को जागरूक बनाकर उन्हें अपने परिवार और समाज तक सुरक्षा एवं नशामुक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम के दौरान थाना रुपझर पुलिस कामेश धुमकेती ने छात्राओं को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी और बैंक संबंधी धोखाधड़ी सहित विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों से बचाव के उपाय विस्तार से बताए। साथ ही महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों तथा किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न या अपराध की स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने की जानकारी दी गई। छात्राओं को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभावों से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ-साथ पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने परिजनों, मित्रों तथा आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें।जागरूकता कार्यक्रम के अंत में सभी छात्राओं एवं विद्यालय के शिक्षकों और स्टाफ को नशामुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाई गई। सभी ने स्वयं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने तथा दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया।इस अवसर पर विद्यालय परिसर से एक विशाल जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली में छात्राओं ने नशामुक्ति, महिला सुरक्षा और साइबर जागरूकता से संबंधित संदेश लिखी तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया। रैली के माध्यम से विद्यार्थियों ने समाज को नशामुक्त बनाने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया।कार्यक्रम में थाना रुपझर पुलिस स्टाफ, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम भविष्य में भी लगातार आयोजित किए जाएंगे, ताकि युवाओं में कानून के प्रति जागरूकता बढ़े और समाज को अपराध एवं नशे से मुक्त बनाया जा सके।

जल जंगल जमीन सब हमारे, और हमे ही किया जा रहा बेदखल ?

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। पिछले कई दशकों से वन भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे लोगो को जहा एक ओर शासन द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे आवंटित किए जाने का दावा किया जा रहा है।तो वही दूसरी ओर शासन के इस दावे की हकीकत कुछ और ही है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले अब भी ऐसे कई लोग हैं।जो कई वर्षों से वन भूमि पर कब्जा कर उसमें खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी उन्हें शासन द्वारा पट्टे आवंटित नहीं किए गए हैं जिसके चलते वे लोग पिछले कई वर्षों से कृषि भूमि का पट्टा प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके भी उन्हें अब तक कब्जे वाली भूमि का शासन द्वारा पट्टा आवंटित नहीं किया गया है वहीं उन्हें आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे पिछली कई पीढ़ियों से वन विभाग की भूमि पर कृषि करते आ रहे

हैं, अब वनकर्मी उन्हें उक्त भूमि से बेदखल कर रहे हैं, तो वही उनकी फसलों को नष्ट करने की बात कही जा रही है।जिसपर उन्होंने अपना एतराज जताते हुए जल्द से जल्द उक्त कृषि भूमि के पट्टे प्रदान किए जाने की मांग की है। तो वहीं उन्होंने मांग पूरी न होने पर समस्त ग्रामीण के साथ आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है।

तो ग्राम वासियों के साथ आंदोलन किया जाएगा- बृजलाल उइके

ग्रामीण बृजलाल उईके ने बताया कि हमारे गांव में बैगा आदिवासी शासन की भूमि पर पिछली कई पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अब वन विभाग वाले हमें उक्त भूमि से बेदखल कर रहे हैं। जबकि हमने वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे की कई बार मांग की है। लेकिन आज तक पट्टा जारी नहीं किया गया है। पिछली 3 पीढ़ियों से 100 से अधिक ग्रामीण उक्त भूमि पर खेती कर रहे हैं पूर्व में भी हमने आवेदन दिया था लेकिन वह आवेदन कहां गया इसकी आज तक कोई जानकारी नहीं मिली। हमारी मांग है कि हमें उक्त भूमि से बेदखल ना किया जाए ,वन अधिकार अधिनियम के तहत हमें पट्टे प्रदान किए जाए ,अभी खरीब का सीजन आ गया है हम धान लगाने जाते हैं तो वन विभाग वाले फसलों को नष्ट करने की बात कहते हैं, हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसीलिए आज हम कलेक्टर कार्यालय आए हैं। हमारी मांग है कि हमें जल्द से जल्द उक्त कृषि भूमि के पट्टे आवंटित किया जाए। यदि मांग पूरी नहीं होती तो समस्त ग्रामीण के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा।

राजनीतिक रंग ले रहा नैतरा का निर्माणाधीन सामुदायिक भवन

सरपंच संतोष लिल्हारे का पलटवार—विकास रोकने की साजिश बर्दाश्त नहीं

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम नैतरा में लगभग 45 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक भवन को लेकर की गई शिकायत अब राजनीतिक रंग लेती दिखाई दे रही है। भवन निर्माण स्थल को लेकर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बरसात के समय यहां पानी भर जाता है, इसलिए यह स्थान उपयुक्त नहीं है। वहीं ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए इसे विकास कार्यों को बाधित करने की राजनीतिक कोशिश करार दिया है।ग्राम पंचायत नैतरा के सरपंच संतोष लिल्हारे ने कहा कि सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए गांव में कई स्थानों पर विचार किया गया, लेकिन पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान स्थल का चयन सभी पंचों की सर्वसम्मति से किया गया। उन्होंने कहा कि भवन बनने के बाद गांव के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को शादी-विवाह, सामाजिक कार्यक्रमों और अन्य सामुदायिक आयोजनों के लिए स्थायी सुविधा उपलब्ध होगी।जिस स्थान को जलभराव वाला बताया जा रहा है, उसके आसपास लोग पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहे हैं और आज तक कभी भी उनके घरों में बारिश का पानी नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि हाल की बारिश में गांव की पुलिया में नालों और शहरी नाले से आया कचरा फंस जाने के कारण पानी की निकासी रुक गई थी। इसी वजह से पानी वापस लौटा और निर्माणाधीन भवन के समीप तक पहुंचा, लेकिन सामुदायिक भवन जलमग्न नहीं हुआ।

जानबूझकर बनाया जा रहा राजनीतिक मुद्दा

पिछले दिनों की गई शिकायत का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि इस अस्थायी स्थिति को जानबूझकर राजनीतिक मुद्दा बनाया गया और शिकायत कर विकास कार्य को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यदि पुलिया से समय पर कचरा हट जाता तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती।उधर गांव के कई ग्रामीणों ने भी पंचायत का समर्थन करते हुए कहा कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं और कभी इस क्षेत्र में जलभराव की समस्या नहीं रही। उनका कहना है कि पुलिया में कचरा फंसने के कारण पानी की निकासी प्रभावित हुई थी, जिसे आधार बनाकर सामुदायिक भवन के निर्माण का विरोध करना उचित नहीं है।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं कलेक्टर से मांग की है कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए तथा 45 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का कार्य बिना किसी अनावश्यक बाधा के शीघ्र पूरा कराया जाए, ताकि गांव के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

जिला शिक्षा अधिकारी ने डाइट बालाघाट में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का किया निरीक्षण

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती धनश्री जैन ने शुक्रवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) बालाघाट पहुंचकर जनशिक्षकों के लिए आयोजित पांच दिवसीय अकादमिक एवं मॉनिटरिंग आधारित क्षमतावर्धन प्रशिक्षण तथा ईसीसीई आधारित नर्सरी, केजी-1 एवं केजी-2 कक्षाओं में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का अवलोकन किया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों से संवाद कर प्रशिक्षण की उपयोगिता पर चर्चा की तथा प्रभावी शिक्षण के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान श्रीमती जैन ने डाइट के प्राचार्य एवं अकादमिक स्टाफ के साथ नवीन शैक्षणिक सत्र में संचालित की जाने वाली गतिविधियों, शिक्षण की गुणवत्ता और अकादमिक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने तथा विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर सहायक संचालक मोहित डहेरिया, डाइट प्राचार्य श्री एन.पी. मलगाम, जिला परियोजना समन्वयक श्री घनश्याम बर्मन, प्रशिक्षण प्रभारी श्री के.डी. तितिरमारे, अकादमिक स्टाफ, मास्टर ट्रेनर्स तथा बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी शिक्षक उपस्थित रहे।

आवश्यकता है
ओ.टी. असिस्टेंट - 02 पद
नर्स - 02 पद
सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर आवें। समय - शाम 6 बजे
पता- सेठिया ऑई केयर एंड पैथोलाजी, हनुमान चौक, बालाघाट
मो.-9109902783

8 दिनों बाद,जिले में हुई बारिश, हेवी रेन का अलर्ट

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। पिछले 8 दिनों बाद बारिश ने बालाघाट को राहत दी है, जहा बीती शाम से बारिश का दौर रूक-रूककर जारी है,आपको बताए कि बारिश नहीं होने से जहां मौसम में उमस बढ़ने से लोग परेशान हो रहे थे, वहीं खेतो में लगे फसल धान के रोपा और फसल सूखने की कागार पर पहुंच गई थी। गुरूवार की रात से हो रही बारिश ने उमस के साथ-साथ किसानों को भी राहत दी है। जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र के मौसम इकाई वैज्ञानिक धर्मेन्द्र अगासे ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चक्रीय निम्न दबाव के कारण, मानसुन सक्रिय हुआ है और यह आगामी दिनो में भी जारी रहेगा।उधर जिले में मानसुन माह जून और जुलाई में बारिश के कमजोर होने से बालाघाट जिला, अब भी बारिश के मामले में पिछड़ा है। 1 जून से 17 जुलाई तब बालाघाट में 331 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

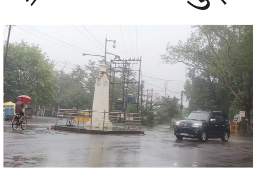

जबकि बीते साल, अब तक 614 मिलीमीटर बारिश हो गई थी।

पुनः शुरू हुआ कृषि कार्य

बारिश ना होने से सबसे ज्यादा किसान परेशान थे, बीते दिनों बारिश होते देख शुरू किया गया कृषि कार्य बारिश ना होने के चलते कई जगह रुक गया था।जो बीती रात से हुई बारिश के बाद पुनः शुरू हो गया है।वही जिनके पास सिंचाई के साधन (कुआ मोटर पंप) नही है उन किसानों का कृषि कार्य अब तक शुरू नही हो पाया है।जिससे किसान परेशान है।

जिले की औसत वर्षा रिकार्ड में

वारासिवनी तहसील में सबसे अधिक 453 मिलीमीटर और खैरलांजी तहसील में सबसे कम 169 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई है।कार्यालय अधीक्षक भू-अभिलेख के अनुसार बीतमे 24 घंटों के दौरान बालाघाट तहसील में 19 मिमी, वारासिवनी में 16 मिमी, बैहर में 04 मिमी, लांजी में 14 मिमी, कटंगी में 17 मिमी, किरनापुर में 12 मिमी, खैरलांजी में 13 मिमी, लालबर्रा में 07 मिमी, बिरसा में 06 मिमी, परसवाड़ा में 01 मिमी एवं तिरोड़ी तहसील में 16 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई है।

जिले में तहसीलवार बारिश का आंकड़ा

01 जून से 17 जुलाई तक बालाघाट तहसील में 440 मिलीमीटर, बैहर में 424 मिलीमीटर, लांजी में 319 मिलीमीटर, कटंगी में 272 मिलीमीटर, किरनापुर में 450 मिलीमीटर, लालबर्रा में 299 मिलीमीटर, बिरसा में 206 मिलीमीटर, परसवाड़ा में 279 मिलीमीटर एवं तिरोड़ी में 331 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

2025 में जिले में हुई बारिश का आंकड़ा

बीते वर्ष 2025 में इसी अवधि के दौरान बालाघाट तहसील में 790 मिलीमीटर, वारासिवनी में 970 मिलीमीटर, बैहर में 760 मिलीमीटर, लांजी में 318 मिलीमीटर, कटंगी में 624 मिलीमीटर, किरनापुर में 562 मिलीमीटर, खैरलांजी में 273 मिलीमीटर, लालबर्रा में 719 मिलीमीटर, बिरसा में 436 मिलीमीटर, परसवाड़ा में 711 मिलीमीटर तथा तिरोड़ी में 584 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी।

बारबेड वायर (कांटेदार तार) एवं चेन लिंक जाली उचित दाम पर उपलब्ध
लघु उद्योग निगम भोपाल से संबद्ध
निर्माता
तिरूपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टॉकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फोन:- 07632-243531
मो:- 8989976858, 9425139998

न्यूज गैलरी

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर सख्त, ब्लैक स्पॉट पर स्ट्रीट लाइट लगाने के दिए निर्देश

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट

सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे, यातायात थाना प्रभारी सुश्री यीना रहांगडाले, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारी सहित जिला सड़क सुरक्षा समिति के अन्य सदस्य और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्राथमिकता के आधार पर लगेंगे स्ट्रीट लाइट

बैठक के दौरान कलेक्टर श्री मीना ने जिले के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, जिन्हें ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन ब्लैक स्पॉट पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का अभाव है, वहां प्राथमिकता के आधार पर तत्काल स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। कलेक्टर ने कहा कि रात्रि के समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर बेहतर रोशनी होना अत्यंत आवश्यक है।

समन्वय के साथ करें कार्य

कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा को सभी संबंधित विभागों की साझा जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी निर्माणाधीन और सुधारात्मक कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए।

नपा डीजल घोटाले की जांच अंतिम चरण में, 30 जुलाई तक आ सकता है फैसला

शिकायतकर्ताओं ने दी डबल बेंच जाने की चेतावनी, शिकायतकर्ता और नगर पालिका अध्यक्ष दोनों के बयान पूरे, आरटीआई दस्तावेजों की जांच भी समाप्त

पद्मेश न्यूज।बालाघाट।नगर पालिका बालाघाट में बहुचर्चित डीजल खर्च और कथित प्रशासनिक अनियमितताओं के मामले की जांच अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। शिकायतकर्ताओं और नगर पालिका अध्यक्ष दोनों के बयान दर्ज होने के बाद जांच प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार राज्य शासन द्वारा गठित जांच समिति इस पूरे मामले में 30 जुलाई तक अपना निर्णय दे सकती है। इस बीच शिकायतकर्ताओं ने भी साफ कर दिया है कि यदि जांच रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं हुई या उन्हें एकपक्षीय निर्णय महसूस हुआ तो वे मामले को डबल बेंच में चुनौती देंगे।

दरअसल, नगर पालिका में डीजल खर्च सहित अन्य वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर भाजपा के ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन ने जांच समिति गठित कर लगभग 90 दिनों में जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे। अब निर्धारित अवधि समाप्त होने के करीब है और जांच अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 जुलाई को भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता केवल सोनेकर, पार्षद सुधीर चिले, पार्षद प्रतिनिधि सौरभ जैन सहित अन्य शिकायतकर्ता जबलपुर स्थित नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय पहुंचे। वहां सभी ने जांच अधिकारियों के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए। शिकायतकर्ताओं ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों के साथ अन्य अभिलेख भी जांच समिति को सौंपे। बताया जा रहा है कि उन्होंने केवल डीजल खर्च से संबंधित जानकारी ही नहीं, बल्कि नगर पालिका के अन्य वित्तीय और प्रशासनिक मामलों से जुड़े दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, जिन्हें जांच टीम ने रिकॉर्ड में शामिल किया। पूर्व में शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के लिए नगर पालिका बालाघाट के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सूर्यप्रकाश उके, वाचस्पति त्रिपाठी तथा सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी बी.डी. कतरोलिया भी जबलपुर पहुंचे। जांच अधिकारियों ने उनके समक्ष उपलब्ध अभिलेखों का मिलान किया और प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन कराया। इससे जांच प्रक्रिया को महत्वपूर्ण आधार मिलने की बात कही जा रही है। वहीं, जांच के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजी ठाकुर का बयान पहले 2 जुलाई को होना था, लेकिन निजी कारणों से वे उस दिन उपस्थित नहीं हो सकीं। इसके बाद 16 जुलाई को उन्होंने जबलपुर पहुंचकर जांच समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा। उनके साथ प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सूर्यप्रकाश उके तथा नगर पालिका के यशवंत राणा भी मौजूद रहे। जांच अधिकारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष से विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। अब शिकायतकर्ता और नगर पालिका अध्यक्ष दोनों पक्षों के बयान पूरे हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार जांच समिति सभी दस्तावेजों, बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण कर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि 30 जुलाई तक जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी या निर्णय सार्वजनिक किया जा सकता है।

न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे - केवल सोनेकर

इधर, शिकायतकर्ता केवल सोनेकर ने स्पष्ट कहा है कि यदि जांच निष्पक्ष नहीं हुई या रिपोर्ट एकपक्षीय प्रतीत हुई तो वे कानूनी विकल्प अपनाते हुए मामले को डबल बेंच में ले जाएंगे। उनका कहना है कि उन्होंने पर्याप्त दस्तावेज और साक्ष्य जांच समिति को सौंपे हैं, इसलिए उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद है। यदि शिकायतकर्ताओं की बातों को नजरअंदाज किया गया तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। गौरतलब है कि यह मामला इसलिए भी बेहद चर्चित बना हुआ है क्योंकि शिकायतकर्ता और जिन पर आरोप लगाए गए हैं, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक ओर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरोपों के केंद्र में नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत ठाकुर हैं। ऐसे में यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब नगर पालिका, राजनीतिक गलियारों और आम लोगों की नजर 30 जुलाई पर टिकी हुई है। देखना होगा कि जांच समिति की रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं, आरोप सही साबित होते हैं या नहीं, और यदि निर्णय किसी एक पक्ष के खिलाफ जाता है तो शिकायतकर्ता अथवा दूसरा पक्ष आगे कौन-सी कानूनी रणनीति अपनाता है। फिलहाल पूरे जिले में इस बहुचर्चित जांच के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है।

कलेक्टर ने की नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कार्यों की समीक्षा

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। कलेक्टर मृणाल मीना ने शुक्रवार 17 जुलाई को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नगरीय निकायों से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त कलेक्टर राहुल नायक, जिले की सभी तहसीलों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

जल संरक्षण कार्यों में लाएं गति

कलेक्टर श्री मीना ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाबों के संरक्षण, गहरीकरण एवं पुनर्जीवन कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी कार्यों में तेजी लायी जाए और तय समय-सीमा के भीतर उन्हें पूर्ण किया जाए, ताकि जल संरक्षण के उद्देश्य को प्रभावी रूप से साकार किया जा सके।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवारा पशुओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश

बैठक में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन अधिनियम-2026 के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने आवारा मवेशियों एवं घूमंतु श्वानों के प्रभावी प्रबंधन के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार कर उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

स्मार्ट फिश पार्लर और गीता भवन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

कलेक्टर ने स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण एवं अन्य प्रक्रियाओं में तेजी लाकर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं गीता भवन की स्थापना की प्रगति की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में भूमि आवंटन होने के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उनमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही लंबित भूमि आवंटन के सभी मामलों का एक सप्ताह के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

जर्जर भवनों की पहचान कर करें आवश्यक कार्रवाई

बैठक में कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्रों में स्थित जर्जर एवं जोखिमपूर्ण भवनों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने, आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने तथा नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके।

राघवटोला आगजनी मामले में बढ़ती गिरफ्तारियों पर भड़का आदिवासी समाज, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। राघवटोला स्थित निर्माणाधीन माइक्रो इरिगेशन परियोजना प्लांट में 1 जुलाई को हुई करोड़ों रुपये की आगजनी के मामले में पुलिस की लगातार बढ़ रही कार्रवाई अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। पहले भाजपा नेता एवं जनपद पंचायत बालाघाट के निर्माण सभापति, ग्राम पंचायत के सरपंच सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब नौ और लोगों को जेल भेजे जाने से आदिवासी समाज में भारी नाराजगी देखने को मिली। शुक्रवार को गाँव से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और मध्यप्रदेश आदिवासी विकास परिषद युवा मोर्चा के बैनर तले पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा निर्दोष ग्रामीणों के विरुद्ध कार्रवाई रोकने की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान जिला मुख्यालय पहुंचे लोगों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आगजनी जैसी घटना निंदनीय है और जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई केवल वास्तविक दोषियों तक सीमित रहनी चाहिए। निर्दोष लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेजना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। मध्यप्रदेश आदिवासी विकास परिषद युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष शुभम उइके ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि एक जुलाई को हुई घटना के बाद पुलिस ने दो जुलाई को भाजपा नेता एवं जनपद पंचायत बालाघाट के निर्माण सभापति भुवनेश्वर रजक, ग्राम पंचायत परतापुर के सरपंच राजेश सिरसाम सहित अन्य लोगों को

गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। समाज को उम्मीद थी कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी और जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के कई दिन बाद अचानक आदिवासी समाज के नौ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि वे सभी अपने-अपने गांवों में रहकर खेती-किसानी का कार्य कर रहे थे। उनका कहना था कि ये लोग न तो फरार थे और न ही पुलिस से बचने का प्रयास कर रहे थे। इसके बावजूद पुलिस उन्हें खेतों से उठाकर ले गई और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। इससे पूरे आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है। शुभम उइके ने आरोप लगाया कि प्रारंभ में पुलिस ने केवल आठ-नौ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी थी, लेकिन अब इस मामले में करीब 32 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आ रही है। उनका कहना था कि पुलिस लगातार नए-नए लोगों के नाम जोड़ रही है। कुछ ग्रामीणों को सीधे खेतों से गिरफ्तार किया जा रहा है तो कुछ को फोन कर थाने बुलाया जा रहा है। इससे गांवों में भय का माहौल बन गया है और लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को यदि किसी व्यक्ति पर संदेह है तो पहले उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। केवल किसी के नाम आने मात्र से उसे आरोपी बनाकर जेल भेज देना न्यायोचित प्रक्रिया नहीं कही जा सकती। समाज चाहता है कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच हो और केवल उन्हीं लोगों पर कार्रवाई की जाए जिनके खिलाफ ठोस साक्ष्य मौजूद हों। प्रदर्शन के दौरान समाज के पदाधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग और उसके बेटे को भी आरोपी बनाया गया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वास्तव में पिता-पुत्र मिलकर करोड़ों रुपये की परियोजना में आगजनी जैसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उनका कहना था कि पुलिस को पूरे घटनाक्रम की वैज्ञानिक और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए तथा वास्तविक आरोपियों और निर्दोष लोगों के बीच स्पष्ट अंतर करना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल ग्राम पंचायत परतापुर के सरपंच राजेश सिरसाम की पत्नी सरोज सिरसाम भी मीडिया से चर्चा के दौरान भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि आगजनी की घटना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है और जो लोग दोषी हैं, उन्हें कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार पुलिस लगातार ग्रामीणों को गिरफ्तार कर रही है, उससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई ऐसे लोगों को भी इस मामले में शामिल किया जा रहा है, जिनका घटना से कोई लेना-देना नहीं है। सरोज सिरसाम ने कहा कि उनका परिवार कानून का सम्मान करता है और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखता है, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि निर्दोष लोगों को प्रताड़ित न किया जाए और यदि ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। प्रदर्शन के बाद आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा से मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराई जाए, निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई जाए तथा केवल वास्तविक दोषियों के विरुद्ध ही कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही समाज ने मांग की कि पुलिस जांच में पारदर्शिता बरते ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति का भविष्य प्रभावित न हो।

रेलवे स्टेशन लोकार्पण समारोह में गूंजीं रेल सुविधाओं की मांग, ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन

भोपाल-इंदौर के लिए सीधी ट्रेन, ट्रेनों की लेटलतीफी पर रोक और डबल रेल लाइन का काम शुरू करने की मांग, विधायक अनुभा मुंजारे भी रहीं मौजूद

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। बालाघाट रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह के दौरान जहां एक ओर विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ, वहीं दूसरी ओर वर्षों से लंबित रेल सुविधाओं को लेकर यात्रियों की आवाज भी बुलंद हुई। कार्यक्रम के दौरान ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति ने विधायक अनुभा मुंजारे के साथ बिलासपुर मंडल से आए रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जिले की रेल समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग उठाई। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा।

ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने बताया कि बालाघाट के यात्रियों को आज भी मूलभूत रेल सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गोंदिया-जबलपुर रेलखंड पर संचालित अधिकांश यात्री ट्रेनें नियमित रूप से विलंब से चल रही हैं। स्थिति यह है कि कई बार यात्री ट्रेनों को लंबे समय तक विभिन्न स्टेशनों पर रोककर पहले मालगाड़ियों को निकाला जाता है, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इससे नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, मरीजों और व्यापारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने ज्ञापन में मांग की कि गोंदिया-जबलपुर रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन समयबद्ध किया जाए तथा यात्री ट्रेनों को अनावश्यक रूप से रोकने की व्यवस्था समाप्त की जाए। उनका कहना था कि रेलवे को माल परिवहन के साथ-साथ यात्री सुविधाओं को भी समान प्राथमिकता देनी चाहिए। समिति ने बालाघाट से भोपाल और इंदौर के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया। पदाधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव काफी पहले रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल तथा व्यावसायिक शहर इंदौर के लिए सीधी ट्रेन नहीं होने से जिले के लोगों को कई बार ट्रेन बदलकर सफर करना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त हानि होती है। ज्ञापन में लंबे समय से घोषित बालाघाट-गोंदिया डबल रेल लाइन परियोजना का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। समिति ने कहा कि परियोजना की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन आज तक न तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो सकी है और न ही निर्माण कार्य शुरू करने के लिए किसी प्रकार की निविदा जारी की गई है। इससे लोगों में यह आशंका बढ़ रही है कि परियोजना केवल घोषणाओं तक सीमित होकर रह जाएगी। समिति ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों का मुद्दा भी रेलवे अधिकारियों के सामने रखा। ज्ञापन में कहा गया कि जिन किसानों की भूमि रेलवे परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई, उनके कई मामले आज भी लंबित हैं। साथ ही भूमि के बदले रोजगार देने की पूर्व व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। संघर्ष समिति ने मांग की कि प्रभावित किसानों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए तथा भूमि के बदले रोजगार की व्यवस्था को पुन: लागू किया जाए, ताकि किसानों के साथ न्याय हो सके। इस दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने भी समिति की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि बालाघाट लंबे समय से बेहतर रेल सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहा है। जिले के यात्रियों को समय पर ट्रेनें, नई रेल सेवाएं और अधूरी परियोजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से इन मांगों को गंभीरता से लेकर संबंधित उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आग्रह किया। ज्ञापन सौंपने के दौरान महेंद्र पचौरी, सूरज वादगुनेर, डॉ. अमर बिसेन, राजा नागपुरे, निखिल गौतम, अजय बिसेन सहित ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कुछ समय के लिए नारेबाजी भी हुई, जिसके बाद समिति ने शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपकर रेल सुविधाओं के शीघ्र विस्तार की मांग दोहराई। अब यात्रियों की नजर रेलवे प्रशासन पर टिकी है कि वर्षों से लंबित इन मांगों पर आखिर कब अमल होता है।

महिला थाना पुलिस की टीम ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जागपुर में दिलाई नशामुक्ति की शपथ

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान 2.0 के तहत महिला पुलिस थाना बालाघाट द्वारा शुक्रवार को ग्राम जागपुर स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए उन्हें नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था।कार्यक्रम के दौरान महिला थाने की पुलिस टीम ने विद्यालय के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणामों की विस्तार से जानकारी दी। विद्यार्थियों को बताया गया कि नशे की लत व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार और भविष्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालती है। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने तथा अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की गई।पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को यह भी समझाया कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार या सेवन में संलिप्त दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि

समाज को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके। विद्यार्थियों को साइबर माध्यमों और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले नशे के अवैध प्रचार-प्रसार से भी सतर्क रहने की सलाह दी गई।कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं विद्यालय स्टाफ को नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प दिलाया गया। सभी ने स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ ली।महिला थाना पुलिस ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान 2.0 के अंतर्गत जिले के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाकर स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण किया जा सके।

हजारों की पाइपलाइन के लिए खोदी लाखों की सड़क, ग्रामीण एवं राहगीर परेशान

नल-जल योजना की पाइपलाइन बिछाने के कार्य में अनियमितता का आरोप, बारिश में कीचड़ और गड्ढों से बढ़ रही दुर्घटनाएं, ग्रामीणों में आक्रोश

ग्रामीणों ने पाइपलाइन कार्य की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाने की मांग की

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। लालबर्रा।

नगर मुख्यालय से लगभग 10 किमी. दूर ग्राम पंचायत मोहगांव (ध.) में इन दिनों विकास के नाम पर विकास कार्य को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नल-जल योजना के तहत पंचायत क्षेत्र में नई पाइपलाइन बिछाने के कार्य में तकनीकी मापदंडों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। हजारों रूपये की पाइपलाइन डालने के लिए लाखों-करोड़ों की लागत से बनी पक्की सीसी सड़कों को बीच से ही जेसीबी मशीन से खोदकर बदहाल कर दिया गया है। साथ ही बारिश होने से सड़क में कीचड़ एवं मलबे व सड़क के बीच में गड्डा हो जाने से आवागमन करने वालों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएचई विभाग के ठेकेदार द्वारा पुरानी व खराब हो चुकी पाइपलाइन को बदलने का कार्य किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को पर्याप्त पानी मिल सके। योजना तो अ'छी है, लेकिन इसे अमलीजामा पहनाने का तरीका बेहद गैर-जिम्मेदाराना है। सड़क के बीचों-बीच और किनारों पर गहरी खुदाई कर पाइपलाइन तो डाल दी गई, लेकिन उसे वापस समतल नहीं किया गया। इस तरह से ठेकेदार द्वारा सड़कों की मरम्मत नहीं करवाई जा रही है जिससे ग्रामीणजनों एवं राहगीरों को आवागमन करने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बारिश ने बढ़ाई आफत, राहगीर हो रहे दुर्घटना का शिकार

वर्तमान में हो रही बारिश के कारण खोदी गई सड़कों पर भारी कीचड़ हो गया है। सड़क कट जाने से इस मुख्य मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीणों और राहगीरों का परेशानी हो रही है और सबसे अधिक परेशानी स्कूली ब'चों एवं दुपहिया वाहन चालकों को हो रही है। जो आये दिन इन छिपे हुए गड्डों और फिसलन के कारण दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। लाखों-करोड़ों रूपयों की लागत से बनी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क एवं बस्ती क्षेत्र की सीसी सड़क को पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई करने से खराब हो रही है। लेकिन कार्य के साथ-साथ गड्डों को समतल नही किया जा रहा है, गड्डे वैसे ही छोड़ दिये जा रहे है जिससे ग्रामीणजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और पीएचई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या की ओर कोई ध्यान नही दे रहे है जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच करवाई जाये, लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत करवाकर इसे गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाने की मांग की है।

10 हजार के विकास के लिए किया गया 10 लाख का नुकसान - विवेक

विवेक सिहोरे ने बताया कि मोहगांव ध. पंचायत में गांव में पीएचई की पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी है और संबंधित विभाग के द्वारा हनुमान मंदिर के पास पूर्व सरपंचों द्वारा बनाई गई मजबूत सीमेंट सड़क को खोद दिया गया है। यानि की महज 4 इंच की पानी की पाइपलाइन डालने के लिए पूरी सड़क को खराब कर दिया गया है। तकनीकी रूप से ठेकेदार को सड़क काटने के लिए उच्च गुणवत्तावाली आधुनिक कटर मशीनों का उपयोग करना चाहिए था ताकि सड़क खराब न हो। लेकिन यहां लापरवाही की हद पार कर दी गई। श्री सिहोरे ने बताया कि महज 10 हजार रूपये के पाइप के चक्कर में 10 लाख की सड़क को बीच से खुदाई कर खराब कर दिया गया है। जबकि इस मार्ग से 3 से 4 गांवों के स्कूली बच्चों का आना-जाना होता है। यहां बड़े-बड़े व्यापारियों के प्रतिष्ठान हैं, लेकिन सड़क खुदने से अब न तो ग्राहक आ पा रहे हैं और न ही किसान अपनी उपज लेकर आ पा रहे हैं। पूरे वार्ड और गांव के लोग इस लापरवाही से परेशान हैं। हमारी मांग है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए

क्या विभाग इस सड़क को पहले जैसी स्थिति में ला पायेगा- मनोज

ग्रामीण मनोज बनोटे ने बताया कि ग्राम में पाइपलाइन का विस्तार होना और हर घर तक पानी पहुंचना एक अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन पीएचई विभाग के माध्यम से ठेकेदार द्वारा काम करने का तरीका बेहद गलत है। सड़क के बिल्कुल बीचों-बीच खुदाई कर दी गई है। इस खुदाई के कारण स्कूली बच्चों, राहगीरों और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि सड़क को इस तरह खोदकर छोड़ा गया है कि अब यहां से किसी बड़े वाहन के निकलने का कोई विकल्प ही नहीं बचा है। श्री बनोटे ने बताया कि जो सड़क पहले इतनी अ'छी और मजबूत थी, वह अब इस खुदाई के बाद कभी वैसी नहीं बन पायेगी। हम पीएचई विभाग से सीधा सवाल करना चाहते हैं कि क्या वे इस क्षतिग्रस्त सड़क को वापस उसी मजबूत और सुव्यवस्थित स्थिति में बनाकर देंगे जैसी यह पहले थी। साथ ही यह भी बताया कि पीएचई विभाग व ठेकेदार के कर्मचारी पाइपलाइन बिछाने के कार्य में अनियमितता बरत रहे है, हमारी मांग है कि सुव्यवस्थित तरीके से कार्य किया जाये ताकि आने-जाने वालों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

महाविद्यालय में नशे के प्रति जनजागरूकता पर विशेष व्याख्यान माला का हुआ आयोजन

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अन्तर्गत नशा उन्मूलन गतिविधियों के तहत शुक्रवार को महाविद्यालय में नशे के प्रति जन जागरूकता संबंधी विशेष व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रभारी प्राचार्य डॉ. देवराज चौरे की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। जिसमें सर्वप्रथम उपस्थितजनों ने माँ सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्र'वलित कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य डॉ. देवराज चौरे ने विद्यार्थियों से आव्हान किया कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने परिवार व आस-पास के लोगों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। प्रो. सुमन बरवा ने अपने व्याख्यान में कहा कि नशा उन्मूलन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें स्वयं नशे से दूर रहना होगा, अपने मित्रों और परिवार को इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना होगा। कार्यक्रम प्रभारी डॉ. प्रदीपकुमार भिमटे ने कहां कि आज हमारे देश का युवा वर्ग राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन जब यही युवा शराब, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट और अन्य मादक पदार्थो की गिरफ्त में आ जाता हैं, तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। नशा केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि सोचने-समझने की क्षमता, आत्मविश्वास, परिवार की खुशियाँ और समाज की शांति को नष्ट कर देता है। कार्यक्रम का मंच संचालन श्रीमती भूमेश्वरी ठाकरे एवं आभार प्रदर्शन श्रीमती अनिभा शरणागत के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को सफ ल बनाने में सहायक प्राध्यापक डॉ. निर्मल कीर्ति गेडाम, नरेश सौलखे, श्रीमती संध्या भलावे, मनीष शिवहरे, डॉ. आशा कारे, डॉ. आरती विश्वकर्मा, दीपक अहिरवार, पीतम मुरते, यादोराव राजुरकर, व्यंकटरमन नगपुरे, श्रीमती सरिता एड़े, रामदयाल मथारे, लकेश गेडाम, श्रीमती वंदना कुर्वे, मिनेश पंचेश्वर, प्रसिक हुमनेकर, निशांत तलवरे, इकबाल खान सहित अन्य प्राध्यापक एवं छात्र-छात्राओं का सराहनीय योगदान रहा।

नशे के खिलाफ लालबर्रा पुलिस की मुहिम

बोरी के हाई और बल्हारपुर के हायर सेकेण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों को किया जागरूक

पद्मेश न्यूज।लालबर्रा। लालबर्रा पुलिस के द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अन्तर्गत शासकीय हाई स्कूल बोरी एवं शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल बल्हारपुर में शुक्रवार को ग्राम नशा मुक्ति अभियान के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों और इससे समाज व परिवार पर पड़ने वाले घातक असर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वारासिवनी एसडीओपी (अनुविभागीय अधिकारी पुलिस) अभिषेक चौधरी ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराई से कोसों दूर रहना चाहिए। उन्होने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से खोखला नहीं करता, बल्कि पूरे हंसते-खेलते परिवार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। आज का युवा वर्ग अनजाने में या संगति के असर में आकर नशे की गिरफ्त में फंस रहा है, जिसे रोकना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री चौधरी ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अपने आसपास यदि किसी को नशे की लत में देखते हैं, तो उसे समझाएं और अपने माता-पिता या पुलिस को इस बात की सूचना दें क्योंकि जागरूक छात्र ही एक नशामुक्त और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लालबर्रा थाना प्रभारी श्री दायमा ने विद्यार्थियों को कानूनी पहलुओं और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अधिकांश अपराधों के पीछे कहीं न कहीं नशा एक मुख्य वजह होता है। नशे की हालत में व्यक्ति सही और गलत का अंतर भूल जाता है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं और आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं। विद्यार्थी पुलिस के कान और आंख बन सकते हैं। अगर गांव या स्कूल के आसपास कोई अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करता है, तो बिना डरे पुलिस को बताये, सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। थाना प्रभारी ने सभी छात्र-छात्राओं को जीवन में कभी भी नशा न करने और अपने गांव को नशामुक्त बनाने में सहयोग करने की शपथ दिलाई। वहीं स्कूल प्रबंधन और ग्रामीणों ने लालबर्रा पुलिस की इस पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह के अभियानों से बच्चों में सही उम्र में अ'छे संस्कार और सजगता आती है। वहीं कार्यक्रम के अंत में पुलिस अधिकारियों द्वारा ब'चों के सवालों के जवाब भी दिये गये और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस जागरूकता अभियान के दौरान दोनों ही स्कूलों के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, बड़ी संख्या में छात्र-छात्रांएं एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कंजई की बेटी श्रध्दा बिसेन ने पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण की नीट परीक्षा, शासकीय कॉलेज में पाई (एमबीबीएस) सीट

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। ग्रामीण अंचलों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इसे एक बार फिर सच कर दिखाया है, क्षेत्र की होनहार सुपुत्री कुमारी श्रध्दा बिसेन ने। श्रध्दा ने अपने पहले ही प्रयास में देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन मानी जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-2026) में शानदार सफलता हासिल की है। इस सफलता के साथ ही उन्होंने शासकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट सुरक्षित कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कुमारी श्रध्दा बिसेन, देव नगरी कंजई के प्रतिष्ठित नागरिक, सरपंच, अधिवक्ता आनंद बिसेन की सुपुत्री हैं। श्रध्दा बिसेन ने अपनी इस सफलता से न केवल अपने माता-पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया है, बल्कि पूरे ग्राम कंजई सहित लालबर्रा क्षेत्र को गौरवांवित किया है। नगर व ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर देश के सर्वोच्च मेडिकल एग्जाम को पहले ही प्रयास में पास करना उनकी असाधारण प्रतिभा और कठिन परिश्रम को दर्शाता है।

परिजनों और शुभचिंतकों में हर्ष की लहर

जैसे ही नीट परीक्षा के परिणाम घोषित हुए और श्रध्दा

बिसेन को शासकीय मेडिकल कॉलेज अलॉट होने की खबर आई, वैसे ही उनके निवास स्थान पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। श्रध्दा की इस स्वर्णिम सफलता पर उनके परिवार, रिश्तेदारों, स्नेहीजनों और मित्रों में भारी हर्ष व्याप्त है। क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। वहीं अपनी सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कुमारी श्रध्दा बिसेन ने बताया कि इस परीक्षा के लिए मैंने पूरी एकाग्रता के साथ नियमित अध्ययन किया। डॉक्टरों की कमी को दूर करना और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। उन्होने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के कुशल मार्गदर्शन, गुरूजनों के आशीर्वाद और अपने कठिन परिश्रम को दिया है। वहीं क्षेत्रीयजनों का कहना है कि श्रध्दा बिसेन की यह सफलता क्षेत्र के अन्य छात्र-छात्राओं के लिए भी प्रेरणा स्त्रोत बनेगी, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। श्रध्दा बिसेन की इस अभूतपूर्व सफलता पर क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और बुध्दिजीवियों ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की है।

सांदीपनी स्कूल लेंडेझरी का 4 स्कूलों के विद्यार्थियों ने किया शैक्षणिक भ्रमण

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लेंडेझरी स्थित सांदीपनी स्कूल का गुरूवार को लालबर्रा विकासखंड स्थित 4 शासकीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने शैक्षणिक भ्रमण किया। जिसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवरगांव ला., उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बकोड़ा, व कोपे स्कूल शामिल है। इन चार विद्यालयों के विद्यार्थियों को लेंडेझरी स्थिति सांदीपनी स्कूल का एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने क्षेत्र के प्रतिष्ठित सांदीपनी स्कूल का भ्रमण कर वहां की आधुनिक शैक्षणिक गतिविधियों और व्यवस्थाओं को करीब से देखा व समझा। भ्रमण के दौरान बच्चों ने सांदीपनी स्कूल के अत्याधुनिक आई.टी. लैब, केमिस्ट्री लैब, डाइनिंग रूम, किड्स रूम सहित स्कूल की तमाम गतिविधियों व बारीकियों का अवलोकन किया। साथ ही स्कूल के व्यवस्थित माहौल और आधुनिक संसाधनों को देखकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आये और उन्होंने स्कूल की गतिविधियों व व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की। वहीं शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आधुनिक शिक्षा पध्दतियों और व्यावहारिक ज्ञान से अवगत करवाना था। इस शैक्षणिक भ्रमण में मुख्य रूप से संस्था के प्रमुख एएन त्रिपाठी, एएल टेंभरे, श्री रिनायत, श्री पटले, आईटी शिक्षक कमलेश चौधरी सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

आस-पास की खबरें

वारासिवनी न्यायालय में चेक बाउंस विशेष लोक अदालत आज

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी न्यायालय में आगामी 18 जुलाई को चेक बाउंस के लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह अदालत मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देशानुसार रखी गयी हैं। इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य परकाम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत पंजीकृत चेक बाउंस के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा करना है। इस विशेष लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के अध्यक्ष प्राणेश कुमार प्राण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व न्यायाधीश सतीश शर्मा के कुशल मार्गदर्शन व निर्देशन में किया जा रहा है। तहसील विधिक सेवा समिति वारासिवनी की अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीमती कविता इवनाती ने आम जनता और पक्षकारों से अपील की है कि जिन नागरिकों के चेक बाउंस से संबंधित राजीनामा योग्य समझौता वादी मामले न्यायालय में लंबित हैं वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। उन्होंने पक्षकारों से 18 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मामलों का शांतिपूर्ण ढंग से निराकरण कराने का आग्रह किया है। श्रीमती कविता इवनाती ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निपटारे से दोनों पक्षों के मध्य आपसी सौहार्द और संबंध बने रहते हैं। न्यायालयी चक्करों से मुक्ति मिलने के कारण पक्षकारों के समय और धन दोनों की बड़ी बचत होती है। इस प्रक्रिया के तहत मामला सुलझने पर नियमानुसार कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। इस विशेष लोक अदालत के संबंध में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी या सहायता प्राप्त करने के लिए नागरिक तहसील विधिक सेवा समिति वारासिवनी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

सूने घर में 11वीं की छात्रा ने लगाई फांसी पुलिस जांच में जुटी

मोबाइल की घंटी बजने पर हुआ खुलासा फंदे पर लटकी मिली लाड़ली

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। वारासिवनी।

खैरलांजी पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम आरंभा में शुक्रवार को एक बेहद दर्दनाक और हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहाँ 11वीं कक्षा की एक 16 वर्षीय छात्रा ने अपने ही सूने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दुखद घटना की खबर जैसे ही पूरे गाँव में फैली सनसनी मच गई और हर कोई स्तब्ध रह गया। सूचना मिलते ही खैरलांजी पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और गहन जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम आरंभा के निवासी मोतीलाल ठाकरे का परिवार यहाँ रहता है। उनकी छोटी बेटी शिवानी ठाकरे 16 वर्ष शिक्षा में होनहार थी और उसने इसी वर्ष पीएम श्री स्कूल भेंडारा में कक्षा 11वीं बायोलॉजी में प्रवेश लिया था। गुरुवार को वह रोजाना की तरह स्कूल गई थी लेकिन शुक्रवार को वह घर पर ही थी। घटना शुक्रवार दिन की है जब शिवानी घर पर अकेली थी। उसके पिता आजीविका चलाने के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ गए हुए हैं जहाँ वह मजदूरी करते हैं। जबकि उसकी माँ और बड़ी बहन धान की रोपाई के लिए खेतों में गई हुई थीं। घर पर सिर्फ शिवानी और उसकी बुजुर्ग दादी थीं। दादी लगी। लगातार मोबाइल बजने पर जब उसकी दादी कमरे की तरफ गईं तो अंदर का नजारा खैरलांजी थाना पुलिस को दी गई। चूंकि मामला एक नाबालिग लड़की की

घर के बाहरी हिस्से में थीं जबकि शिवानी अंदर कमरे में थी। इसी बीच अज्ञात कारणों के चलते शिवानी ने कमरे के भीतर फांसी का फंदा बनाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। इस खौफनाक वारदात का पता तब चला जब शिवानी के मोबाइल पर अचानक किसी का फोन आया और रिंगटोन बजने देखकर उनके होश उड़ गए। शिवानी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी और उसकी सांसें थम चुकी थीं। वृद्ध दादी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते वहाँ ग्रामीणों का भारी हुजूम जमा हो गया। ग्रामीणों द्वारा तत्काल घटना की सूचना संदिग्ध आत्महत्या से जुड़ा था इसलिए खैरलांजी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की गंभीरता को समझा। पुलिस ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और बालाघाट से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को विशेष रूप से मौके पर बुलाया। एफ एसएल टीम और स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारकर आवश्यक पंचनामा कार्यवाही पूरी की। पुलिस ने मृतिका के शव को खैरलांजी स्थित पोस्टमार्टम गृह पहुंचाया। जहां डॉक्टरों के द्वारा शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं खैरलांजी पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच को आगे बढ़ाया है। पुलिस के द्वारा परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रहे हैं ताकि आत्महत्या के असली कारणों का पता लगाया जा सके।

इनका कहना हैं-

दूरभाष पर चर्चा में बताया कि आरंभा में एक ब' ची के द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। जिस पर खैरलांजी पुलिस को मौके पर भेज दिया गया है वहीं एफएसएल टीम के द्वारा घटना की जांच की जा रही है। 16 वर्षीय बालिका है अब किस कारण उसने यह कदम उठाया वह विवेचना का विषय है मामले में जांच प्रारंभ कर दी गई है। अभी तक मौत का कारण अज्ञात हैं।

अभिषेक चौधरी
एसडीओपी वारासिवनी

गाली देकर मारपीट करने वाले दोषी को 6 माह की जेल और जुर्माना

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश नयन जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने पड़ोस में कचरा फेंकने का विरोध करने पर महिला के साथ गाली गलौज और लाठी से मारपीट करने वाले मामले में एक आरोपी को जेल की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त विजय बरैया को धारा 325 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाया और उसे 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड ना चुकाने की स्थिति में अभियुक्त को 7 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रणव राजनेगी ने बताया की मामला 12 नवंबर 2020 का है। सुबह करीब 11 बजे प्रार्थियां के पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त की पत्नी घर का कचरा लाकर प्रार्थियां के घर के सामने फेंक रही थी। जब प्रार्थिया ने इसका विरोध करते हुए कचरा वहां फेंकने से मना किया तो अभियुक्त विजय पिता हेमचंद बरैया उम्र 43 वर्ष निवासी मोहगांव धपेरा वहां आ गया और विवाद करने लगा। आरोपी ने यह कहते हुए कि यह हमारी जगह है प्रार्थिया को मां.बहन की अत्यंत अश्लील गालियां देनी शुरू कर दीं। जब प्रार्थियां ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने हाथ में रखी लकड़ी से उस पर हमला कर दिया। इस मारपीट के कारण प्रार्थियां के दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई। इतना ही नहीं आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पुलिस थाना लालबर्रा के द्वारा मामले की आवश्यक विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान अभियोजन ने कोर्ट के सामने पुख्ता साक्ष्य और तथ्य पेश किए। सहायक निदेशक कपिल कुमार डेहरिया के कुशल मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रणव राजनेगी द्वारा की गई। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों पर विश्वास करते हुए अभियुक्त विजय बरैया को दोषी करार दिया और उपरोक्त सजा से दंडित किया।

विधायक गौरव सिंह पारधी की पहल पर कटंगी में क्लाइमेट ग्रीन इकोनॉमिक जोन परियोजना को मिली गति

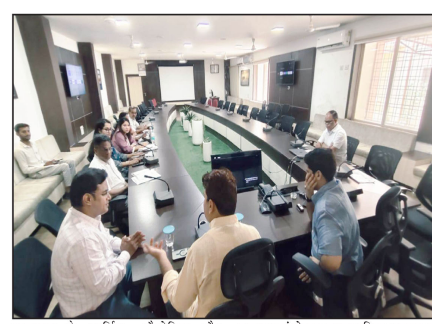

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। कटंगी.खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के समग्र एवं सतत विकास की दिशा में विधायक गौरव सिंह पारधी की पहल पर क्लाइमेट पार्लियामेंट इंडिया के सहयोग से क्लाइमेट ग्रीन इकोनॉमिक जोन परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विधायक के मार्गदर्शन में क्लाइमेट पार्लियामेंट इंडिया के प्रतिनिधि निखिल चौहान ने कलेक्टर मृणाल मीणा से मुलाकात कर परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इसके बाद विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर परियोजना के क्रियान्वयन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में हरित ऊर्जा आधारित उद्योगों की स्थापना, निवेश आकर्षित करने, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने, कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई दिशा देने पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही विभागों के समन्वय से परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतारने पर सहमति बनी। विधायक गौरव सिंह पारधी ने कहा कि यह परियोजना कटंगी एवं बालाघाट के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि शासन, प्रशासन और सभी संबंधित विभागों के सहयोग से इस महत्वाकांक्षी योजना को जल्द अमल में लाया जाएगा। परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, वेयर हाउसिंग, कृषि आधारित उद्योगों सहित विभिन्न ग्रीन सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। जिससे स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही स्थानीय व्यापार, लघु उद्योग और किसानों को भी नए बाजार एवं बेहतर व्यावसायिक अवसर प्राप्त होंगे। कलेक्टर मृणाल मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने अपने कार्यालयों एवं परिसरों में ग्रीन एनर्जी आधारित सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दें, ताकि कटंगी का यह मॉडल प्रदेश ही नही, बल्कि देश के लिए भी हरित विकास का उदाहरण बन सके। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, खनिज, विद्युत वितरण, उद्योग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं क्लाइमेट पार्लियामेंट इंडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बारिश से सिंगोड़ी उमरवाड़ा मार्ग पर चलना हुआ दूभर ग्रामीण आक्रोशित

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंगोड़ी से उमरवाडा मार्ग की हालत इन दिनों बद से बदतर हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश के कारण यह पूरा मार्ग बेतहाशा कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गया है। जिससे मार्ग का आवागमन पूरी तरह से ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। कई वर्षों से उपेक्षित इस मार्ग के निर्माण ना होने से अब स्थानीय ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे रहा है और उनमें प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है।

कम दूरी का सफर बना जी का जंजाल

प्राप्त जानकारी के अनुसार उमरवाडा, बकेरा सहित आसपास के विभिन्न ग्रामीणों के लिए रामपायली पहुंचने के लिए सिंगोड़ी वाला मार्ग सबसे सीधा, सटीक और कम दूरी का विकल्प है। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण यह महत्वपूर्ण मार्ग आज भी कच्चा और जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। वर्तमान में इस मार्ग पर पैदल चलना तो दूर मोटरसाइकिल या साइकिल से गुजरना भी जान जोखिम में डालने जैसा है। जगह.जगह बने दलदल में राहगीरों के पैर धंस रहे हैं और आए दिन दुपहिया वाहन चालक कीचड़ में फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। इस नारकीय स्थिति से बचने के लिए अब राहगीरों को मजबूरन लालपुर होते हुए करीब 4 किलोमीटर का अतिरिक्त और लंबा फासला तय करना पड़ रहा है। एक ओर जहां राहगीर लंबा रास्ता अपना रहे हैं वहीं दूसरी ओर इस मार्ग के किनारे स्थित खेतों के किसानों को भारी मजबूरी में इसी जानलेवा कीचड़ और दलदल से होकर गुजरना पड़ रहा है। कृषि कार्य के दिनों में किसानों को आ रही यह समस्या उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। ग्रामीणों ने इस मार्ग के पक्के निर्माण के लिए अनेकों बार संबंधित विभाग और जिम्मेदार लोगों से गुहार लगाई है लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला हैं जिससे वह बहुत परेशान है।

सड़क की जर्जर हालत से ग्रामीणों में आक्रोश- चैनलाल भगत

ग्रामीण चैनलाल भगत ने बताया कि सड़क की हालत बारिश आने से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मोटरसाइकिल साइकिल कीचड़ में फंस रही है वर्तमान में पैदल ही लोगों का आना जाना हो पा रहा है। यहां सामने कुछ जगह ठीक है बाकी आगे दलदल जैसी स्थिति है बारिश आने पर हर बार यही स्थिति हो जाती है। कई वर्षों से हम देख रहे हैं पंचायत द्वारा मुरुम डालकर रोड़ बनाई गई थी परंतु वह सार्थक नहीं है। शासन प्रशासन को पक्की सड़क बनाकर देनी चाहिए यहां से बहुत आवागमन बना रहता है कई गांव के लोग आते जाते रहते हैं सड़क पर ध्यान देना चाहिए।

बारिश के कारण गढ़ों में पानी और सड़क पर कीचड़ बहुत हो गया है-धनेंद्र पारधी

ग्रामीण धनेंद्र पारधी ने बताया कि सड़क में गड्ढे बहुत ज्यादा है बारिश के कारण गढ़ों में पानी भर गया है तो वहीं सड़क पर कीचड़ में बहुत हो गया है। यह सड़क विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र एवं खेती किसानी में जाने के लिए उपयोग होती है परंतु बारिश के कारण सड़क खराब होने से आना जाना बहुत कम हो गया है। सड़क पर कीचड़ है लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं अधिकांश लोग लालपुर होते हुए उमरवाड़ा जा रहे हैं। इस दौरान उन्हें करीब 4 किलोमीटर का फेरा काटना पड़ रहा है हम चाहते हैं कि यह रोड़ बने ताकि सभी को सुविधा हो।

अज्ञात कीट के काटने से 5 वर्षीय बालिका बीमार जिला अस्पताल रिफर

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम खंडवा में शुक्रवार को एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची अज्ञात कीट के काटने से गंभीर रूप से बीमार हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची की

हालत को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खंडवा निवासी कमलेश पटले की 5 वर्षीय पुत्री पूर्वी पटले शुक्रवार को रोजाना की तरह अपने घर में खेल रही थी। खेलते खेलते वह अचानक सीढ़ियों से नीचे उतरी तभी वहां छिपे किसी अज्ञात जीव या जहरीले कीट ने उसे काट लिया। कीट के काटते ही मासूम पूर्वी दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूर्वी के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के सदस्य तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे। परिजनों ने आसपास काफी खोजबीन की कि किस जीव ने बच्ची को काटा है लेकिन तब तक वह अज्ञात जीव वहां से भाग चुका था और मौके पर कुछ नजर नहीं आया। कुछ ही देर में बच्ची के पैर की उंगली में तेजी से सूजन आने लगी घबराए परिजन उसे बिना समय गंवाए तत्काल वारासिवनी के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची का प्राथमिक उपचार किया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर कर दिया गया।

सोनम वांगचुक का व्यक्तिगत त्याग शिक्षा सुधार के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा बने

जब संसद का सत्र शुरू होता है तो देश की निगाहें बहस, हंगामे और नए कानूनों पर टिक जाती हैं। टेलीविजन चैनलों पर राजनीतिक समीकरणों का विश्लेषण शुरू हो जाता है और सुर्खियां यह तय करने लगती हैं कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन लोकतंत्र की वास्तविक सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि संसद ने कितने विधेयक पारित किए। असली सवाल यह है कि संसद ने देश के सामने मौजूद सबसे महत्वपूर्ण सवालों को कितनी गंभीरता से उठाया और उनके समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठाए। आज ऐसा ही एक बड़ा सवाल संसद के बाहर खड़ा है, भारत की शिक्षा व्यवस्था का भविष्य क्या होगा? सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, इंजीनियर और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन इसी सवाल को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला रहा है। उनका संघर्ष केवल किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है। यह उस शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता है, जो देश के करोड़ों बच्चों और युवाओं का भविष्य तय करती है। सोनम वांगचुक की पत्नी की चिंता स्वाभाविक है। हर दिन अपने पति के कमजोर होते शरीर को देखना किसी भी परिवार के लिए पीड़ादायक होगा। लेकिन यह व्यक्तिगत चिंता अब राष्ट्रीय चिंता बन चुकी है। जब कोई व्यक्ति अपने विश्वास और उद्देश्य के लिए अहिंसक तरीके से व्यक्तिगत त्याग का रास्ता चुनता है, तो उसका उद्देश्य केवल सरकार को झुकाना नहीं होता। वह समाज और सत्ता की अंतरात्मा को जगाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि इस आंदोलन का परिणाम यदि केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे या मंत्रालय में फेरबदल तक सीमित रह जाता है, तो यह एक बड़े राष्ट्रीय प्रश्न को छोटा कर देगा। लोकतंत्र में मंत्रियों की जवाबदेही आवश्यक है। यदि कोई मंत्री अपने विभाग की विफलताओं की जिम्मेदारी नहीं लेता, तो उससे इस्तीफे की अपेक्षा करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन व्यक्ति बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। मंत्री आते-जाते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, राजनीतिक दल सत्ता में आते-जाते रहते हैं, लेकिन शिक्षा संस्थाएं और नीतियां लंबे समय तक समाज को प्रभावित करती हैं।

इसलिए आज भारत को केवल शिक्षा मंत्री बदलने की नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की दिशा बदलने की जरूरत है। लगभग डेढ़ दशक पहले भारत की करीब आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु की थी। अर्थशास्त्रियों ने इसे भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश कहा। दुनिया के किसी भी देश के लिए इतनी बड़ी युवा आबादी एक असाधारण अवसर होती है। यदि इस युवा शक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर मिलें, तो यह देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्कूलों और कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। नामांकन में वृद्धि हुई है। शिक्षा का विस्तार पहले की तुलना में कहीं अधिक हुआ है। लेकिन केवल स्कूल और कॉलेज बढ़ा देना शिक्षा की सफलता का प्रमाण नहीं है। असली सवाल यह है कि बच्चे और युवा वास्तव में क्या सीख रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपनी कक्षा के अनुरूप पढ़ने, लिखने और गणितीय कौशल में अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाते। उच्च शिक्षा में भी डिग्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन शोध, नवाचार, आलोचनात्मक सोच और रोजगारपरक कौशल के क्षेत्र में अभी लंबी दूरी तय करनी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति- 2026 एवं राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक- 2026 मसौदा जारी

27 व 31 जुलाई 2026 तक सुझाव आमंत्रित-विकसित भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने वाला दूरदर्शी कदम समग्र व्यापक विश्लेषण

वैश्विक स्तरपर भारत आज विकसित भारत- 2047 के अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है,जहाँ आर्थिक प्रगति के साथ- साथ एक सुदृढ़,आधुनिक, वैज्ञानिक तथा जन-केंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है भारत आज केवल विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं, बल्कि तेजी से उभरती हुई स्वास्थ्य महाशक्ति बनने की दिशा में भी निरंतर आगे बढ़ रहा है।किसी भी राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि केवल उसके सकल घरेलू उत्पाद से नहीं मापी जाती, बल्कि उसके नागरिकों के स्वास्थ्य,अनुसंधान क्षमता, चिकित्सा नवाचार तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से भी आंकी जाती है। यही कारण है कि भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निरंतर ऐसी नीतियाँ और कानून विकसित कर रहा है जो देश की स्वास्थ्य प्रणाली को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सशक्त बना सकें।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र अधिवक्ता होने के नाते इस आर्टिकल के माध्यम से आम जनता को यह जानकारी देना चाहूंगा कि अभी हाल ही में 8 जुलाई 2026 को जारी की गई डब्ल्यूएचओ- आईएआर सी ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर 2026 की कैंसर सुनामी 2050 की चेतावनी से दुनियाँ चिंतित हो गई है? इसके पहले हमने देखे कि कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनियाँ को यह स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी देश की वास्तविक ताकत केवल उसकी सैन्य या आर्थिक क्षमता नहीं होती, बल्कि उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था, वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता और दवा प्रणाली की मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।महामारी के दौरान भारत ने टीकों के अनुसंधान,उत्पादन और वैश्विक आपूर्ति में जो भूमिका निभाई, उसने दुनिया का ध्यान भारतीय वैज्ञानिक क्षमता की ओर आकर्षित किया।इसी अनुभव के आधार पर अब भारत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रही है।इसी दिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति- 2026 तथा राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक-2026 के मसौदे सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किए गए हैं।इन पर क्रमश: 27 जुलाई 2026 तथा 31 जुलाई 2026 तक नागरिकों वैज्ञानिकों, चिकित्सा विशेषज्ञों, फार्मासिस्टों, शिक्षाविदों,उद्योग जगत तथा अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। यह पहल इस बात का प्रमाण है कि सरकार नीति निर्माण को केवल सरकारी प्रक्रिया न मानकर जनभागीदारी पर आधारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाना चाहती है।

साथियों,आज पूरी दुनियाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में चौथी औद्योगिक क्रांति का अनुभव कर रही है।आर्टिफिशल इंटेलीजेंस,मशीन लर्निंग,जीन एडिटिंग,बिग डेटा, रोबोटिक सर्जरी, टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जैसी तकनीकें चिकित्सा व्यवस्था का स्वरूप बदल रही हैं। ऐसे समय में भारत यदि अपनी अनुसंधान नीति और फार्मेसी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक नहीं बनाता, तो भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकता है।राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति-2026 का मूल उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा देना है। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि जिन देशों की वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता मजबूत होती है, वे महामारी, नई बीमारियों और स्वास्थ्य आपदाओं का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। भारत ने भी कोरोना काल में वैक्सीन निर्माण, दवा उत्पादन तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, किंतु इस अनुभव ने यह भी बताया कि अनुसंधान के लिए दीर्घकालिक निवेश, आधुनिक प्रयोगशालाएँ, प्रशिक्षित वैज्ञानिक, गुणवत्ता पूर्ण डेटा तथा उद्योग एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग आवश्यक है।नई नीति इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान को अधिक समन्वित, पारदर्शी,नैतिक तथा नवाचार- आधारित बनाने का प्रयास करती है।

साथियों, यह नीति केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य अनुसंधान को सीधे जनस्वास्थ्य से जोड़ना है।कैंसर,मधुमेह,हृदय रोग, मानसिक स्वास्थ्य, क्षय रोग, दुर्लभ बीमारियाँ,एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस,मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा वृद्धजन स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता जीनोमिक्स बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल हेल्थ, बिग डेटा तथा प्रिसिजन मेडिसिन जैसे आधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार केंद्र बनाने का लक्ष्य भी इस नीति में दिखाई देता है। अनुसंधान में नैतिक मानकों का पालन, डेटा सुरक्षा, रोगियों के अधिकारों की रक्षा तथा वैज्ञानिक पारदर्शिता को भी नीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक-2026 भारत की फार्मेसी शिक्षा एवं पेशेवर नियमन में व्यापक सुधार का प्रयास है। आज भारत विश्व की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में प्रसिद्ध है। देश विश्व के अनेक देशों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराता है। भारतीय औषधि उद्योग वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है, किंतु फार्मेसी शिक्षा, प्रशिक्षण, पंजीकरण व्यवस्था, व्यावसायिक नैतिकता तथा आधुनिक कौशल विकास में समय के साथ सुधार की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही थी। प्रस्तावित विधेयक इन्हीं कमियों को दूर करने का प्रयास करता है ताकि भारत में फार्मेसी शिक्षा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सके।

साथियों,विधेयक का उद्देश्य केवल एक नया आयोग बनाना नहीं है,बल्कि पूरे नियामक ढाँचे का आधुनिकीकरण करना है। इसमें फार्मेसी शिक्षा कीगुणवत्ता बढ़ाने, आधुनिक पाठ्यक्रम लागू करने, डिजिटल पंजीकरण प्रणाली विकसित करने, राज्यों और केंद्र के बीच बेहतरसमन्वय स्थापित करने, फार्मासिस्टों के लिए सतत व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने तथा मरीज- केंद्रित फार्मेसी सेवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। यदि ये सुधार प्रभावी रूप से लागू होते हैं तो देश में दवा वितरण व्यवस्था और अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक तथा सटिका से जवाबदेह बन सकती है।

साथियों, इन दोनों मसौदों का सबसे बड़ा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। मजबूत स्वास्थ्य अनुसंधान प्रणाली के कारण नई दवाओं, वैक्सीनों और उपचार पद्धतियों का विकास तेज होगा। रोगों की शीघ्र पहचान संभव होगी, उपचार अधिक प्रभावी होगा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। फार्मेसी शिक्षा में सुधार से अधिक प्रशिक्षित और उत्तरदायी फार्मासिस्ट तैयार होंगे, जिससे दवाओं के सुरक्षित उपयोग, रोगियों को उचित परामर्श तथा नकली एवं निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाने में भी सटीकता से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

साथियों, वैश्विक स्तर पर भी इन सुधारों का महत्व अत्यंतव्यापक है।वर्तमान समय में विश्वस्वास्थ्य अनुसंधान, जैव-प्रौद्योगिकी, डिजिटल हेल्थ, मेडिकल डिवाइस, वैक्सीन विकास तथा प्रिसिजन मेडिसिन के क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका,ब्रिटेन, जर्मनी, जापान,दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों ने अनुसंधान एवं नवाचार को राष्ट्रीय विकास का आधार बनाया है। यदि भारत भी इन दोनों सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करता है तो वह वैश्विक क्लीनिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल निर्माण,जैव-प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य नवाचार का प्रमुख केंद्र बन सकता है। इससे विदेशी निवेश, रोजगार, निर्यात तथा वैज्ञानिक सहयोग के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।

साथियों, हालाँकि, इन सुधारों की सफलता केवल कानून बनाने से सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए अनुसंधान पर पर्याप्त सार्वजनिक एवं निजी निवेश बढ़ाना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधान सुविधाएँ विकसित करनी होंगी, मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आधुनिक प्रयोगशालाएँ स्थापित करनी होंगी तथा युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन देना होगा। साथ ही डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अनुसंधान नैतिकता, बौद्धिक संपदा अधिकार तथा रोगियों की गोपनीयता जैसे विषयों पर भी स्पष्ट और प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी होगी। फार्मेसी शिक्षा में व्यावहारिक प्रशिक्षण, उद्योग- अकादमिक सहयोग तथा आधुनिक तकनीकों का सटीकता से समावेश भी आवश्यक होगा।

साथियों, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित करना केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है,बल्कि नीति निर्माण को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने का माध्यम है चिकित्सक,वैज्ञानिक,फार्मासिस्ट,शिक्षण संस्थान, अस्पताल, उद्योग संगठन, सामाजिक संस्थाएँ तथा आम नागरिक अपने अनुभवों के आधार पर ऐसे सुझाव दे सकते हैं जो भविष्य में इन नीतियों और कानूनों को अधिक उपयोगी बना सकें। यह जनभागीदारी ही लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है।यदि सुझावों के आधार पर अंतिम नीति और विधेयक को व्यापक,व्यवहारिक तथा भविष्य उन्मुख स्वरूप दिया जाता है तो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था नई ऊँचाइयों तक पहुँच सकती है।इससे देश में अनुसंधान संस्कृति मजबूत होगी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, चिकित्सा शिक्षा और फार्मेसी शिक्षा विश्वस्तरीय बनेगी तथा भारत वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व की दिशा में और अधिक सशक्त होकर आगे बढ़ेगा।

अत: अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति- 2026 तथा राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक-2026 केवल दो मसौदा दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि विकसित भारत की भावी स्वास्थ्य व्यवस्था की आधारशिला हैं। यदि सरकार इन पर प्राप्त सुझावों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर उन्हें अंतिम स्वरूप में समुचित स्थान देती है और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है, तो भारत न केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करा सकेगा, बल्कि स्वास्थ्य अनुसंधान, दवा निर्माण, चिकित्सा शिक्षा और वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनने की दिशा में भी ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करेगा। यही विकसित भारत-2047 की वास्तविक भावना है, जहाँ विज्ञान, अनुसंधान, गुणवत्ता, पारदर्शिता और जनभागीदारी मिलकर स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगी।

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

तटीय सुरक्षा का अभेद्य कवच बनेगा भारत

-कांतिलाल मांडोत

बंदरगाहों पर सख्त निगरानी से रुकेगी घुसपैठ आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी

भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा देश की आर्थिक प्रगति, सामरिक शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। समुद्री मार्गों से देश का अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, इसलिए बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सबसे महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में समुद्री रास्तों के जरिए आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की हेराफेरी और अवैध घुसपैठ की घटनाओं ने यह साबित किया है कि यदि समुद्री सीमाओं की निगरानी कमजोर हो तो उसका सीधा असर देश की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ता है। इसी चुनौती को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब तटीय सुरक्षा को पूरी तरह अभेद्य बनाने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की तटीय सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा है कि समुद्री सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने तटीय जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों के मछली बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटरों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। इन संवेदनशील स्थानों पर केवल स्थायी पुलिसकर्मियों की तैनाती करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में निरंतरता और जवाबदेही बनी रहे। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो में केवल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से प्रशिक्षित निजी सुरक्षा कर्मियों को ही तैनात किया जाए। इसके साथ ही सभी प्रमुख बंदरगाहों पर कंटेनर स्कैनिंग की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती समुद्री मार्गों से होने वाली अवैध घुसपैठ रही है। कई बार तस्कर और अपराधी छोटे मछली पकड़ने वाले जहाजों या नावों का उपयोग करके भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। यदि तटीय क्षेत्रों की निगरानी मजबूत होगी, आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा और प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी तो ऐसी घुसपैठ लगभग असंभव हो जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों को पहले से सूचना मिल सकेगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

देश ने अतीत में यह अनुभव किया है कि समुद्री मार्गों का उपयोग आतंकवादी संगठन भी कर चुके हैं। ऐसे अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया कि तटीय सुरक्षा केवल सीमा सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली रक्षा पंक्ति है। गृह मंत्रालय का मानना है कि यदि बंदरगाहों, मछली लैंडिंग केंद्रों और समुद्री गतिविधियों पर चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रखी जाए तो आतंकवादी किसी भी रूप में भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आधुनिक निगरानी प्रणाली, प्रशिक्षित सुरक्षा बल और बेहतर समन्वय आतंकवाद के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करेंगे।

समुद्री मार्गों के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी भी लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती रही है। अंतरराष्ट्रीय तस्कर समुद्री रास्तों का उपयोग करके करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ भारत तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कई बार कंटेनरों के भीतर छिपाकर प्रतिबंधित सामग्री भेजी जाती है। ऐसे मामलों में यदि प्रत्येक कंटेनर की आधुनिक स्कैनिंग होगी तो अवैध सामान की पहचान करना कहीं अधिक आसान हो जाएगा। इससे न केवल मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगेगी बल्कि हथियारों, विस्फोटकों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की हेराफेरी भी रोकी जा सकेगी।

बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था में निजी सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल लाइसेंस प्राप्त और प्रशिक्षित सुरक्षा एजेंसियों को ही यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इससे सुरक्षा मानकों में एकरूपता आएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता की संभावना कम होगी। सीआईएसएफ से प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का निर्णय भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि यह बल देश के सबसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का व्यापक अनुभव रखता है।

तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए केवल पुलिस या सुरक्षा बलों की भूमिका ही पर्याप्त नहीं होती। इसमें तटरक्षक बल, नौसेना, राज्य पुलिस, खुफिया एजेंसियां, बंदरगाह प्राधिकरण और स्थानीय मछुआरा समुदाय सभी की सहभागिता आवश्यक होती है। समुद्र में सबसे पहले किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी अक्सर मछुआरों को ही मिलती है। यदि उनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए तो सुरक्षा एजेंसियां समय रहते किसी भी खतरे को रोक सकती हैं। केंद्र सरकार इसी समन्वित सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

भारत वैश्विक व्यापार का तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। देश के बंदरगाहों पर प्रतिदिन हजारों कंटेनरों का आवागमन होता है। ऐसे में सुरक्षा और व्यापार के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। आधुनिक कंटेनर स्कैनिंग प्रणाली इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी क्योंकि इससे व्यापार प्रभावित किए बिना सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकेगा। डिजिटल निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण और अत्याधुनिक स्कैनिंग तकनीक भविष्य की समुद्री सुरक्षा का आधार बन सकती है।

गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट संकेत दिया है कि तटीय सुरक्षा को लेकर सरकार किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेगी। उनका कहना है कि भारत की समुद्री सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित रहें, इसके लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित मानव संसाधन और बेहतर समन्वय के माध्यम से लगातार मजबूत किया जाएगा। उनका यह संदेश भी स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

आज भारत जिस गति से वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें सुरक्षित समुद्री सीमाएं और सुरक्षित बंदरगाह अत्यंत आवश्यक हैं। मजबूत तटीय सुरक्षा से न केवल अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी बल्कि आतंकवादी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी और नशीले पदार्थों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को भी बड़ा झटका लगेगा। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था दोनों मजबूत होंगी।

केंद्र सरकार का यह अभियान केवल सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास नहीं बल्कि भारत की समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाने का राष्ट्रीय संकल्प है। यदि सभी निर्देश प्रभावी ढंग से लागू होते हैं तो आने वाले वर्षों में भारत की तटीय सुरक्षा दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं में शामिल हो सकती है। यह कदम देश की सुरक्षा, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की दिशा में एक निर्णायक पहल साबित होगा।

मंदिरों में भ्रष्टाचारः वहां सुशासन की नई क्रांति का सूत्रपात हो

भारत की पहचान केवल उसकी प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक दर्शन से नहीं है, बल्कि उन मंदिरों से भी है जो करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और जीवन का आधार हैं। अयोध्या का श्रीराम मंदिर, बद्रीनाथ धाम, माता वैष्णोदेवी, तिरुपति, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, सालासर बालाजी, खाटू श्यामजी जैसे मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा के जीवंत प्रतीक हैं। इन मंदिरों में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु इस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि यहां उन्हें केवल भगवान के दर्शन ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और नैतिक ऊर्जा भी प्राप्त होगी। लेकिन जब इन्हीं मंदिरों से चढ़ावे की चोरी, वित्तीय अनियमितताओं, वीआईपी संस्कृति, पुजारियों अथवा कर्मचारियों के अनुचित आचरण और श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सामने आती हैं, तब केवल कोई संस्था बदनाम नहीं होती, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था घायल होती है। हाल के वर्षों में श्रीराम मंदिर, बद्रीनाथ और अब माता वैष्णोदेवी मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मंदिरों की व्यवस्था को केवल धार्मिक भावना के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जिस धन को श्रद्धालु भगवान का अर्पण मानकर समर्पित करते हैं, वह किसी व्यक्ति या समूह की निजी संपत्ति नहीं है। उस धन का प्रत्येक रुपया सार्वजनिक विश्वास की धरोहर है। यदि उसी में अपारदर्शिता या चोरी का संदेह पैदा हो जाए तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि धार्मिक विश्वास के साथ विश्वासघात है। मंदिरों में बढ़ती अव्यवस्था का दूसरा गंभीर पक्ष है-वीआईपी दर्शन संस्कृति। आज देश का सामान्य श्रद्धालु कई-कई घंटे कतार में खड़ा रहता है। वृद्ध, महिलाएं, दिव्यांग और छोटे बच्चों के साथ आए परिवार कठिन परिस्थितियों में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मंत्री, विधायक, अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति पहुंचता है, सामान्य दर्शन रोक दिए जाते हैं और वीआईपी दर्शन शुरू हो जाते हैं। आम श्रद्धालु की लाइन रोक दी जाती है, उसके दर्शन का समय बाधित होता है और उसे यह एहसास कराया जाता है कि भगवान के दरबार में भी सभी बराबर नहीं हैं। यह स्थिति भारतीय संस्कृति और धर्म की मूल भावना के विपरीत है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर के समक्ष राजा और रंक में कोई भेद नहीं होता। यदि मंदिरों में भी सामाजिक और राजनीतिक विशेषाधिकार का प्रदर्शन होगा तो यह धर्म के मूल स्वरूप का अपमान है। मंदिरों को लोकतांत्रिक समानता और आध्यात्मिक समरसता का सर्वोच्च उदाहरण बनना चाहिए, न कि सामाजिक असमानता का मंच। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में 'समान मन्दिर दर्शन नीति' लागू की जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा या अत्यंत विशिष्ट संवैधानिक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को सामान्य श्रद्धालुओं की कतार से अलग विशेष दर्शन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यदि किसी कारणवश सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक हो, तब भी आम श्रद्धालुओं के दर्शन बाधित नहीं होने चाहिए। भगवान के दरबार में सबसे बड़ा वीआईपी केवल श्रद्धा होनी चाहिए, पद और सत्ता नहीं। इसी प्रकार मंदिरों की च ?ावा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। आज डिजिटल भारत का युग है, फिर भी अनेक मंदिरों में दान और चढ़ावे की पारदर्शी व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी है। प्रत्येक बड़े मंदिर में दान-पात्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, सीसीटीवी कैमरे, बारकोड आधारित सीलिंग, नियमित स्वतंत्र ऑडिट तथा प्रत्येक माह आय-व्यय का सार्वजनिक विवरण वेबसाइट और सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। श्रद्धालु को यह जानने का अधिकार है कि उसके द्वारा दिया गया धन कहां और किस उद्देश्य में उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन में केवल धार्मिक पहचान ही नहीं, बल्कि चरित्र, ईमानदारी और प्रशासनिक दक्षता को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मंदिर प्रबंधन समितियों में ऐसे व्यक्तियों को स्थान मिले जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा निष्कलंक हो, जिनका सार्वजनिक जीवन पारदर्शी रहा हो और जिन पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या आपराधिक आरोप न हों। समय-समय पर उनके कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन भी किया जाए। मंदिर प्रबंधन किसी का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। मंदिरों में सेवा करने वाले पुजारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी आचार-संहिता बनाई जानी चाहिए। श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा, दलालों से मिलीभगत, नशाखोरी या किसी भी प्रकार का अनुशासनहीन व्यवहार पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई हो। सालासर बालाजी में बाउंसरों द्वारा श्रद्धालु की पिटाई और खाटू श्यामजी में मुख्य पुजारी से जु? विवाद जैसे प्रसंग यह संकेत देते हैं कि केवल धार्मिक पहचान पर्याप्त नहीं, बल्कि नैतिक अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है। मंदिरों में दलाल संस्कृति भी समाप्त की जानी चाहिए। दर्शन, प्रसाद, पूजा और विशेष अनुष्ठानों के नाम पर होने वाली अनधिकृत वसूली श्रद्धालुओं के विश्वास को कमजोर करती है। सभी सेवाओं की दरें सार्वजनिक हों, ऑनलाइन बुकिंग उपलब्ध हो और किसी भी अतिरिक्त वसूली पर कठोर दंड का प्रावधान हो। भारत आज विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्रीराम मंदिर के निर्माण के बाद दुनिया भर से करोड़ों लोग भारतीय मंदिरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। धार्मिक पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण आधार बन रहा है। ऐसे समय यदि मंदिरों की व्यवस्थाओं पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अव्यवस्था के आरोप लगते हैं तो केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की छवि प्रभावित होती है। विश्व यह संदेश ग्रहण करता है कि जिस देश ने धर्म और नैतिकता का संदेश दिया, वह अपने ही धर्मस्थलों को पारदर्शी नहीं बना पाया, वहां भी व्यापक भ्रष्टाचार पसरा है। भारत सरकार और राज्य सरकारों को अब इस विषय पर व्यापक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। 'राष्ट्रीय मंदिर सुशासन आयोग' जैसी स्वतंत्र संस्था का गठन किया जा सकता है, जो बड़े मंदिरों की वित्तीय पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही, दर्शन व्यवस्था और श्रद्धालुओं के अधिकारों की निगरानी करे। प्रत्येक मंदिर के लिए सेवा-मानक निर्धारित हों तथा शिकायत निवारण की समयबद्ध व्यवस्था हो। धार्मिक संगठनों और संत समाज को भी आत्ममंथन करना होगा। धर्म का अर्थ केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि सत्य, ईमानदारी, सेवा और उत्तरदायित्व है। यदि मंदिरों के भीतर ही इन मूल्यों का ह्रास होगा तो समाज को नैतिक दिशा कौन देगा? मंदिर केवल पूजा के केंद्र नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण के विद्यालय भी होने चाहिए। आज आवश्यकता किसी छोटे-मोटे सुधार की नहीं, बल्कि मंदिर प्रशासन में एक नैतिक क्रांति की है। यह क्रांति पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता और सेवा के चार स्तंभों पर आधारित होनी चाहिए। मंदिरों को तकनीक से जो?ना होगा, वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और ऑडिट-आधारित बनाना होगा, वीआईपी संस्कृति को समाप्त करना होगा तथा हर श्रद्धालु को समान सम्मान देना होगा। याद रखना होगा कि मंदिरों की सबसे बड़ी संपत्ति उनका स्वर्ण, रजत या चढ़ावा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों का विश्वास है। यदि विश्वास टूट गया तो सबसे भव्य मंदिर भी अपनी आत्मा खो देगा। इसलिए समय की पुकार है कि मंदिरों को भ्रष्टाचार से मुक्त, दर्शन व्यवस्था को समान, प्रशासन को पारदर्शी और सेवा को मानवीय बनाया जाए। यही भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, यही भारतीय संस्कृति का वास्तविक सम्मान होगा और यही वह परिवर्तन होगा जो भारत को केवल आध्यात्मिक महाशक्ति ही नहीं, बल्कि नैतिक महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करेगा।

-ललित गर्ग

इंदौर बाजार भाव

इंदौर। एजेंसी। आयातित खाद्य तेलों में बनी तेजी का असर शुक्रवार को स्थानीय बाजार पर भी दिखाई दिया। खाद्य तेलों के भाव मजबूत रहे, वहीं तिलहनों में भी मजबूती का रुख कायम रहा। खोपरा गोला के दामों में भी सुधार दर्ज किया गया। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में आयातित तेलों की कीमतों में तेजी के कारण स्थानीय खाद्य तेल बाजार में खरीदारी बढ़ी, जिससे भावों को समर्थन मिला। तिलहनों में भी मजबूती बनी रही। किराना जिंसों में शक्कर और नारियल के भावों में भी बढ़त दर्ज की गई। दलहन बाजार में चना लगभग स्थिर रहा, जबकि बेहतर पूछपरख के चलते चना और उड़द के भाव मजबूत बने रहे। कारोबारियों का कहना है कि मांग बनी रहने से अधिकांश प्रमुख कृषि जिंसों में बाजार का रुख सकारात्मक रहा। भाव इस प्रकार रहे-

किराना- शक्कर 4700-4850, खोपरा गोला 380-430, खोपरा बूरा 3200-6800 (15 कि.ग्रा.), जीरा राजस्थान 280-285, ऊंझा हल्का 290-295, बेस्ट 315-325, हल्दी निजामाबाद 210-230, सांगली 275-280, साबूदाना हल्का 5200-5350, मीडियम 5450-5600, बेस्ट 6000-6100, सच्चा मोती 5700, मोरधन 7200-8200, सौंफ मोटी 275-350, बेस्ट 350-400, सौंफ बारिक 180-300, एक्स्ट्रा बोल्ड 350-400, राई दाल 90-95, सरसो दाल 85-95, कालीमिर्च एटम 750-755, मीनी मटरदाना 770-800, मटरदाना 825-850, खसखस अनक्लीन 1150-1250, क्लीन 1300-1350, दालचीनी 250-260, जायफल 725-750, वाद्यान फूल 405-600, शाहजीरा 350-400, तेजपान 90-100, पत्थर फूल 235-425, जावत्री 1675-1750, केसर 200-250, नाग केसर 925-975, सौंठ 325-500, धोली मूसली 1400-1600, लौंग 700-720, बेस्ट 760-790, हींग (वनदेवी 751) 3450, पाउच 10 ग्राम 3550, सिंघाडा छोटा 100-120, बड़ा 120-130, सिंदूर (25 कि.ग्रा. पैकिंग) 7300, देशी कपूर 850-860, बेस्ट 875-900, पूजा बादाम 115-125, बेस्ट 220-230, पूजा सुपारी 425-450, अरीठा 180-200, हरी इलायची एवरेज 2700-2800, मीडियम 2900-3050, बेस्ट 3150-3250, एक्ट्रा बेस्ट 3300-3500, पानबार 2450, बड़ी इलायची 1800-2100, तरबूज मगज 525-550, काजू (240) 880-925, काजू (210) 950-1000, काजू डब्ल्यू (340) 840-870, काजू एस.डब्ल्यू (300) 800-825, काजू जे.एच. 840-870, टुकड़ी 780-820, बादाम मगज 840-870, सिंगापुरी 850-860, बादाम टांच 700-725, अखरोट 590-850, अखरोट गिरी 1250-1550, जर्दालु 375-500, बेस्ट 550-650, किशमिश कंधारी 450-600, इंडियन 400-450, चारौली 1450-1750, मुनक्का 350-550, अंजीर 850-950, मखाना 850-1200, बेस्ट 1350-1400, खारक एवरेज 75-80, मीर्डि?यम 90-130, बेस्ट 140-260, पिस्ता पिशोरी 2900-3100, कंधारी 2500-2700, नमकीन पिस्ता 1000-1150, बेस्ट 1200-1250, गेहूँ आटा 1820, मैदा कट्टा 1850, रवा कट्टा 1880, बेसन 4675 (50 कि.ग्रा.), नारियल (120) 2500, (160) 2900, (200) 3100, (250) 3600,

तेल- सींगदाना 1720-1740, मुम्बई 1700, राजकोट तेलिया 2630, सोया साल्वेंट 1400-1410, सोया रिफाइंड 1460-1470, कपास्या 1525-1530, धूलिया 1530, कड़ी 1530,

रात की धारणा- गुजरात लुज 1650, मुम्बई पाम 1485, मुम्बई सोया 1505,

खली- कपस्या खली (60 कि.ग्रा.) इन्दौर 2600, देवास-उज्जैन 2600, खंडवा-बुरहानपुर 2575, अकोला 3925 (प्रति क्विंटल)

तिलहन- सरसो 7800-8100, रायडा 7000-7100, सोयाबीन 7200, टोली (महुआ बीज) 5000-5100, करंज 4400-4500, अलसी 8500-9000, अरंडी 4500-4700, तिल्ली पुरानी 6500-7000, तिल्ली नई 7200-7500,

दलहन- चना कांटेवाला बेस्ट 6300-6400, एवरेज 5900-6000, विशाल 6050-6150, महाराष्ट्र विशाल 5900-5950, काबूली चना डॉलर 7000-8300, काबूली चना रशियन 5600-5800, बिटकी 5200-5300, मसूर बेस्ट 6000-6050, एवरेज 5800-5900, मूंग गर्मी बेस्ट नया 7100-7250, मूंग पुराना बोल्ड 7600-7900, मीर्डि?यम 7400-7700, मोगर 5500-6500, तुअर निमाड़ी बेस्ट 7200-7400, एवरेज 6500-6600, हल्की 6400-6500, महाराष्ट्र सफेद 7400-7500, महाराष्ट्र लाल 7700-7900, उड़द बेस्ट 9800-9900, उड़द गर्मी 8800-9500, ग्रेविटी क्लीन 10000-10200, हल्की 5000-7000,

दाल- चना दाल एवरेज 7400-7500, मीडियम 7600-7700, बोल्ड 7900-8100, तुअर दाल सवा नं. 8200-8400, तुअर दाल 7300-7600, तुअर दाल मीडियम 8500-8800, बेस्ट 9900-10200, मसूर दाल 6800-7100, मूंग दाल 8700-8900, मूंग मोगर 10100-10600, उड़द दाल 9900-10300, मोगर 10800-11000,

अनाज- गेहूं मिल क्वालिटी 2500-2550, लोकवन एवरेज 2550-2650, बेस्ट 2750-2800, मालवराज 2600-2650, गेहूँ पूर्णा एवरेज 2400-2550, बेस्ट 2650-2750, मक्का पीली 1975-2000,

चावल- चावल हंसा सफेद 2900-3100, सेला 3500-3700, परमल 3400-3500, दुबराज 4500-5500, राजभोग 7500, काली मुंछ डिनर किंग 9000, बासमती दुबार 9500-10000, मीनी दुबार 8000-8500, मोगरा 5000-7000, तिबार 10500-11500, बासमती (921) 12000-13000, बासमती सेला 7500-9500, पोहा 4500-5100,

मावा- इन्दौर 340, उज्जैन 280, रतलाम 275 रू. प्रति किलो।

इंदौर सर्राफा बाज़ार

इन्दौर। एजेंसी। स्थानीय सराफा बाजार में शुक्रवार को कारोबार की मात्रा अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन दोनों ही मूल्यवान धातुओं सोना और चांदी के भाव मजबूत रहे। बाजार में तेजी का रुख बना रहा। भाव इस प्रकार रहे-

चॉंदी (9999) 219000, चॉंदी (99) 218900, टंच 218200, सिक्का 2600, सोना 10 ग्राम 140700,

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई। एजेंसी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को भारतीय रुपया 19 पैसे की बढ़त के साथ ही 96.23 पर बंद हुआ। आज सुबह घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच रुपया शुरुआती कारोबार में 14 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.28 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि हालांकि, विदेशी पूंजी की भारी बिकवाली और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने स्थानीय मुद्रा की बढ़त को सीमित रखा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 96.35 प्रति डॉलर पर खुला।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 965 , निफ्टी भी 261 अंक उछला

मुम्बई। एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये तेजी दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के बाद भी खरीदारी हावी होने से आई है। आज दिग्गज कंपनी रिलायंस के शेयरों में भारी तेजी रही। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स अंत में 964.58 अंक बढ़कर 78,151.45 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 261.55 अंक ऊपर आकर 24,334.30 अंक पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी रिलायंस के शेयर में आई ओर से 1326.50 रुपये पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर तेजी के साथ बंद हुए। टेक महिंद्रा में सबसे ज्यादा उछाल आया। इसके अलावा कोटक महिंद्रा, टीसीएस, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस के शेयरों में भी भारी तेजी रही। दूसरी ओर, ट्रेंट, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिगो और एनटीपीसी के शेयरों में गिरावट रही।

इससे पहले आज सुबह तेजी के साथ खुला। सेंसेक्स ने 77,800 का स्तर पार करते हुए 627.98 अंक की बढ़त दर्ज की, जबकि निफ्टी 50 भी 166.55 अंक चढ़कर 24,239.30 के स्तर पर पहुंच गया। इस दमदार शुरुआत ने निवेशकों का उत्साह बढ़ाया।

त्योहारों से पहले महंगाई का वार, गेहूं और खाद्य तेलों के दाम बढ़े

नई दिल्ली। एजेंसी। त्योहारी सीजन से ठीक पहले आम आदमी की जेब पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। गेहूं और खाद्य तेलों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की आशंका है, जिससे रसोई का बजट बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के साथ-साथ घरेलू मौसम संबंधी चुनौतियां भी इस मूल्य वृद्धि को हवा दे रही हैं। पिछले एक माह में घरेलू बाजार में गेहूं के दाम 8 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुके हैं। काला सागर क्षेत्र में आपूर्ति जोखिमों और यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमलों के कारण वैश्विक बाजार में गेहूं के दाम उछले हैं, जिससे शिकागो वायदा दो महीने के उच्चतम स्तर पर है। इसका असर भारतीय मंडियों पर भी दिखा है, जहां इंदौर में 8.44 फीसदी, जबकि दिल्ली, कानपुर और कोटा में औसतन 3.5-4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू स्तर पर भी बढ़ता तापमान और बेमौसम बारिश गेहूं उत्पादन के अनुमान को घटा रहे हैं, जिससे भविष्य में कीमतें और बढ़ सकती हैं। खाद्य तेलों की कीमतों में भी तेजी आने की पूरी आशंका है। इस साल सोयाबीन की खेती में 6 फीसदी की कमी और अपर्याप्त बारिश से प्रति हेक्टेयर उत्पादन घटने की संभावना है। वैश्विक स्तर पर पाम तेल की कमी और बायोफ्यूल में इसके बढ़ते इस्तेमाल ने सोया व सूरजमुखी तेल को महंगा किया है। भारत ने फिलहाल आयात कम किया है, जो भविष्य में घरेलू स्टॉक पर दबाव बढ़ाएगा। कमजोर रुपया भी आयात लागत बढ़ा रहा है। अगस्त के पहले पखवाड़े से शुरू होने वाली त्योहारी मांग इन कीमतों को और ऊपर धकेल सकती है, जिससे उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा।

आयकर पोर्टल पर अब दिखेगी विदेशी आय-परिसंपत्ति की जानकारी

नई दिल्ली। एजेंसी। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है। अब वे अपने आयकर विवरणिका फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में विदेशी बैंक खाते, निवेश खाते और विदेशी कर प्राधिकरणों द्वारा भारत को साझा की गई कुछ विदेशी आय की जानकारी देख सकते हैं। इसका उद्देश्य करदाताओं को आयकर विवरणिका दाखिल करते समय विदेशी परिसंपत्तियों और आय की सही जानकारी देने में मदद करना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह सुविधा ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन (एईओआई) फ्रेमवर्क के तहत शुरू की है। इस वैश्विक ढांचे के तहत विभिन्न देश कर चोरी रोकने के लिए एक-दूसरे के साथ वित्तीय खातों की जानकारी साझा करते हैं। इस डेटा में विदेशी बैंक खाते, वित्तीय निवेश, ब्याज, लाभांश और विदेश में भारतीय टैक्स रेजिडेंट्स से जुड़ी अन्य वित्तीय आय शामिल हो सकती है। वर्तमान में, एआईएस में कैलेंडर वर्ष 2022, 2023 और 2024 से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। कैलेंडर ईयर 2025 की जानकारी इस साल सितंबर-अक्टूबर में उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि एआईएस में प्रदर्शित जानकारी वही है जो साझेदार देशों ने भारत के साथ साझा की है, और यह करदाताओं की विदेश में मौजूद सभी संपत्तियों या आय को नहीं दर्शा सकती है। इसलिए, यदि एआईएस में जानकारी नहीं भी दिखती है, तब भी करदाता शेड्यूल एफए में सभी विदेशी परिसंपत्तियों और शेड्यूल एफएसआई में सभी विदेशी आय की जानकारी देने के लिए जिम्मेदार होंगे।

मेष- आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा और नए उत्साह से भरपूर रहेगा। ससुराल पक्ष से किसी प्रिय व्यक्ति का आगमन रिश्तों में और मिठास घोल सकता है। किसी बात को लेकर माताजी से हल्की नाराजगी हो सकती है, लेकिन समय रहते बातचीत से स्थिति संभाल लेना बेहतर रहेगा। संतान को अच्छे संस्कार और पारिवारिक परंपराओं का महत्व समझाने का अवसर मिलेगा।

वृषभ- आज व्यापार और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाती नजर आएगी। किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या चर्चा में आपकी राय को विशेष महत्व मिलेगा, इसलिए आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें। प्रेम संबंधों में छोटी-सी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन समझदारी से स्थिति संभल जाएगी। वरिष्ठों और मित्रों का सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा।

मिथुन- आज किस्मत आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। आध्यात्मिक गतिविधियों और भगवान की भक्ति में मन लगेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। परिवार के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ने से थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। नए काम की शुरुआत और निवेश की योजना बनाने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपकी नेक नीयत हर किसी को समझ आए, यह जरूरी नहीं, इसलिए अपनी भावनाओं को संतुलित रखें।

कर्क- आज बेवजह के विवादों से दूरी बनाए रखना ही आपके हित में रहेगा। जो भी जिम्मेदारी मिले, उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएं। कार्यक्षेत्र में किसी जूनियर से गलती हो जाए, तो उसे डांटने के बजाय समझाना ज्यादा बेहतर रहेगा। पिछले कुछ समय से चली आ रही मानसिक चिंता अब धीरे-धीरे कम होती नजर आएगी। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो अनुभवी सलाहकार की राय लेना आपके लिए लाभदायक साबित होगा।

सिंह- आज नया घर, जमीन या संपत्ति खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है। हालांकि किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच-पड़ताल जरूर करें। करियर को लेकर जो चिंता आपको परेशान कर रही थी, उसमें अब राहत मिलने के संकेत हैं। परिवार के मुद्दों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करने से पहले उन्हें अच्छी तरह परख लेना चाहिए।

कन्या- आज निवेश से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी और उसी के दम पर सफलता भी मिलेगी। परिवार के किसी सदस्य के साथ काम को लेकर हल्की बहस हो सकती है। यदि स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं चल रहा है, तो लापरवाही बिल्कुल न करें। संतान की सफलता और तरक्की आपको गर्व और खुशी का एहसास कराएगी।

तुला- आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों चरम पर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके काम से अधिकारी प्रभावित होंगे और प्रमोशन को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है। महिला मित्रों के साथ बातचीत में मर्यादा और संयम बनाए रखें। मनमर्जी के खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर खर्च करें। जीवनसाथी की ओर से कोई प्यारा-सा सरप्राइज मिल सकता है। माता-पिता से बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें।

वृश्चिक- आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं रहेगा। जिद और अहंकार से दूरी बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में कोई विरोधी आपके खिलाफ गलत माहौल बनाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपनी बात पूरे आत्मविश्वास और तथ्यों के साथ रखें। विद्यार्थियों को पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

धनु- आज नए लोगों से बनने वाले संपर्क भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। आप सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी सक्रियता भी बढ़ेगी। किसी सरकारी योजना में निवेश करने का विचार लाभ दे सकता है, लेकिन किसी भी शुभ समाचार पर तुरंत निर्णय लेने से बचें। अपने जरूरी काम समय पर पूरे करें, क्योंकि टालमटोल आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकती है।

मकर- आज मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। आपकी कोई पुरानी गलती सामने आ सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से स्थिति संभालें। बिना मांगे सलाह देने या दूसरों की हर बात मान लेने से बचें। यदि किसी को उधार दिया हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद थी, तो उससे जुड़ी कोई चर्चा हो सकती है।

कुंभ- आज का दिन आत्मविश्वास और नई ऊर्जा लेकर आएगा। आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। तनाव कम करने के आपके प्रयास सफल रहेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी परेशानियों को हल्के में न लें। धन से जुड़ा कोई रुका हुआ काम पूरा होने से राहत मिलेगी।

मीन- रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आया है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी से ऐसी बात न कहें जिससे रिश्तों में कड़वाहट आए। खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए बजट बनाकर चलना जरूरी होगा। विदेश से जुड़े व्यापार या कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है।

शब्दजाल - 8323

शब्दजाल में प्राण की दस फिल्मों के नाम ढूंढिए. नाम उपर से नीचे व तिरछे हो सकते हैं.

उपकार, शराबी, नसीब, हीर रांझा, आदमी, जंजीर, कुर्बानी, धर्मा, गंगा की सौगंध, राम और श्याम

आ	ल	र	ही	दा	उ	प	का	र	झ	आ
ज	द	ल	र	आ	क	ह	ब्ब	तें	शा	रा
अं	इ	मी	रां	ल	दा	ल	न	र	ला	म
जं	कु	अ	झा	बे	ला	क	सी	रि	श	औ
जी	ति	श	ने	व	द	स	ब	ग	वी	र
र	रं	गं	गा	की	सौ	गं	ध	ती	प	श्या
जो	गा	ध	र्मा	गा	प	म	र	कौ	या	म
श	बा	जीं	स	त	क	छ	श	ग	श	थ
म	स	मि	न	व	न	ज	म	रा	जू	द
द	र	ल	म	ह	र	औ	के	स	बी	ना
थो	कु	र्बा	नी	र	हो	ग	या	दु	र	क

शब्दजाल - 8322 का हल

मु	हु	मे	रि	ह	आ	ल	म	आ	रा	म
ग	खु	क	दू	म	जी	ने	शि	या	इ	द
ले	पी	जा	क	दि	ग	बा	द	ह	प	र
आ	ग	ए	रा	ल	दे	व	दा	स	लि	इं
ज	आ	रा	ल	दे	ब्लै	ला	कि	यो	प	डि
म	इ	वा	मो	चु	प	क	शी	ह	गी	या
न	अ	ल	रा	के	मा	जो	न	व	प	क्ति
क	रि	ल	र	स	र	प्या	सा	ल	वि	रे
र	या	बा	बे	न	न	ज	जी	व	जू	ड्डी
र	ग	ल	नो	म	व	शि	का	री	क्त	ल
बां	दो	बी	घा	ज	मी	न	स	सु	रा	ल

Jagrutidaur.com, Bangalore

फिल्म वर्ग पहेली- 7267

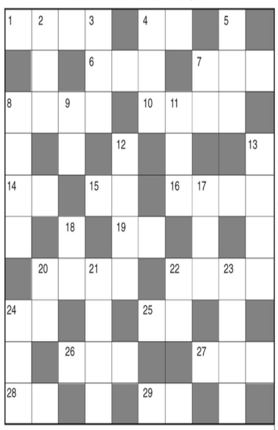

बायें से दायें:-

१. सैफ, चंद्रचूड़, प्रीति की 'इसे खेल ना समझो' गीत वाली फिल्म-१,३
४. 'एक लड़की जिसके' गीत वाली संजय दत्त, जैकी, रवीना की फिल्म-२
६. गोविंदा, रवीना टंडन की 'सासूजी थारो लल्ला' गीत वाली फिल्म-३
७. 'हम दिल दे चुके सनम' में सलमान की माँ की भूमिका किसने की थी-३
८. ऋषि कपूर, जूही चावला वाली फिल्म 'दरार' में सहनायक कौन था-४
१०. 'रंग दे रंग दे' गीत वाली फिल्म 'तक्षक' के संगीत निर्देशक कौन हैं-४
१४. राजकुमार, जीतेंद्र की फिल्म 'मेरे हुजूर' की नायिका कौन थी-२
१५. 'दिल है तुम्हारा' में अर्जुन रामपाल के किरदार का क्या नाम है-२
१६. राजेंद्रकुमार, बी. सरोजादेवी की 'जाना तुम्हारे प्यार में' गीत वाली फिल्म-४
१९. 'इस टूटे दिल' गीत वाली अनिल, अक्षय, ऐश्वर्या की फिल्म-२
२०. अक्षयकुमार, करिश्मा की 'माथे पे चमके इसके' गीत वाली फिल्म-४
२२. 'सोला किये थे' गीत वाली मिथुन, शिल्पा शिरोडकर की फिल्म-४
२४. आमिर खान, माधुरी की 'मुझे नींद न आये' गीत वाली फिल्म-२
२५. नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, कुमार गौरव, जावेद, जूही की फिल्म-२
२६. राजकपूर, दिलीपकुमार की 'उठाये जा उनके' गीत वाली फिल्म-३
२७. 'ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम' गीत वाली फिल्म-३
२८. राजेंद्रकुमार, माला सिन्हा की 'जिसके सपने हमें रोज' गीत वाली फिल्म-२
२९. 'जाने क्या होगा रामा रे' गीत वाली फिल्म-२

ऊपर से नीचे:-

२. आफताब, लिसा रे की 'कितना बेचैन हो के' गीत वाली फिल्म-३
३. 'तेरे बिना मैं कुछ' गीत वाली मिथुन, अतुल अग्निहोत्री, पूजा भट्ट की फिल्म-३
४. अमिताभ, जया भादुड़ी की 'यारी है ईमान मेरा' गीत वाली फिल्म-३
५. 'बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया' गीत वाली सुनीलदत्त, नूतन की फिल्म-३
७. फिल्म 'रजिया सुल्तान' में शीर्षक भूमिका किसने की थी-२
८. अमिताभ, जया भादुड़ी की 'मीत ना मिला रे मन का' गीत वाली फिल्म-४
९. संजय दत्त, इंद्रकुमार, मनीषा की फिल्म-२
११. शॉवर अली, तरूण अरोड़ा, मेघना की 'तेरी चाहत में' गीत वाली फिल्म-३
१२. राजेश खन्ना, शबाना की 'चलो बुलावा आया है' गीत वाली फिल्म-४
१३. सनी, रजनीकांत, श्रीदेवी की फिल्म-४
१७. अजय, अक्षय, करिश्मा, नगमा की 'शाबा ये नखरा' गीत वाली फिल्म-३
१८. 'ये मेरा दिल यार का दीवाना' गीत वाली अमिताभ, जीनत की फिल्म-२
२०. सनी, तब्बू, रीमा सेन की फिल्म-२
२१. 'दिल का तोहफा लाई हूँ' गीत वाली फिल्म-४
२२. आयशा, दिव्या भारती, कमल सदाना की 'तेरी मुहब्बत' गीत वाली फिल्म-२
२३. 'ये काली काली आँखें' गीत वाली फिल्म-४
२४. सनी, बॉबी, उर्मिला की फिल्म-३

फिल्म वर्ग पहेली- 7266

गु	रू		खा	मो	शी		आ	स	रा
रू		फ	न		बा	द	शा	ह	
दे	वी		दा	ग		स्त		र	न
व	र	दा	न		म	क	ड़ी		ती
	ता			फॉ	सी			रा	जा
आ		स	जा		हा	र	जी	त	
शि	का	र		आ		क्ष		औ	
क		ग	ब	न		क	ह	र	
	धू	म		बा	जी			दि	ल
पा	प		जी	न	त		डॉ	न	

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

18 जुलाई 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति	लग्नारंभ समय	
सूर्य	कर्क में	कर्क	05.19 बजे से
चंद्र	सिंह में	सिंह	07.39 बजे से
मंगल	वृष में	कन्या	09.51 बजे से
बुध	मिथुन में	तुला	12.02 बजे से
गुरू	कर्क में	वृश्चिक	14.16 ब.से
शुक्र	सिंह में	धनु	16.32 बजे से
शनि	मीन में	मकर	18.37 बजे से
राहु	कुंभ में	कुंभ	20.24 बजे से
केतु	सिंह में	मीन	21.57 बजे से
		मेष	23.27 बजे से
		वृष	01.07 बजे से
		मिथुन	03.05 बजे से

राहुकाल 9.00 से 10.30 बजे तक

शनिवार 2026 वर्ष का 199 वा दिन
दिशाशूल पूर्व **ऋतु** वर्षा।
विक्रम संवत् 2083 **शक संवत्** 1948
मास आषाढ़ **पक्ष** शुक्ल
तिथि पंचमी 03.43 बजे प्रातः को समाप्त।
नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी 18.01 बजे को समाप्त।
योग वरीयान 20.46 बजे को समाप्त।
करण बव 16.08 बजे तदनन्तर बालव 03.43 बजे प्रातः को समाप्त।
चन्द्रायु 3.6 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 21° 03'
सूर्य दक्षिणायन
कलि अहर्गण 1872774
जूलियन दिन 2461239.5
कलियुग संवत् 5128
कल्पारंभ संवत् 1972949128
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885128
वीरनिर्वाण संवत् 2552
हिजरी सन् 1448
महीना सफर **तारीख** 03

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
काल	05.55 से	07.23 बजे तक	लाभ	05.37 से	07.10 बजे तक
शुभ	07.23 से	08.51 बजे तक	उद्वेग	07.10 से	08.42 बजे तक
रोग	08.51 से	10.19 बजे तक	शुभ	08.42 से	10.14 बजे तक
उद्वेग	10.19 से	11.46 बजे तक	अमृत	10.14 से	11.47 बजे तक
चर	11.46 से	01.14 बजे तक	चर	11.47 से	01.19 बजे तक
लाभ	01.14 से	02.42 बजे तक	रोग	01.19 से	02.51 बजे तक
अमृत	02.42 से	04.10 बजे तक	काल	02.51 से	04.23 बजे तक
काल	04.10 से	05.37 बजे तक	लाभ	04.23 से	05.56 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

प्रसंगतः अद्भुत मांग

प्रख्यात संत बाबा गुलाब चंद अघोरी अपने अद्भुत चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके चमत्कार देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते थे। लोगों को लगातार चमत्कार दिखाते-दिखाते बाबा ने उनमें महारत हासिल कर ली। इससे उनमें अभिमान आ गया। उन्हें अहसास हो गया कि वह कुछ भी कर सकते हैं। वह जिन लोगों से मिलते, अपने चमत्कारों या अपनी सिद्धियों की चर्चा जरूर करते। एक दिन बाबा गुलाब चंद संत साहित्य के लेखक सुदर्शन सिंह 'चक्र' की एक कविता पढ़कर गदगद हो उठे। चक्र जी की कविता से बेहद प्रभावित होकर उन्होंने उनसे कहा, 'आज तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। मांगो, दिल खोलकर मांगो।' बाबा की बात पर चक्र जी बोले, 'नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं भगवान की भक्ति तथा साहित्य की साधना करता रहूं, यही मेरी आकांक्षा है।' चक्र जी के यह कहने पर भी बाबा बार-बार उनसे आग्रह करते रहे और बोले, 'आज मैं अपनी ओर से पहली बार आग्रह कर रहा हूं। नहीं मांगोगे तो बाद में पछताओगे।' यह सुनकर चक्र जी ने कहा, 'बाबा मैं जो मांगूंगा, उसे आप दे भी पाओगे या नहीं, पहले यह विचार कर लीजिए।' इस पर बाबा बोले, 'नहीं, तुम जो मांगोगे वह अवश्य मिलेगा, मैं तुमसे वादा करता हूं।' इसके बाद चक्र जी बोले, 'बाबा, तो आप यह आशीर्वाद दीजिए कि भारत में जितने रोगी हैं वे सब निरोगी हो जाएं, जो दरिद्र हैं वे दरिद्र न रहें।' चक्र जी की अद्भुत मांग सुनकर बाबा हैरान हो गए और फूट-फूट कर रोने लगे। वह चक्र जी के सामने नतमस्तक होकर बोले, 'आज तुमने मेरा अभिमान नष्ट कर दिया। आज मुझे यह पता चल गया है कि मनुष्य सभी कुछ करने की क्षमता नहीं प्राप्त कर सकता। चाहे वह कितनी ही सिद्धियां प्राप्त कर ले, वह अक्षम ही रहेगा। सर्व सक्षम तो केवल ईश्वर है।' बाबा की बात सुनकर चक्र जी वहां से चले गए।

सूडोकु नवताल- 7576

★★★★☆ कठिन

4					1	9		
						8	5	
			7	3				
			3				4	7
9								2
8	5				6			
				5	8			
	7	4						
		6	2					5

Jagrutidaur.com, Bangalore

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
■ पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7575 का हल

2	4	5	6	9	8	1	7	3
1	7	6	4	3	5	8	2	9
3	8	9	1	2	7	6	5	4
9	1	7	3	6	2	4	8	5
5	6	3	8	7	4	9	1	2
4	2	8	5	1	9	3	6	7
7	3	1	9	5	6	2	4	8
8	9	2	7	4	1	5	3	6
6	5	4	2	8	3	7	9	1

शब्द पहेली - 8791

बाएँ से दाएँ

1. शमशीर, कृपाण-4
4. उपद्रवी, आतंकी-4
6. अनुबंध, संधि-3
8. धोखा, छल, मक्कारी-3
9. चांदी-3
11. अश्रु-2
13. नीचता-5
15. कुंजी, जिससे ताला खोलते हैं-2
16. पुराना जुकाम-3
18. प्रश्न-3
19. चांदी-3
20. जहां ताजिये दफन किए जाते हैं-4
22. बोरिया-बिस्तर-4

ऊपर से नीचे

1. झगड़ा, कहासुनी-4
2. संगीत यंत्र-2
3. बहुत बड़ा, विशाल-3
4. अपनत्व, अपनापा-5
5. अनबन, झगड़ा-4
7. कपड़े धोनेवाला-3
10. तहजीबदार-5
12. अकस्मात, सहसा-4
14. दृष्टि, निगाह-3
17. बेमिसाल, अनूठा-4
18. बलवान-3
21. उम्मीद, आशा-2

शब्द पहेली -8790 का हल

आ	म	रा	य		सा	व	धा	न
रा		ह	म	स	फ	र		फ
ध	न			ली			का	र
ना	क		ना	का	रा		न	त
	ब	हा	र		श	र	भ	
खो	ज		द	ह	न		र	म
फ	न			र			ना	न
ना		स	र	फ	रो	श		व
क	र	त	ब		ना	मा	व	ली

Jagrutidaur.com, Bangalore

बहेला की छोटी बाघ नदी पर बने केटीवेयर पुल में फंसी झांड़ियां बन सकती है बाढ़ का कारण

पद्मेश न्यूज। लांजी।

आपदा कभी अचानक नहीं आती, उसकी आहट पहले से दिखाई देती है। बहेला की छोटी बाघ नदी पर बने केटीवेयर पुल की मौजूदा तस्वीर भी कुछ ऐसी ही चेतावनी दे रही है। बाढ़ का पानी उतर चुका है, नदी सामान्य बहाव में लौट आई है, लेकिन पुल के गेट में फंसी लकडियां, बांस, झाड़.झंखाड़ और भारी मलबा अब भी पानी के रास्ते पर दीवार बनकर खड़ा है। हैरत की बात यह है कि प्रशासन के पास सफाई कराने का सबसे अनुकूल समय होने के बावजूद जिम्मेदार विभागों ने अब तक कोई पहल नहीं की। यदि यही स्थिति अगली तेज बारिश तक बनी रही तो बहेला क्षेत्र को एक बार फिर उसी संकट से गुजरना पड़ सकता है, जिसे हर वर्ष प्राकृतिक आपदा कहकर टाल दिया जाता है। महाराष्ट्र सीमा से लगे बहेला क्षेत्र में छोटी बाघ नदी पर निर्मित केटीवेयर पुल वर्षो से बाढ़ के समय बड़ी चुनौती बनता रहा है। बारिश के दौरान नदी में बहकर आने वाली लकडियां, बांस, झाडियां और अन्य मलबा पुल के गेट में फंस जाता है, जिससे पानी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो जाता है। परिणामस्वरूप नदी का पानी वापस उफान लेकर निचले इलाकों में फैलने लगता है और बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो जाते हैं।

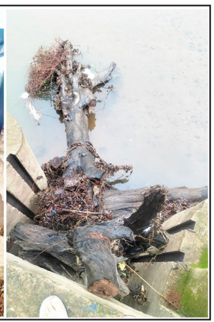

प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगतते हैं ग्रामीण.

इस वर्ष आई बाढ़ के दौरान भी यही स्थिति बनी थी। अब जबकि जलस्तर काफी नीचे आ चुका है और पुल की सफाई बिना किसी जोखिम के कराई जा सकती है, तब भी संबंधित विभागों की निष्क्रियता समझ से परे है। पुल में फंसा मलबा आज भी जस का तस पड़ा हुआ है, मानो अगली बारिश का इंतजार कर रहा हो। ग्रामीणों का कहना है कि यदि हर वर्ष बाढ़ के बाद इसी अवधि में पुल की नियमित सफाई और रखरखाव सुनिश्चित कर दिया जाए तो पानी की निकासी निर्बाध बनी रहेगी और बहेला क्षेत्र में बाढ़ का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन हर साल यही लापरवाही दोहराई जाती है और नुकसान झेलते हैं आम नागरिक। अब क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और जल संसाधन विभाग से मांग की है कि मानसून के अगले दौर से पहले युद्धस्तर पर पुल में फंसे मलबे को हटाया जाए। साथ ही ऐसी तकनीकी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे भविष्य में बहकर आने वाला मलबा गेट में न अटके और नदी का प्राकृतिक बहाव बाधित न हो।

आज भी पानी के प्रवाह में बाधा बना मलबा.

इस वर्ष आई बाढ़ के दौरान भी बड़ी मात्रा में लकडियां, बांस, झाडियां और अन्य मलबा पुल के गेट में आकर अटक गया था। अब जबकि नदी का जलस्तर काफी कम हो चुका है और सफाई कार्य कराने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, तब भी संबंधित विभागों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। पुल में फंसा यह मलबा आज भी पानी के प्रवाह में बाधा बना हुआ है और यही स्थिति अगली बारिश में बड़े संकट का कारण बन सकती है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रशासन हर वर्ष बाढ़ आने के बाद राहत और बचाव की कवायद तो करता है, लेकिन बाढ़ के प्रमुख कारणों को दूर करने के लिए समय रहते कोई प्रभावी कदम नहीं उठाता। यदि जलस्तर कम होने के दौरान ही पुल की सफाई कर दी जाए तो आगामी बारिश में पानी का बहाव निर्बाध रहेगा और बाढ़ की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है। इसके विपरीत यदि यह मलबा यथावत पड़ा रहा तो तेज बारिश के दौरान पानी की निकासी बाधित होगी और एक बार फिर बहेला सहित आसपास के निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है।

श्रावण मास के 30 दिनों में 30 गांवों में होगा अखण्ड श्रीरामचरित मानस पाठ

पद्मेश न्यूज। लांजी। श्रावण मास के पावन अवसर पर लांजी एवं किरनापुर क्षेत्र के 30 गांवों में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 29 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक अखण्ड श्रीरामचरित मानस पाठ एवं भारतीय संस्कृति के आधारभूत मूल्यों पर आधारित विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान पूरे श्रावण मास तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक गांव में दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों की सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ 29 जुलाई से 30 जुलाई तक देवरबेली से होगा। इसके बाद क्रमश: कलपाथरी, थानेगांव, सुलसुली, घोटी, नेवरवाही, कोसमारा, पीपलगांव, टेमनी, मोहारा, बोरगांव, पल्हेरा, किन्ही, मुंडेसरा, बिनोरा, कोकना, कान्द्रीकला, सावरीकला, देवलगांव, कारंजा, साडरा, कुम्हारीकला, पालडोंगरी, बड़गांव-म, बहेला, सावरीखुर्द, मोहझरी, टेंडवा, भिमोड़ी एवं दुलापुर ग्रामों में क्रमवार आयोजन किए जाएंगे। आयोजन समिति ने बताया कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में कार्यक्रम की तिथियों में आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य श्रीरामचरित मानस के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक जागृति लाने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों का प्रचार-प्रसार करना है। इसके साथ ही सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता तथा युवाओं के मार्गदर्शन से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के प्रथम दिवस की शुरुआत प्रात: 6 बजे योग, प्राणायाम एवं ध्यान से होगी। इसके बाद नगर संकीर्तन यात्रा निकाली जाएगी तथा गांव के मंदिरों में पूजन-अर्चन एवं ध्वज स्थापना के साथ अखण्ड श्रीरामचरित मानस पाठ का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थियों एवं युवाओं के लिए शिक्षा, करियर, परिवार संस्कार तथा पुलिस एवं सेना भर्ती संबंधी मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। द्वितीय दिवस पर महिला मंडलों के सहयोग से गांव के 25 चयनित स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर, दवा वितरण, मोतियाबिंद जांच एवं चयनित मरीजों के ऑपरेशन की व्यवस्था रहेगी। दुर्घटनाओं में हाथ या पैर गंवा चुके दिव्यांगजनों का कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए चयन भी किया जाएगा। इसके पश्चात हवन-यज्ञ, गौपूजन एवं नौकन्या पूजन संपन्न होगा तथा शाम को मानस प्रसादम (भोजन) का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर धार्मिक अनुष्ठान एवं सामाजिक सेवा गतिविधियों का लाभ उठाने तथा तन, मन, धन एवं अन्न से सहयोग प्रदान कर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ-साथ समाज में सेवा, संस्कार, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश देने का भी माध्यम बनेगा। कार्यक्रम का आयोजन समस्त ग्रामवासी एवं ग्राम समितियों द्वारा किया जा रहा है। अभिनंदन लाइफ फाउंडेशन सेवा सहयोग प्रदान कर रहा है, जबकि एकल अभियान संच लांजी के अध्यक्ष झनकार किरनापुरे कार्यक्रम के संयोजक हैं।

वन स्टॉप सेंटर की पहल से दो परिवारों में लौटी खुशियां, परामर्श से सुलझे पारिवारिक विवाद

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेन्द्र कुमार सुंदरियाल के मार्गदर्शन में संचालित वन स्टॉप सेंटर, बालाघाट एवं बैहर ने प्रभावी काउंसलिंग और सतत फॉलो-अप के माध्यम से दो परिवारों के लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवादों का सफल समाधान कराया। केंद्र द्वारा महिलाओं को कानूनी, मनोसामाजिक एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ संवाद के जरिए टूटते रिश्तों को जोड़ने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है।

वन स्टॉप सेंटर प्रशासक सुश्री रचना चौधरी ने बताया कि पहले प्रकरण में 35 वर्ष पुराने वैवाहिक संबंध में उत्पन्न विवाद को वन स्टॉप सेंटर की परामर्शदाता द्वारा लगातार काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाया गया। परामर्श के दौरान पति ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए परिवार के साथ पुन: रहने का निर्णय लिया, जबकि पत्नी ने भी रिश्ते को एक और अवसर देने की सहमति जताई। वहीं दूसरे प्रकरण में दहेज प्रताड़ना एवं घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायत पर दोनों पक्षों की अलग-अलग एवं संयुक्त काउंसलिंग की गई। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देने और लगातार समझाइश के बाद ससुराल पक्ष ने अपने व्यवहार में सुधार का आश्वासन देते हुए पीड़िता से क्षमा मांगी और आपसी सम्मान के साथ जीवन शुरू करने का संकल्प लिया।

वन स्टॉप सेंटर की इस पहल से दोनों परिवारों में पुन: विश्वास और सौहार्द का वातावरण बना। विभाग का कहना है कि केंद्र का उद्देश्य केवल संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि जहां संभव हो, संवाद, विश्वास और सकारात्मक परामर्श के माध्यम से परिवारों को पुन: जोड़कर समाज में स्वस्थ एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना भी है।

लांजी की बेटी डॉ. पुष्पारानी बड़घैया को कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी की उपाधि

पद्मेश न्यूज। लांजी। लांजी क्षेत्र की प्रथम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की संस्थापक परिवार से जुड़ी डॉ. पुष्पारानी बड़घैया को कंप्यूटर विज्ञान विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। इस उपलब्धि पर क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। आईएसबीएम विश्वविद्यालय, नवापारा कोसमी, तहसील छुरा, जिला गरियाबंद (छत्तीसगढ़) द्वारा पुष्पारानी बड़घैया को शोध प्रबंध सिंथेटिक एपर्चर रडार छवियों का सुपर-रिजॉल्यूशन: संशोधित सीएनएन तथा रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट-6 पर आधारित डीप लर्निंग का उपयोग विषय पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की उपाधि प्रदान की गई। पुष्पारानी बड़घैया लांजी क्षेत्र के गांव कोचेवाही की निवासी हैं तथा वर्तमान में बालाघाट में रह रही हैं। वे सहायक प्राध्यापक डॉ. ताराचंद बड़घैया (रसायन शास्त्र) की धर्मपत्नी हैं। उन्होंने अपना शोध कार्य डॉ. आभा ताम्रकार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कंप्यूटर विज्ञान विभाग, आईएसबीएम विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में पूरा किया।

शिक्षा और योगदान

पुष्पारानी बड़घैया ग्राम खजरी, लांजी की निवासी तथा श्रीमती कांतीदेवी लक्ष्मीचंद कर्राहे की सुपुत्री हैं। उनके परिवार ने लांजी क्षेत्र को पहला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय श्री लक्ष्मीकांता कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना का अनमोल उपहार दिया है। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा हैदराबाद से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से प्राप्त की। बचपन से ही शिक्षा के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने अपनी मेहनत और योग्यता से यह उपलब्धि हासिल की है। वर्तमान में वे विद्यार्थियों को निरंतर मार्गदर्शन दे रही हैं तथा शिक्षा के प्रसार में सक्रिय योगदान दे रही हैं।

सफलता का श्रेय परिवार को

इस उपलब्धि पर डॉ. पुष्पारानी बड़घैया ने अपने परिजनों, गुरुजनों और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया है।

बधाई और शुभकामनाएं

इस खुशी के अवसर पर आईएसबीएम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आनंद महालवार, कुलसचिव डॉ. बी.पी. भोल, डीन (अकादमी) डॉ. एन.के. स्वामी, पीएचडी सेल प्रभारी डॉ. राकेश तिवारी, रिसर्च कोऑर्डिनेटर श्रीमती स्वाति शर्मा, लांजी-किरनापुर विधायक राजकुमार कर्राहे, लक्ष्मीकांता कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के संचालन समिति, प्राचार्य तथा समस्त स्टॉफ ने हार्दिक बधाई दी है। परिवार के सदस्यों श्रीमती कांतीदेवी लक्ष्मीचंद कर्राहे, श्रीमती शुगन खेमचंद कर्राहे, लखाराम बड़घैया, सी.एल. बड़घैया, श्रीमती ममताचंद, डॉ. लक्ष्मीचंद (प्राचार्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस), सुकचंद बड़घैया, रामचंद बड़घैया, गुलाबचंद बड़घैया, प्रेमचंद बड़घैया, डॉ. ताराचंद बड़घैया, श्रीमती गुड़िया किशोर कुमार कर्राहे, श्रीमती घटा श्रीराम कर्राहे, श्रीमती उषारानी गजानंद बड़घैया, श्रीमती हीरा दिगंबर बड़घैया, श्रीमती लक्ष्मीदेवी निरंजन देवगड़े, मुकेश कर्राहे, सुरेश कर्राहे, हरिराम कर्राहे, आरव, आरल बड़घैया सहित सभी मित्रगण, शुभचिंतक और विद्यार्थियों ने भी डॉ. पुष्पारानी बड़घैया को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

मध्यप्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ ने अपनी लंबित विभिन्न मांगों का विधायक को सौंपा ज्ञापन

पद्मेश न्यूज। किरनापुर। मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ तहसील शाखा किरनापुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 109 लांजी विधानसभा के विधायक राजकुमार कर्राहे से उनके निवास स्थान पर भेंट कर उन्हें अपनी विभिन्न लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण करवाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान संघ के अध्यक्ष अचरित ने बताया कि प्रदेश के कोटवार शासन के राजस्व, कानून व्यवस्था, निर्वाचन, जनगणना, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन तथा अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों का वर्षों से निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे है। इसके बावजूद उनकी अनेक न्यायोचित एवं लंबित मांगों का आज तक निराकरण नहीं हो पाया है। जिनमे 24सितम्बर 2023 की घोषणा के अनुसार प्रदेश के सभी कोटवारों को सीयूजी सिम उपलब्ध कराने तथा उसका रिचार्ज शासन द्वारा कराने की घोषणा की गई थी। इस आदेश का पूर्ण पालन नहीं किया गया है जिससे कोटवारो को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा हैं। कोटवारों को शासन द्वारा सिलवाई हुई वर्दी का कपड़ा न देकर उनके बैंक खातों में राशि भेजी जाए ताकि गुणवत्ता पूर्ण वर्दी बनवाई जा सके। कोटवारों को दी जा रही राशि से उनके परिवार का भरण पोषण नही हो पा रहा है, सरकार से निवेदन करते हुए मानदेय की राशि दुगुनी किए जाने का आग्रह किया गया है। इस दौरान अपनी मांगों के सम्बन्ध मे विधायक राजकुमार कर्राहे जी को ज्ञापन सौंपे जाने के अवसर पर संगठन के साथी राजू मेश्राम,संतोष बारमाठे,विजय बोरकर तहसील अध्यक्ष किरनापुर अचरित गेडाम,रंजीत हुमनकर सहित अन्य साथियों की उपस्थिति रही।

श्रावण मास में दादा कोटेश्वर धाम लांजी में होगा संगीतमय शिव नाम जप एवं पार्थिव शिवलिंग निर्माण

पद्मेश न्यूज। लांजी। श्रावण मास के पावन अवसर पर दादा कोटेश्वर धाम, लांजी में 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक एक माह का विशेष धार्मिक आयोजन किया जाएगा। आयोजन के दौरान प्रतिदिन ओंम नम: शिवाय नाम जप संगीतमय संकीर्तन, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक एवं महाआरती का आयोजन होगा।

आयोजन समिति के अनुसार प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक संगीतमय शिव नाम जप एवं संकीर्तन, दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक पार्थिव शिवलिंग निर्माण तथा शाम 4:00 बजे से रुद्राभिषेक एवं महाआरती संपन्न होगी।

श्रावण मास के इस विशेष धार्मिक अनुष्ठान में क्षेत्र के श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर भगवान शिव की आराधना का लाभ लेने की अपील आयोजन समिति ने की गई है।

लांजी में "पद्मेश"

इंटरनेट (ब्राडबेंड) कनेक्शन के लिये संपर्क करें

Mo. 8319969927

वन परिक्षेत्र हट्टा (सामान्य)द्वारा पैंगोलिन का रेस्क्यू

पद्मेश न्यूज। हट्टा। आज दिनांक 17 जुलाई 2026 को रात्रि लगभग 12.30 बजे ग्राम पारसपानी के निवासी प्रशांत चौधरी की सूचना के आधार पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन मै वन परिक्षेत्र हट्टा सामान्य के अधिकारी एवं कर्मचारी उसके निवास पर पहुंचे जहां एक विलुप्त प्राय: वन्य जीव पैंगोलिन उसके घर पर भटककर आ गया था। जिसे वन विभाग के द्वारा सुरक्षित रूप रेस्क्यू कर वन परिक्षेत्र कार्यालय हट्टा लेकर आए,एवं श्रीमान उपवनमण्डलाधिकारी बालाघाट (सा.) एवं सुरेंद्र कुमार शेंडे परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा सा. की उपस्थिति में उक्त वन्य जीव पेंगोलीन की पशु चिकित्सक डॉ दार्मेंद्र गौतम पशु चिकित्सा अधिकारी हट्टा द्वारा उक्त वन्य जीव का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, उसके पश्चात् वन्य प्राणी पैंगोलिन को मानव व्यवधान रहित आरक्षित वन क्षेत्र में सुरक्षित रूप से छोड़ा गया। उक्त कार्यवाही में हट्टा परिक्षेत्र के कर्मचारी तिलक उइके,वीरेंद्र कुमार बुरे, दिलीप सोनेकर, नितिन कुमार ,कमलेश,राहुल, रामसखा,का सराहनीय योगदान रहा ।

कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

राज परिवार के महाराज गोविंद देव ने घनश्याम सिंह के खिलाफ कलेक्टर से की शिकायत

भोपाल। मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने यहां की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दतिया राज परिवार के महाराज गोविंद देव ने कांग्रेस प्रत्याशी कुंअर घनश्याम सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दतिया कलेक्टर को एक शिकायती पत्र सौंपा है। इस शिकायत के बाद से ही चुनावी मैदान में आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार उन्होंने बताया कि उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुंअर घनश्याम सिंह ने नामांकन के दौरान निर्वाचन विभाग को जो भी जानकारियां सौंपी हैं, वे सरासर गलत और भ्रामक हैं। इसी को आधार बनाकर उन्होंने आज दतिया कलेक्टर को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। महाराज गोविंद देव ने यह भी

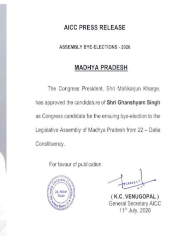

AICC PRESS RELEASE

ASSEMBLY BYE-ELECTIONS - 2026

MADHYA PRADESH

The Congress President, Shri Mallikarjun Kharge, has approved the candidature of **Shri Ghanshyam Singh** as Congress candidate for the ensuing bye-election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh from 22 – Datia Constituency.

For favour of publication.

(K.C. VENUGOPAL)
General Secretary AICC
11th July, 2026

स्पष्ट किया कि वे इस मामले की शिकायत तत्काल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से भी करेंगे। इस पूरे मामले पर अभी रहस्य बना हुआ है। जब महाराज गोविंद देव से सवाल किया गया कि आखिर इस शिकायत के पीछे का मुख्य मुद्दा क्या है और वे क्या खुलासा करने वाले हैं, तो वे फिलहाल इन तीखे सवालों से बचते नजर आए। हालांकि, उन्होंने ऐलान किया है कि वे जल्द ही एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया के सामने इस पूरे मामले का बड़ा पर्दाफाश करेंगे।

क्या है विवाद की मुख्य वजह?

राजनीतिक गलियारों और सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, यह पूरा विवाद राज परिवार की रियासत और संपत्ति के बंटवारे की पुख्ता जानकारियों को छिपाने या गलत तरीके से पेश करने से जुड़ा हो सकता है। माना जा रहा है कि संपत्ति के इसी ब्यौरे को लेकर महाराज गोविंद देव ने कलेक्टर तक अपनी शिकायत पहुंचाई है। उपचुनाव के मुहाने पर खड़े दतिया में इस नई शिकायत ने चुनावी समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या चुनाव आयोग और प्रशासन महाराजा गोविंद देव की इस शिकायत को संज्ञान में लेता है? और क्या यह नया विवाद कांग्रेस प्रत्याशी कुंअर घनश्याम सिंह के लिए चुनावी रण में बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला साबित होगा? यह आने वाले समय में साफ हो पाएगा।

दतिया उपचुनाव के मैदान में 21 प्रत्याशी

- 22वें नंबर पर होगा नोटा; वोटिंग के लिए 582 ईवीएम लगेंगी
- प्रत्याशी ज्यादा होने से हर पोलिंग बूथ पर 2-2 ईवीएम लगेंगी

भोपाल। दतिया उपचुनाव में 21 प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापिसी लेने की प्रक्रिया 16 जुलाई को पूरी हो गई। इस दौरान तीन ने अपने नाम वापिस लिए हैं। इस तरह नामांकन जांच के बाद शेष बचे 24 में से 21 उम्मीदवार ही चुनावी रण में किस्मत आजमाएंगे।

जिन तीन प्रत्याशियों ने नाम वापिस लिए हैं, उनमें केशव यादव निर्दलीय, मेहरबान राष्ट्रीय समाज पक्ष, शदाबुद्दीन निर्दलीय शामिल हैं। इधर चुनाव मैदान में शेष रहे उम्मीदवारों को संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग आफीसरों द्वारा चुनाव चिंह आबंटित कर दिए गए हैं। जिले में 30 जुलाई को सुबह सात बजे से सांय छह बजे तक मतदान होगा। चुनाव मैदान में शेष बचे उम्मीदवारों में आशुतोष तिवारी भाजपा, घनश्याम सिंह कांग्रेस, दामोदर सिंह यादव आजाद समाज पार्टी (कांशीराम), बालकिशन विश्वकर्मा परिवर्तन पार्टी

आफ इंडिया, वेदराम कुर्मी निर्दलीय, डा.राखी बाला सिंगारे राष्ट्रीय समाधान पार्टी, जितेंद्र मेहरा आपका गणतंत्र पार्टी, हंसमुखी लोधी निर्दलीय, बृजेंद्र निर्दलीय, सुरेश अहिरवार निर्दलीय, शुभम राजपूत भारतीय सभ्यता पार्टी, संजना सिंह भारतीय गणवार्ता पार्टी, देवेश परिहार आजाद क्रांति पार्टी, रामसिंह कुशवाहा राष्ट्रीय समानता दल, राघवेंद्र सिंह निर्दलीय, बाबूलाल सोनी निर्दलीय, कंछेदीलाल निर्दलीय, हरदास कुशवाह निर्दलीय, धर्मेंद्र सिंह निर्दलीय, धर्मेंद्र सिंह पवार राइट टू रिकाल पार्टी, रोहित गुप्ता निर्दलीय शामिल हैं।

प्रत्याशी ज्यादा इसलिए

दोगुनी लगेंगी ईवीएम

दतिया उपचुनाव के लिए 21 कैंडिडेट होने के कारण इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। एक मशीन में 16 बटन हैं। जिसमें 15 बटन तो राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के और एक बटन नोटा का होता है। यानी एक मशीन में सिर्फ 15 उम्मीदवारों के नाम ही शामिल किए जा सकते हैं, जबकि इस उपचुनाव में 21 कैंडिडेट मैदान में हैं। ऐसे में अब हर पोलिंग स्टेशन पर दो ईवीएम रखी जाएंगी। यानी मशीनें पहले से दोगुनी चाहिए होंगी। मास्टर ट्रेनर्स मनोज द्विवेदी ने बताया कि ऐसे में बीयू यानि वेलेट यूनिट हर केंद्र पर दोगुनी लगेंगी। इसके लिए एफएलसी जल्दी कराई जाएगी। जिसके बाद प्रत्याशियों के नाम मशीन पर अंकित किए जाएंगे। दतिया में 291 मतदान केंद्र हैं, ऐसे में यहां 582 ईव्हीएम मतदान के लिए उपयोग में लाई जाएंगी।

कोहेफिजा थाने के टू-आईसी केजी शुक्ला सस्पेंड

भोपाल। राजधानी के कोहेफिजा थाने के टू-आईसी के.जी. शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कार्रवाई उनके खिलाफ लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद की गई है। जानकारी के अनुसार करीब एक महीने पहले केजी शुक्ला को कोहेफिजा थाना प्रभारी के पद से हटाकर टू-आईसी बनाया गया था। उस समय भी उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए आला अफसरो ने मामले पर नजर रखी। और अब उन्हें सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। सूत्रो के मुताबिक अफसरो को यह भी शिकायत मिली थी कि कोहेफिजा थाना क्षेत्र में अवैध काम चल रहे थे। इन गतिविधियों पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही थी। सूत्र बताते है की इन शिकायतो में सिर्फ केजी शुक्ला ही नहीं, बल्कि थाने के दूसरे पुलिसकर्मियों की भूमिका की संदिग्धता की भी जॉच की जा रही है। जांच के आधार पर अन्य पुलिसकर्मियो पर भी गाज गिर सकती है।

अब अगले माह जारी होगी निगम-मंडलों की सूची

- विधानसभा का मानसून सत्र और महीने के अंत में दतिया उपचुनाव होने से आगे बढ़ी प्रक्रिया

भोपाल। पहले दौर में निगम-मंडलों में नियुक्ति करने के बाद अब राजनीतिक नियुक्तियों के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सूची अगले महीने ही जारी हो सकेगी, क्योंकि इस महीने विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, वहीं माह के अंत में दतिया उपचुनाव भी हैं, जिसमें पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है।

मई माह में एक के बाद एक लगातार हो रही निगम-मंडलों में नियुक्तियों को लेकर लग रहा था कि मई माह में ही सभी नियुक्तियां पूरी हो जाएंगी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को उपकृत कर दिया जाएगा, लेकिन पिछले दो महीने से नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। इसका कोई स्पष्ट कारण भाजपा नेताओं की ओर से तो नहीं बताया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खर्चे कम करने को लेकर जो

अपील की थी, उसके कारण ही सरकार का व्यय न बढ़ाते हुए इन नियुक्तियों पर विराम लगा हुआ है। अब कहा जा रहा हैकि जल्द ही ये विराम खुलने वाला है और अगले महीने अगस्त माह में नियुक्तियों की सूची जारी होने वाली है। सूत्रों का कहना है कि इस महीने शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर ये नियुक्तियां और टल जाएंगी, वहीं दतिया उपचुनाव में भाजपा को अधिकांश नेताओं को जवाबदारी दी गई है, इसलिए भी इस माह नियुक्तियां होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जो होगा अब अगस्त माह में ही होगा। अगस्त माह में अगर सरकार चाहेगी तो इंदौर विकास प्राधिकरण को अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके साथ ही एल्डरमैनों के नाम की घोषणा होने के आसार भी नजर आ रहे हैं।

60 हजार कर्मचारियों को अब भी बढ़ा वेतन मिलने का इंतजार

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के एक लाख से अधिक संविदा अधिकारी-कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 4.46 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि लागू करने के वित्त विभाग के आदेश के एक महीने बाद भी कई विभागों ने इस पर अमल नहीं किया है। अब तक चार विभागों के करीब 41 हजार कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलने का रास्ता साफ हुआ है, जबकि लगभग 60 हजार अधिकारी-कर्मचारी अब भी अपने विभागों से आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।

वित्त विभाग ने 8 जून को एक अप्रैल 2026 से 4.46 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि लागू करने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने जून में ही अपने 2,800 कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर दिए थे। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद ने भी इस महीने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के कई अन्य विभागों में अब तक बढ़े हुए पारिश्रमिक के आदेश जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में लगभग 60 हजार संविदा अधिकारी-कर्मचारी वेतन वृद्धि का लाभ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। विभागीय स्तर पर आदेश जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

एनएचएम के 32 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन संचालक सलोनी सिडाना द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य, संभाग और जिला स्तर पर कार्यरत करीब 32 हजार संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को एक अप्रैल 2026 से 4.46 प्रतिशत बढ़ा हुआ पारिश्रमिक मिलेगा। इसका भुगतान जुलाई के वेतन के साथ किया जाएगा। हालांकि, यह लाभ संविदा चिकित्सा अधिकारी, स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी और पे माइनस पेंशन पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। एनएचएम ने आशा और शहरी आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी 4.46 प्रतिशत वृद्धि के आदेश जारी किए हैं।

रोजगार गारंटी परिषद में अगस्त से मिलेगा बढ़ा वेतन

मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद ने अपने करीब 6 हजार संविदा अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। परिषद के सहायक यंत्री, परियोजना अधिकारी, ऑडिट अधिकारी, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, लेखाधिकारी, उपयंत्री, डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रयोगशाला तकनीशियन, कार्यालय सहायक, भृत्य सहित विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ा वेतन मिलेगा, जिसका भुगतान अगस्त में किया जाएगा। विभाग ने एक अप्रैल से जून 2026 तक का एरियर भी देने के निर्देश दिए हैं। वेतन वृद्धि का सबसे अधिक लाभ रोजगार गारंटी परिषद के सहायक यंत्रियों को मिलेगा। उनका मासिक पारिश्रमिक 78,500 रुपए से बढ़कर 82,100 रुपए हो जाएगा। वहीं भृत्य का वेतन 21,800 रुपए से बढ़कर 22,800 रुपए हो जाएगा।

सीपीआई के आधार पर हर साल होती है वृद्धि

वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग की 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति के आधार पर यह वृद्धि लागू की है। नीति के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर हर वर्ष संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि की जाती है। पिछले वर्ष यह वृद्धि 2.94 प्रतिशत थी, जबकि इस बार इसे बढ़ाकर 4.46 प्रतिशत किया गया है। संविदा अधिकारी-कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर के अनुसार, जुलाई 2023 की संविदा नीति लागू होने से पहले अलग-अलग विभागों में समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन मिलता था। नई नीति के बाद समकक्ष पदों के वेतनमान एक समान कर दिए गए।

मध्य प्रदेश में बारिश की वापसी

- 19 जुलाई से भारी वर्षा का दौर; 31 जिलों में अलर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। करीब 9 दिन की सुस्ती के बाद मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई से प्रदेश में तेज बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 31 जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि, प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने के कारण गर्मी और उमस भी बढ़ सकती है। बीते 24 घंटे के दौरान भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, लेकिन मानसून अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया और तीन सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से मध्य प्रदेश में मानसून को नई ताकत मिलेगी, जिससे आगामी दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। बारिश के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में अब तक सामान्य से 13 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक असर पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, जहां 26 प्रतिशत बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई है। वहीं राजधानी भोपाल के बारिश के इतिहास पर नजर डालें तो जुलाई महीने में सर्वाधिक 41 इंच बारिश दर्ज होने का रिकॉर्ड है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आगामी सिस्टम मजबूत बना रहता है तो जुलाई के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, आकाशीय बिजली से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

सांदीपनि विद्यालयों से बदल रही शिक्षा की तस्वीर, यूसीसी वर्षाकालीन सत्र में होगी पेश - मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के सांदीपनि विद्यालय सर्वसुविधायुक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए केंद्र बनकर उभर रहे हैं। बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाओं के कारण अब विद्यार्थी निजी विद्यालयों से निकलकर शासकीय सांदीपनि विद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लगातार निवेश कर रही है। यह बात उन्होंने कटनी जिले के स्लीमनाबाद में झिंझरी और बहोरीबंद सांदीपनि विद्यालयों के लोकार्पण समारोह में कही।

मुख्यमंत्री ने बताया कि झिंझरी में 38.61 करोड़ रुपये तथा बहोरीबंद में 35.63 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित विद्यालयों में आधुनिक डिजिटल सुविधाओं के साथ गुरुकुल परंपरा का समन्वय किया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें, साइकिलें, 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर लैपटॉप तथा विद्यालय में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान की जा रही है। गुरुपूर्णिमा महोत्सव भी पूरे प्रदेश में उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा।

डॉ. यादव ने स्लीमनाबाद टनल परियोजना को किसान कल्याण वर्ष की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि लगभग 1,400 करोड़ रुपये की इस परियोजना से रीवा, सतना, मैहर, पन्ना और कटनी जिलों में सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा मजबूत होगी। साथ ही केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) परियोजनाओं से भी प्रदेश के कई जिलों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विधानसभा के आगामी वर्षाकालीन सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश एक देश, एक विधान, एक निशान और एक कानून की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्षाकालीन सत्र से पहले जगदीशपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित कर यूसीसी के प्रारूप को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं के खातों में 1,500 रुपये की राशि अंतरित की जाएगी। समारोह में सांसद विष्णु दत्त शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सरकार के दबाव में बदला फैसला? मंत्री प्रतिमा बागरी को क्लीन चिट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

1950 के अनुसूचित जाति आदेश, जनगणना रिकॉर्ड और ट्राई रिपोर्ट की अनदेखी का दावा, हाईकोर्ट जाने की घोषणा

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के अनुसूचित जाति (स्ष्ट) प्रमाण पत्र को लेकर चल रहे विवाद में राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति ने उनके जाति प्रमाण पत्र को वैध मानते हुए क्लीन चिट दे दी है। हालांकि, शिकायतकर्ता एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान इस निर्णय को चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि समिति ने सरकार के दबाव में निष्पक्ष जांच नहीं की और उनके द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवं ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी कर दी।

अहिरवार ने दावा किया कि मंत्री प्रतिमा बागरी छह अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिली थीं, जिसके बाद पूरी जांच प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि समिति ने 1950 के संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, जनगणना रिकॉर्ड और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (ट्राई) की रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को निर्णय में महत्व नहीं दिया।

उन्होंने कहा, मेरी शिकायत पूरी तरह तथ्यों और दस्तावेजों पर आधारित थी। यह फैसला सरकार के दबाव में हुआ है। मैं अंतिम सांस तक इस लड़ाई को जारी रखूँगा। अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने दिया जाएगा।

अहिरवार ने कहा कि वह इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

1. 1950 के अनुसूचित जाति आदेश का हवालाः शिकायतकर्ता का कहना है कि अनुसूचित जातियों का निर्धारण संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के अनुसार होता है। उनके अनुसार उस समय प्रतिमा बागरी का परिवार जिस क्षेत्र में निवास करता था, वहां बागरी समुदाय अनुसूचित जाति सूची में शामिल नहीं था। उनका आरोप है कि समिति ने इस पहलू पर स्पष्ट चर्चा नहीं की।

2. 1961 और 1971 की

जनगणना का उल्लेखः अहिरवार का दावा है कि 1961 और 1971 की जनगणना में प्रतिमा बागरी के परिवार ने स्वयं को अनुसूचित जाति के रूप में दर्ज नहीं कराया था। उनका कहना है कि इन अभिलेखों को भी जांच का महत्वपूर्ण आधार बनाया जाना चाहिए था।

3. ट्राई की मानवशास्त्रीय रिपोर्टः

शिकायत में 1998-99 की ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (ट्राई) की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार इस अध्ययन में विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के बागरी समुदाय को राजपूत/ठाकुर की उपजाति बताया गया था। उनका आरोप है कि समिति ने इस रिपोर्ट पर पर्याप्त विचार नहीं किया।

4. 1976 के बाद अनुसूचित जाति सूची में बदलावः

अहिरवार का कहना है कि 1976 में प्रदेश के लिए अनुसूचित जातियों की संयुक्त सूची लागू हुई, जिसमें बागरी/बागड़ी' को शामिल किया गया। उनका आरोप है कि इसके बाद ऐसे क्षेत्रों के लोगों ने भी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाने शुरू कर दिए, जहां पहले यह दर्जा लागू नहीं था।

5. क्षेत्रीय आधार पर लाभ का विवादः

शिकायतकर्ता का दावा है कि अनुसूचित जाति का लाभ पाने वाले मूल बागरी समुदाय का निवास मुख्यतः मालवा, निमाड़ और मध्यभारत क्षेत्र में रहा है, जबकि प्रतिमा बागरी का परिवार लंबे समय से सतना (तत्कालीन विंध्य प्रदेश) का निवासी है। प्रतिमा के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों में परिवार का लगभग 112 वर्षों से सतना में निवास दर्शाया गया है।

6. 2007 के राजपत्र का हवालाः

शिकायत में वर्ष 2007 के एक राजपत्र का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसमें कुछ जिलों के संबंध में अनुसूचित जाति लाभ को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया था, लेकिन समिति ने अपने निर्णय में इस पहलू को स्पष्ट नहीं किया।

हाईकोर्ट जाएंगे शिकायतकर्ता

प्रदीप अहिरवार ने कहा कि समिति का निर्णय निष्पक्ष नहीं है और वह इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उनका कहना है कि यदि आवश्यक हुआ तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। अहिरवार ने कहा, छानबीन समिति ने मंत्री प्रतिमा बागरी मामले में देखभाल समिति जैसा काम किया है और उन्हें बचाने के लिए 1950 के संविधान आदेश तक को नहीं माना। इसके अलावा ट्राई रिपोर्ट के साथ अन्य शासकीय दस्तावेजों को दरकिनार कर निर्णय किया है, जिसको न्यायालय में चुनौती देंगे।

16 खदानों में तत्काल खनन बंद

हाईकोर्ट का अवैध खनन पर बड़ा प्रहार - एसडीओ पर अवमानना, कलेक्टर को सौंपी व्यक्तिगत जिम्मेदारी

भोपाल। मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में लंबे समय से चल रहे कथित अवैध खनन और प्रशासनिक उदासीनता पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए 16 खदानों में तत्काल प्रभाव से खनन गतिविधियां बंद करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण और मानव जीवन की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। साथ ही नौ वर्षों से लंबित मामलों में कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।

जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि वर्ष 2017 में जिन खदान संचालकों को अवैध खनन, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनिज उत्खनन और करोड़ों रुपये की रॉयल्टी एवं पेनाल्टी वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, उन मामलों का आज तक अंतिम निराकरण नहीं किया गया। अदालत ने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी पर्यावरण और मानव अस्तित्व जैसे गंभीर विषयों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। हाईकोर्ट ने जिन 16 खदानों में तत्काल खनन रोकने का आदेश दिया है, उनमें बच्चन सिंह, ए.के. जैन/जे.जे. ग्रेनाइट, पीताम्बरा ग्रिट इंडस्ट्रीज, कल्लू उर्फ दीनदयाल, रामनिवास शर्मा, राजेश नीखरा, मनोहर लाल, ओमप्रकाश, राजीव लोचन, अशोक सिंह यादव, सुनील शर्मा, मिरेंद्र सिंह, विनीता यादव, प्रतीक खंडेलवाल सहित अन्य संचालकों की खदानें शामिल हैं।

एसडीओ की रिपोर्ट पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान डबरा के एसडीओ रूपेश रतन सिंघई व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए। अदालत ने उनकी ओर से प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को भ्रामक और अधूरी माना। कोर्ट ने पाया कि बच्चन सिंह की खदान का वर्ष 2020 में बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) और नियमों की अनदेखी करते हुए पट्टा नवीनीकरण कर दिया गया, जबकि उन पर 21 करोड़ रुपये से अधिक की रॉयल्टी और 17.53 करोड़ रुपये से अधिक की पेनाल्टी लंबित थी। अदालत ने यह भी पाया कि एसडीओ कई खनन क्षेत्रों का निरीक्षण तक नहीं कर सके थे और बार-बार पूछे जाने पर भी यह नहीं बता पाए कि वर्तमान में कहां खनन जारी है। इसे गंभीर कर्तव्यहीनता मानते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद-215 के तहत अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए और 15 दिन के भीतर जवाब तलब किया।

कलेक्टर को सौंपी व्यक्तिगत जिम्मेदारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान भी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं। हाईकोर्ट ने कहा कि अब क्षेत्र में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। अदालत ने यह भी पाया कि खदान क्षेत्रों के ई-चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं, लेकिन उनकी नियमित निगरानी नहीं की जा रही। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने सभी डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज तत्काल जब्त कर सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कोई फुटेज हटाई या नष्ट की गई तो इसे साक्ष्य मिटाने का प्रयास माना जाएगा।

नए सीमांकन पर भी रोक

हाईकोर्ट ने प्रशासन द्वारा नए सीमांकन की प्रक्रिया शुरू करने पर भी रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि यह मामला भटकाने का प्रयास प्रतीत होता है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगली अनुमति तक कोई नया सीमांकन नहीं किया जाएगा और आगे की पूरी कार्रवाई वर्ष 2017 की मूल सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर ही होगी।

अदालत का स्पष्ट संदेश

हाईकोर्ट की यह टिप्पणी पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए सख्त संदेश मानी जा रही है कि पर्यावरण संरक्षण, खनिज संपदा और राजस्व से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्षों से लंबित कार्रवाई, अवैध खनन पर ढिलाई और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब जवाबदेही तय होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लेनोक्स की घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को तीसरे एकदिवसीय में छह विकेट से हराया

जमैका। स्पिनर जेडन लेनोक्स की अच्छी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड ने यहां खेले गये तीसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को छह विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। इस तीसरे मैच में मेजबान वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 37.1 ओवरों में ही 140 रन बनाकर आउट हो गयी। इसके बाद जीत के लिए मिले लक्ष्य को मेजबान टीम न्यूजीलैंड ने आसानी से 39.3 ओवरों में ही चार विकेट खोकर 141 रन बनाकर हासिल कर लिया।

मैच में कीवी स्पिनर के सामने मेजबान बल्लेबाज टिक नहीं पाये। लेनोक्स ने अपनी गेंदबाजी से मध्यक्रम व निचले क्रम क्रम को आसानी से समेट दिया। मैच के दौरान वेस्टइंडीज के केवल तीन बल्लेबाज ही दो अंकों तक पहुंच पाये। केसी कार्टी ने सबसे अधिक 48 रन बनाये। उनके अलावा, अकीम ऑगस्ट और शिमरोन हेटमायर ने 26-26 रन बनाए। वहीं लेनोक्स ने 52 रन देकर चार विकेट लिए। यह उनका लगातार दूसरा मैच था जब लेनोक्स की गेंदबाजी के सामने मेजबान टीम टिक नहीं पायी। पिछले मैच में भी उन्होंने केवल 19 रन देकर पांच विकेट लिए थे। लेनोक्स के अलावा, मिचेल सैंटनर ने 8.1 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर दो विकेट लिए, जबकि माइकल ब्रैसवेल ने 33 रन देकर दो विकेट लिए।

वहीं इसके बाद जीत के लिए मिले 141 रनों के आसान से लक्ष्य को न्यूजीलैंड की टीम ने हेनरी निकोल्स के 24 रन और विल यंग के 23 रनों की सहायता से आसानी से हासि कर लिया। कीवी टीम की ओर से डेरिल मिचेल ने 28 रन बनाए जबकि कप्तान टॉम लैथम और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के बीच पांचवें विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी हुई। लैथम ने 53 गेंदों में नाबाद 31 रन बनाए, जबकि फॉक्सक्रॉफ्ट ने 28 गेंदों में नाबाद 22 रन बनाये।

रोहित को बाहर किये जाने की अटकलों से सहमत नहीं बल्लेबाजी कोच कोटक

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा को लेकर आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय के बाद उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि रोहित का करियर अब समाप्त होने की ओर है। इसका कारण ये बताया गय है कि वह इंग्लैंड दौरे में उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाये हैं। यह अटकलें ऐसे समय में सामने आ रही हैं जब भारतीय टीम 2027 में होने वाले अगले एकदिवसीय विश्व कप की रूपरेखा तैयार करने में लगी है। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सिंताशु कोटक ने एक अलग ही बात कही है। जिसमें रोहित को बाहर किये जाने की अटकलें को खारिज किया गय है। कोटक ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे नहीं लगता कि रोहित जैसे बड़े कद के खिलाड़ी पर कोई दबाव है। वह एक बेहतरीन और असाधारण खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, हां, उन्होंने पिछले दो मैचों में अपेक्षित रन नहीं बनाए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस छोटी अवधि के प्रदर्शन से उनके पूरे करियर या क्षमता पर कोई फर्क पड़ेगा। दूसरे मैच में ऐसा लग रहा था कि वह एक बड़ी पारी खेलने जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया।

2027 एकदिवसीय विश्व कप को देखते हुए कुलदीप को लगातार अवसर दें - अश्विन

चेन्नई । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने कहा है कि बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव आगामी 2027 एकदिवसीय विश्वकप में उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें अधिक से अधिक अवसर दिये जाने की जरुरत है। अश्विन ने स्पष्ट किया कि 2027 विश्व कप के संयोजन में अंगुली के दो ऑलराउंडर फिट नहीं बैठेंगे। ऐसे में टीम को कुलदीप की जरुरत रहेगी उन्होंने भविष्य की रणनीति को लेकर कहा, जब भी कुलदीप के लिए जगह बनेगी, और अगर तेज गेंदबाज हर्षित राणा फिट और अच्छी फॉर्म में होंगे, तो हर्षित राणा तीसरे तेज गेंदबाज बन जाएंगे। ऐसे में कुलदीप के लिए एक अवसर बन जाएगा। अश्विन ने कहा कि कुलदीप को इसलिए भी टीम में बनाये रखा जाना चाहिये क्योंकि एक मैच विजेता ले स्पिनर हैं। उन्होंने कहा कि 2023 एकदिवसयी विश्व कप में भी कुलदीप ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। वह किसी भी चरण में गेंदबाजी कर सकते हैं, साथ ही उनका दक्षिण अफ्रीका में भी रिकॉर्ड अच्छा है। अश्विन ने कुलदीप के आत्मविश्वास के स्तर को लेकर भी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्तमान टीम प्रबंधन ने कुलदीप को पर्याप्त अवसर नहीं दिये है जबकि वह कठिन अवसरों पर विकेट निकलकर मैच पलटने में माहिर हैं। इसलिए उन्हें अधिक से अधिक अवसर दिये जाने चाहिये। अश्विन के अनुसार, यदि कुलदीप को सही मानसिकता के साथ 2027 विश्व कप में जाना है, तो उन्हें लगातार मौके दिए जाने चाहिए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने भारत से कुलदीप यादव को मुख्य स्पिनर के तौर पर खिलाने की इच्छा व्यक्त की।वहीं ऑलराउंडर विकल्पों को लेकर अश्विन ने कहा कि हार्दिक पांड्या और नितीश कुमार रेड्डी ही सबसे बेहतर रहेंगे। साथ ही कहा कि शिवम दुबे को ऑलराउंडर के तौर पर जगह दिया जाना सही नहीं होगा क्योंकि एकदिवसीय प्रारुप में वह अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाये हैं।

पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने बताया विराट की सफलता का राज

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने कहा है अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली को अपने कौशल और खेलने के तरीकों पर पूरा भरोसा रहता है और इसी कारण वह इतने सफल है। नायर के अनुसार जब विराट खराब दौर से गुजरते हैं तब भी वह अपनी तकनीक पर भरोसा बनाये रखते हैं और किसी प्रकार के बदलाव के बारे में नहीं सोचते। यही उनके महान होने का करण है। नायर ने कहा कि अपने तरीकों पर अटूट भरोसा ही उनकी लगातार सफलता का मूल कारण है। नायर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जब विराट रन नहीं बना पा रहे थे तब भी अपने खेलने के तरीके पर बने हुए थे। नायर का मानना है कि यही अंतर दिग्गज और आम खिलाड़ियों के काम करने के तरीके में होता है। कोहली की मानसिक दृढ़ता और उनके अटूट विश्वास पर प्रकाश डालते हुए, नायर ने कहा कि वह विराट को लंबे समय से जानते हैं, लेकिन हाल ही में उन्हें समझ आया कि कोहली की महानता का रहस्य उनका दृढ़ भरोसा है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। नायर ने एक घटना का जिक्र किया जब ऑस्ट्रेलिया में एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान कोहली संघर्ष कर रहे थे और दो बार शून्य पर आउट हुए थे। उस समय उन्होंने कोहली से संपर्क किया था यह जानने के लिए कि वह इस खराब दौर का सामना कैसे कर रहे हैं।

तब कोहली ने काफी शांत तरीके से उनका जवाब दिया था। नायर ने बताया, मैंने उनसे पूछा कि क्या सब ठीक है और क्या वह किसी बात पर चर्चा करना चाहेंगे। उन्होंने बस इतना कहा, नहीं, सब ठीक है। यह खेल का हिस्सा है। उनका आत्मविश्वास जरा भी कम नहीं हुआ था। नायर ने कहा कि उन्होंने कोहली से एक तकनीकी अवलोकन साझा करने की अनुमति मांगी। पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें अपने पर पूरा भरोसा था। नायर के लिए, यह घटना बखूबी दर्शाती है कि उन खिलाड़ियों को क्या अलग बनाता है जो लगातार उच्चतम स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। उनका मानना है कि चैंपियन खिलाड़ी अपने वर्षों के अनुभव और अपने काम के तरीके पर पूरा भरोसे करते हैं खासकर तब जब परिणाम उनके पक्ष में नहीं होते।

रूट के नाबाद 99 रनों की सहायता से इंग्लैंड ने दूसरा एकदिवसीय जीता

कार्डिफ। अनुभवी बल्लेबाजी जो रुट के नाबाद 99 रनों से सहायता से मेजबान इंग्लैंड ने यहां खेले गये दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारतीय टीम को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। भारतीय टीम ने तीन मैचों की इसी सीरीज का पहला एकदिवसीय जीता था पर दूसरे मैच में बल्लेबाजी असफल रहने से उसे हार का सामना करना पड़ा। मैच में शानदार प्रदर्शन के कारण रुप को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला।

मैच की बात करें तो मेजबान टीम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। भारतीय टीम 44 ओवरों में ही 233 रनों पर सिमट गयी। इसके बाद जीत के लिए मिले लक्ष्य को मेजबान टीम ने 44.1 ओवर में ही 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी कर करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत ठीक रही। कप्तान शुभमन गिल 31 और रोहित शर्मा 26 ने

संभलकर खेल पर बड़ा स्कोर नहीं बना पाये। इनके आउट होने के बाद ईशान किशन भी 1 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। वहीं विराट कोहली ने 65 और श्रेयस अय्यर ने 66 रन बनाये। इनके बीच चौथे विकेट के लिए 67 रन की अहम साझेदारी हुई। इस साझेदारी के टूटने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई। अंत में, जसप्रीत बुमराह ने 13 गेंदों में नाबाद 20 रन बनाकर टीम को 233 रनों तक पहुंचाया। वहीं इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने 3-3 विकेट लिए, जबकि साकिब महमूद ने 2 विकेट लिए। सैम करन और विल जैक्स को 1-1 विकेट मिला।

इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम की शुरुआत भी खराब रही। सलामी बल्लेबाज बेन डकेट खाता भी नहीं खोल पाये जबकि जैकब बेथेल 4 रन ही बना पाये। इसके बाद रूट ने एक छोर संभाले रखा और टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। उन्होंने कप्तान हैरी ब्रूक 16 के साथ 45 रन, सैम करन 26 के साथ 45 रन और जोस बटलर 17 के साथ 31 रन की साझेदारियां कीं। विल जैक्स 30 के साथ छठे विकेट के लिए 86 गेंदों में 72 रन की अहम साझेदारी कर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। अंत में, रूट ने गस एटकिंसन नाबाद 23 के साथ मिलकर 38 रन की साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। रूट 133 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से नाबाद 99 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि एटकिंसन ने 16 गेंदों में 4 चौकों के साथ तेजी से रन बनाए। वहीं भारत की ओर से गुरनूर बरार ने 2 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया।

फीफा विश्व कप 2026 फाइनल में मुख्य रैफरी होंगे स्लोवेनिया के विंसिक

न्यूयॉर्क । स्लोवेनिया के स्लावको विंसिक फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 के फाइनल मुकाबले में मुख्य रेफरी होंगे। ये खिताबी मुकाबला न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। फीफा के रेफरी प्रमुख पियरलुइगी कोलिना ने कहा है कि विश्व कप फाइनल जैसे बड़े और महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए एक अनुभवी तथा योग्य रेफरी का होना बेहद आवश्यक है जिसके लिए विंसिक सही व्यक्ति हैं।

गौरतलब है कि 46 वर्षीय स्लावको विंसिक के लिए यह पहला बड़ा विश्व कप फाइनल होगा। उन्होंने अपने विश्व कप करियर की शुरुआत कतर में आयोजित 2022 विश्व कप से की थी, जहाँ उन्होंने दो मैचों में रेफरी की जिम्मेदारी संभाली थी। इस विश्व कप 2026 में भी वह अब तक तीन मैचों में रेफरी रहे हैं। फाइनल मुकाबला उनके विश्व कप करियर का छठा मैच होगा। फीफा द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, फाइनल मुकाबले में स्लावको विंसिक की सहायता के लिए टोमाज क्लैंचनिक को सहायक रेफरी-1 और एंड्राज कोवाचिक असिस्टेंट रेफरी-2 के रूप में उपस्थित रहेंगे।

वहीं, अधम मखादमेह चौथे अधिकारी की भूमिका निभाएंगे, जबकि मोहम्मद अल्कालाफ रिजर्व सहायक रेफरी होंगे।

विंसिक के करियर में कई प्रतिष्ठित और बड़े मुकाबले शामिल हैं, जिनमें हाल ही में रियल मैड्रिड और बोरूसिया डॉर्टमुंड के बीच खेला गया यूईएफए 2024 चैंपियंस लीग फाइनल भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यूईएफए यूरोपीय चैंपियनशिप, विश्व कप क्वालिफायर, यूरोपा लीग, नेशंस लीग और क्लब विश्व कप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों में भी अपनी रेफरी की भूमिका निभाई है। विश्वकप फाइनल 19 जुलाई को अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा।

स्पेन के यामल और पोरो का फीफा विश्वकप फाइनल में खेलना संदिग्ध

न्यू जर्सी । फीफा विश्वकप फुटबॉल के रविवार को होने वाले खिताबी मुकाबले से ठीक पहले अपने दो प्रमख खिलाड़ियों लैमिन यामल और डिफेंडर पेड्रो पोरो की फिटनेस को लेकर स्पिन की चिन्ताएं बढ़ गयी हैं। इसका कारण है कि न्यू जर्सी में हुए टीम के पहले प्रशिक्षण सत्र के दौरान ये दोनों खिलाड़ी मुख्य दल से अलग अभ्यास करते हुए देखे गए, जिससे उनकी खिताबी मुकाबले में खेलने को लेकर संशय छा गया है। इन दोनो ही खिलाड़ियों ने अब तक टूर्नामेंट में स्पेन की ओर से अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में अगर से इन मैच में नहीं खेल पाते हैं तो स्पेन की जीत की उम्मीदें घट जाएंगी।

टीम के बेहतरीन खिलाड़ी यामल, अपनी बाईं जांघ पर पट्टी बांधे हुए थे और उन्होंने मैदान के किनारे हल्की एक्सरसाइज तथा स्ट्रेचिंग की। जानकारी के अनुसार, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था। हालांकि उनकी चोट की गंभीरता के बारे में कोई आधिकारिक बयाान नहीं आया है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें इसलिए मुख्य समूह से बाहर रखा गया है जिससे फाइनल से पहले उनकी फिटनेस पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। यामल ने इस विश्व कप में सक्रिय भूमिका निभाई है और केप वर्डे के खिलाफ मुकाबले को छोड़कर उन्होंने लगभग हर मुकाबले में शुरुआती एकादश में जगह बनाई है। चोट से वापसी के बाद वे भले ही अपनी पूरी लय में न दिखे हों पर फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल में उनके शानदार प्रदर्शन से ही टीम को पैनाल्टी मिली थी जिससे उसने बढ़त हासिल की।

वहीं दूसरी ओर पोरो भी फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने भी न्यू जर्सी में पहले ट्रेनिंग सेशन में बाकी खिलाड़ियों के साथ अभ्यास नहीं किया। पोरो ने स्पेन के सात में से पांच मैचों में शुरुआती एकादश में स्थान बनाया टूर्नामेंट में उन्होंने दो महत्वपूर्ण गोल भी किए हैं, जिनमें ऑस्ट्रिया के खिलाफ राउंड ऑफ 32 और फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल का गोल शामिल है। सेमीफाइनल के बाद स्पेन के मुख्य कोच लुइस डे ला फुएंते ने स्वयं इस बात की पुष्टि की थी कि पोरो की मांसपेशियों में हल्की जकड़न है और फाइनल से पहले उनकी फिटनेस की गहन जांच की जाएगी।

हालांकि, कोच डे ला फुएंते ने लैमिन यामल की स्थिति पर भरोसा जताया है। उन्होंने मेडिकल टीम से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि यामल की कोई गंभीर समस्या नहीं है और उनकी हालत ठीक है।

सुंदर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय से बाहर हुए

लॉर्ड्स । भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले तीसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच से बाहर हो गये हैं। सुंदर का बाहर होना

भारतीय टीम के लिए करारा झटका है क्योंकि उन्होंनें पहले एकदिवसीय में भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

सुंदर को हैमस्ट्रिंग की चोट दूसरे एकदिवसीय के दौरान लगी थी। इससे वह मैच की दूसरी पारी में नहीं उतरे थे। सुंदर की यह चोट भारत के लिए एक और झटका है, क्योंकि टीम पहले से ही ऑलराउंडर हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी फिट नहीं होने के कारण टीम से बाहर हैं। है। ऐसे में, निर्णायक मुकाबले से पहले सुंदर का बाहर होना टीम की चुनौतियों को और बढ़ा देगा।

दूसरे एकदिवसीय मैच के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने भी कहा कि इस ऑलराउंडर की चोट गंभीर है।

वहीं कप्तान शुभमन गिल ने भी सुंदर की अनुपस्थिति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुंदर की चोट से दूसरे एकदिवसीय में टीम की लय बिगड़ गई, क्योंकि उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। शुभमन ने बताया कि सुंदर टीम का एक अहम हिस्सा थे और अगर उन्हें चोट न लगी होती, तो बल्लेबाजी के दौरान दबाव कम करने में उनकी भूमिका हो सकती थी।

तीसरे स्थान के लिए फ्रांस और इंग्लैंड की प्रतिष्ठा की जंग, कांस्य पदक पर होगी नजर

मियामी । फीफा विश्व कप 2026 में तीसरे स्थान के लिए होने वाला प्ले-ऑफ मुकाबला रविवार, 19 जुलाई को भारतीय समयानुसार तड़के 2:30 बजे खेला जाएगा। इस मुकाबले में दो यूरोपीय फुटबॉल महाशक्तियां फ्रांस और इंग्लैंड आमने-सामने होंगी। दोनों टीमें सेमीफाइनल में हार के बाद अब जीत के साथ अपने अभियान का समापन करने और कांस्य पदक हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। मुकाबला अमेरिका के मियामी स्थित मियामी स्टेडियम (हार्ड रॉक स्टेडियम) में खेला जाएगा।

फ्रांस को सेमीफाइनल में स्पेन के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही लगातार तीसरी बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने का उसका सपना टूट गया। दूसरी ओर इंग्लैंड को गत चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ 2-1 की रोमांचक हार झेलनी पड़ी, जिसमें अंतिम क्षणों में मैच का पासा पलट गया। अब दोनों टीमें तीसरे स्थान के मुकाबले में अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश करेंगी। फ्रांस के पास किलियन एमबाप्पे, उस्मान डेम्बेले और माइकल ओलीसे जैसे स्टार खिलाड़ी हैं, जबकि इंग्लैंड की उम्मीदें हैरी केन, एंथनी गॉर्डन और जूड बेलिंगहैम जैसे खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला तेज गति, आक्रामक फुटबॉल और रणनीतिक खेल के लिए जाना जाता है, इसलिए प्रशंसकों को एक रोमांचक मैच देखने की उम्मीद है।

हालांकि तीसरे स्थान का मुकाबला विश्व कप ट्रॉफी जितना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, फिर भी यह दोनों टीमों के लिए सम्मान बचाने और सकारात्मक परिणाम के साथ टूर्नामेंट समाप्त

करने का अवसर होगा। यह मुकाबला युवा खिलाड़ियों को खुद को साबित करने और टीम प्रबंधन को भविष्य की योजनाओं का आकलन करने का भी मौका देगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों टीमें अपनी मजबूत प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती हैं ताकि विश्व कप अभियान का समापन जीत के साथ किया जा सके। इस मुकाबले के बाद विश्व कप का फाइनल 20 जुलाई (भारतीय समयानुसार) स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। ऐसे में तीसरे स्थान का यह प्ले-ऑफ भी फुटबॉल प्रेमियों के लिए किसी बड़े फाइनल से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इसमें दो विश्व स्तरीय टीमें सम्मान और कांस्य पदक के लिए पूरा दमखम लगाती नजर आएंगी।

फ्रांस और इंग्लैंड दोनों सेमीफाइनल में हार के बाद तीसरे स्थान के लिए उतरेंगे, इसलिए दोनों टीमों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उपलब्ध टीम समाचार और हालिया मैचों के आधार पर संभावित प्लेइंग इलेवन इस प्रकार हो सकती है-

फ्रांस (संभावित XI) - 4-2-3-1

गोलकीपर: माइक मेन्यां

डिफेंडर: जूल्स कुंडे, इब्राहिमा कोनाते, मैक्सेंस लाक्रोआ, थियो हर्नांडेज़

मिडफील्डर: मानु कोने, वॉरेन ज़ैरे-एमरी

अटैकिंग मिडफील्डर: रायान शेरकी, माइकल ओलीसे, देज़िरे दूए

स्ट्राइकर: किलियन एम्बाप्पे

फ्रांस के नियमित सेंटर-बैक विलियम सालिबा पीठ की चोट के कारण उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, जबकि कोच दिदिए देशां कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं।

इंग्लैंड (संभावित XI) - 4-2-3-1

गोलकीपर: जॉर्डन पिकफोर्ड

डिफेंडर: जेड स्पेंस, जॉन स्टोन्स, मार्क गुएही, निको ओराइली

मिडफील्डर: डेक्लन राइस, इलियट एंडरसन

अटैकिंग मिडफील्डर: जूड बेलिंघम, मॉर्गन रोजर्स, एंथनी गॉर्डन

स्ट्राइकर: हैरी केन

रीस जेम्स सेमीफाइनल में चोटिल हुए थे, इसलिए उनके इस मुकाबले में खेलने की संभावना कम मानी जा रही है।

दोनों टीमों के पास विश्वस्तरीय आक्रमण है। फ्रांस की उम्मीदें किलियन एम्बाप्पे पर रहेंगी, जबकि इंग्लैंड के लिए हैरी केन और जूड बेलिंघम सबसे अहम खिलाड़ी होंगे। हालांकि तीसरे स्थान के मैच में अंतिम एकादश मैच से ठीक पहले घोषित की जाएगी, इसलिए इसमें बदलाव संभव हैं।

टी20 प्रारुप में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर डिविलियर्स ने चिन्ता जतायी

बोले आईपीएल सितारों को जमीनी हकीकत समझनी होगी

जोहांबर्ग । दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने कहा है कि आईपीएल के सितारों को जमीनी हकीकत समझने की जरुरत है। डिविलियर्स ने टी20 प्रारुप में भारतीय टीम के गिरते हुए प्रदर्शन को लेकर ये बात ही है। डिविलियर्स ने कहा कि आईपीएल में धमाकेदार पारियां खेलने वालों को ये समझना चाहिये कि लीग और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के स्तर में काफी अंतर होता है। उन्होंने किसी खिलाड़ी का नाम लिए बिना कहा कि आईपीएल में रनों का पहाड़ बनाने वाले खिलाड़ियों को अब जमीन पर वापस आने की जरूरत है। माना जा रहा है कि उनका संकेत आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी की ओर था। डिविलियर्स ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हर समय पांचवें गियर में खेलने का खेल नहीं है क्योंकि यहां कमजोर गेंदबाज नहीं मिलते, बल्कि हर प्रतिद्वंद्वी विश्व स्तरीय होता है। डिविलियर्स ने जोर दिया कि बल्लेबाजों को हालातों के अनुकूल ढलते हुए एक या दो से अधिक गियर में खेलना आना चाहिए। उनके अनुसार भारतीय टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड से मिली हार को देखते हुए अब संभल जाना

चाहिये।

वहीं भारतीय टीम की हार के बाद से ही मुख्य कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से वह टीम में लगातार बदलाव करते हैं वह टीम को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं डिविलियर्स का मानना है कि केवल कोच को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं, बल्कि मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। भारतीय प्रशंसकों को सांत्वना देते हुए डिविलियर्स ने धैर्य रखने की अपील की है, क्योंकि टीम इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की जगह रातों-रात नहीं ली जा सकती। इसके अलावा, जसप्रीत बुमराह जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज के कार्यभार को प्रबंधित करने के कारण द्विपक्षीय सीरीज में अक्सर गेंदबाजी आक्रमण अनुभवहीन दिखता है।

आरबीआई ने जारी किया पॉलिमर सब्सट्रेट शीटों के लिए ग्लोबल टेंडर...

भारत में जल्द आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट!

नई दिल्ली। भारत में जल्दी ही कागज की बजाय प्लास्टिक के नोट चलने वाले हैं! बीते महीनों में सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पॉलीमर नोट को चलन में लाने की तैयारी कर में है। अब मीडिया के सूत्रों की मानें तो आरबीआई जल्द ही देश में पॉलीमर नोटों के संचालन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, जिसके लिए बड़ी तैयारी भी सामने आई है।

देश के करेंसी सिस्टम में बड़े सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए आरबीआई ने पॉलीमर नोटों को चलन में लाने के पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत आरबीआई की नोट मुद्रण शाखा ने नोट छपाई के लिए ओपेसिफाइड पॉलिमर सब्सट्रेट शीटों (प्लास्टिक नोट बनाने वाले बेस मटीरियल) के लिए एक ग्लोबल टेंडर भी जारी कर दिया है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि ईओआई के तहत बोली जमा करने के लिए 18 अगस्त तक की लास्ट डेट तय की गई है।

रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलीमर नोटों को चलन में लाने की तैयारी तेज कर दी है। और 10-20 रूपए के नोटों के साथ इसका संचालन भी शुरू होने की संभावना जताई गई है। हालांकि अब तक इसके चलन की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लास्टिक नोटों का फुल-स्केल रोलआउट साल 2027 से शुरू हो सकता है। प्लास्टिक के नोट पेपर करेंसी के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ होते हैं। उन पर गंदगी और नमी का असर कागजी नोट की तुलना में कम होता है, जिसके कारण उनकी सेल्फ लाइफ अधिक होती है। हालांकि प्लास्टिक नोट की छपाई का शुरुआती खर्च मौजूदा नोट की तुलना में अधिक हो सकता है लेकिन इनकी सेल्फ लाइफ अधिक होने के कारण बार-बार छापने की जरूरत नहीं होती. जिसके कारण समय के साथ लागत में भी कमी आ सकती है।

60 देशों में चलते हैं प्लास्टिक के नोट

आरबीआई की ओर से पॉलीमर नोट को चलन में लाने का प्रयास पहली बार नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि दुनिया के करीब 60 देशों में पॉलीमर नोट चलन में हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुई, उसके बाद कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, रोमानिया और ब्रुनेई जैसे देशों में भी ये नोट चलन में आया। अब भारत में भी इसको चलाने पर जोर दिया जा रहा है।

दमन से दिल्ली के लिए पहली सीधी हवाई सेवा शुरू

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश दमन को दिल्ली के लिए पहली सीधी हवाई सेवा की सौगात मिली है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नवनिर्मित नमो एयरपोर्ट से एलायंस एयर की दमन-दिल्ली-दमन उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इस ऐतिहासिक शुरुआत से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 8 से 10 घंटे से घटकर मात्र ढाई घंटे रह जाएगा, जिससे आम लोगों को तेज और सुलभ हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा। यह नई विमान सेवा दमन और उसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली क्षेत्र में 7,000 से अधिक उद्योग सक्रिय हैं, जबकि नजदीकी वापी और वलसाड में करीब 15,000 उद्योग हैं। बेहतर हवाई संपर्क से कारोबारी यात्राएं आसान होंगी, नया निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के अवसर बढ़ने है। इसके साथ ही, सालाना दमन आने वाले 20 लाख पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को बड़ा सहारा मिलेगा।

भारतीय तटरक्षक बल के एयर स्टेशन पर 124 करोड़ रुपये की लागत से विकसित नमो एयरपोर्ट का आधुनिक टर्मिनल सालाना 3.67 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है। भविष्य में इसके रनवे का विस्तार कर मुंबई, सूरत और पटना जैसे शहरों के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने उड़ान योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, जिसके तहत 29,000 करोड़ रुपये के बजट से देश भर में 100 नए एयरपोर्ट और 200 नए हेलीपैड विकसित किए जाएंगे।

आसाराम की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से मांगी मेडिकल रिपोर्ट

नई दिल्ली। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। खराब सेहत का हवाला देकर कुछ समय की राहत मांग रहे आसाराम की याचिका पर सुनवाई कर शीर्ष अदालत ने राजस्थान सरकार को उनकी ताजा मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि क्या आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति वाकई इतनी नाजुक है कि उन्हें इलाज के लिए जेल से बाहर भेजना जरूरी हो।

सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार का पक्ष रखकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि फिलहाल आसाराम की तबीयत ठीक है। उन्होंने कहा कि करीब तीन महीने पहले आसाराम ने अयोध्या और काशी विश्वनाथ की यात्रा की थी, जहां उन्होंने पैदल चलकर दर्शन किए थे। इसके बावजूद, राजस्थान सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वे संबंधित अधिकारियों से पूरी जानकारी और ताजा मेडिकल रिपोर्ट जुटाकर जल्द ही कोर्ट के सामने रखी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि मेडिकल जांच में आसाराम की हालत वास्तव में गंभीर मिलती है, तब मानवीय आधार पर सिर्फ इलाज के उद्देश्य से सीमित समय के लिए अंतरिम जमानत पर विचार हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह किसी भी अप्रिय स्थिति से बचना चाहती है। राजस्थान सरकार को मामले में 21 जुलाई तक अपना जवाब और रिपोर्ट दाखिल करनी है, जिसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2013 में हुए इस अपराध के लिए जोधपुर की विशेष अदालत ने अप्रैल 2018 में आसाराम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वे सलाखों के पीछे हैं।

अमेरिका के ट्रंप से सतर्क रहे भारत, ब्राजील-ईरान के अनुभवों से सीख लें

नई दिल्ली। अमेरिका द्वारा ब्राजील पर अचानक 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का घटनाक्रम भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यह प्रसिद्ध भू-राजनीतिक विशेषज्ञ डॉ. ब्रह्मा चेलानी का आकलन है, जो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक विश्वसनीयता संदिग्ध है और उनका कोई भी वादा कभी भी टूट सकता है। ट्रंप ने 2025 में भी इसी तरह की कार्रवाई की थी, और ईरान पर अमेरिका द्वारा फिर शुरू किए गए हमले से भी उनकी अप्रत्याशितता साबित हो चुकी है।

डॉ. चेलानी ने बताया कि सेक्शन 301 के तहत जांच के बाद ब्राजील पर ट्रम्प का यह अप्रत्याशित कदम उन सभी देशों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए जो वाशिंगटन के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, विशेषकर भारत जैसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए सतर्क रहना चाहिए। उनका मानना है कि अगर अमेरिका दुनिया की विशाल अर्थव्यवस्था के खिलाफ इतनी तेजी से कार्रवाई कर सकता है, तब ट्रंप प्रशासन के साथ किसी भी तरह की चर्चा में जोखिम निहित हैं।

ट्रंप की अप्रत्याशितता केवल उलझने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अपने ही वादों से पलटने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने ईरान के साथ 17 जून को वर्साय में एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने के मुश्किल से तीन सप्ताह बाद ही उस समझौते को फाड़ दिया और फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए, जो उनके भरोसेमंद न होने का एक स्पष्ट प्रमाण है।

डॉ. चेलानी की चिंताओं को अमेरिकी इरादों में भी देखा जा सकता है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने ब्राजील के खिलाफ कार्रवाई का कारण बताकर भारत और मैक्सिको का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी जांच में पाया कि ब्राजील ने भारत और मैक्सिको को कई अलग-अलग टैरिफ लाइनों में अनुचित तरजीह दी है, जबकि अमेरिकी कामगारों और उत्पादकों को वैसी तरजीह नहीं मिली।

भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने टैरिफ के चाबुक से ब्राजील और भारत जैसे देशों को डराने की कोशिश की है। पिछले साल भी, अमेरिका ने इन दोनों देशों से आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रयास किया था। भारत को तब रियायत मिली थी जब वह इंडो-यूएस ट्रेड डील को लेकर औपचारिक रूप से सहमत हुआ था। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिक्स देशों की बढ़ती गोलबंदी और ग्लोबल साउथ को लेकर भारत की सक्रियता भी ट्रंप की नाराजगी का एक कारण हो सकती है।

जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 8 संदिग्ध आतंकियों को 7 दिन की और रिमांड

अहमदाबाद। जैश-ए-मोहम्मद से कथित संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आठ संदिग्ध आतंकियों को शुक्रवार को गुजरात के कड़ी स्थित अदालत में पेश किया गया। मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने अदालत से आरोपियों की 10 दिन की अतिरिक्त रिमांड की मांग की। एटीएस ने अदालत को बताया कि आरोपियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अभी गहन जांच की जानी बाकी है। एजेंसी के अनुसार, आरोपियों के पास से बरामद टाइम बम से जुड़े तथ्यों, जैश-ए-मोहम्मद के साहित्य और अन्य अहम दस्तावेजों के आधार पर विस्तृत पूछताछ आवश्यक है। इसके अलावा पूरे नेटवर्क, संपर्क सूत्रों और संभावित सहयोगियों तक पहुंचने के लिए भी अतिरिक्त समय की जरूरत बताई गई। मामले में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कड़ी कोर्ट ने एटीएस की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। अदालत ने 10 दिन के बजाय सभी आठ आरोपियों की 7 दिन की अतिरिक्त रिमांड मंजूर की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी अदालत ने सभी आठ आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा था। अब नई अवधि के दौरान एटीएस तकनीकी और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को और तेज करेगी। एजेंसी आरोपियों के कथित आतंकी संगठन से संबंध, उनकी गतिविधियों, संपर्कों और संभावित साजिश के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करेगी। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले से जुड़े डिजिटल डेटा, जब्त सामग्री और अन्य सबूतों का विश्लेषण जारी है।

नोएडा सोसाइटी में एसी से लगी आग, मेंटेनेंस टीम की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा

नई दिल्ली। भीषण गर्मी के बीच नोएडा के सेक्टर 137 स्थित पारस टिएरा सोसाइटी में आग लगने की एक बड़ी घटना टल गई। सोसाइटी के फ्लैट की सातवीं मंजिल पर लगे एयर कंडीशनर (एसी) में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिससे निवासियों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग फ्लैट के बाहरी हिस्से में लगे एसी यूनिट से शुरू हुई थी। सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने अदम्य साहस और मुस्तैदी दिखाकर तुरंत मोर्चा संभाला। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही टीम ने सोसाइटी के अपने फायर फाइटिंग सिस्टम का उपयोग कर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। उनकी इस तत्परता के कारण आग आसपास के अन्य फ्लैटों में फैलने से रोक दी गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रभावित इलाके का मुआयना किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आग के दोबारा भड़कने का कोई खतरा नहीं है और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार, रिहायशी इमारतों में आग लगने की मुख्य वजह बिजली से जुड़ी खराबी होती है, खासकर गर्मियों के चरम महीनों में जब एयर कंडीशनर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। विशेषज्ञ ऐसी घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए बिजली के उपकरणों की नियमित सर्विसिंग, वायरिंग की जांच और ओवरलोडेड सर्किट से बचने की सलाह देते हैं। हाल ही में नोएडा में आग लगने की कई अन्य घटनाएं भी सामने आई हैं। कुछ समय पहले मामूरा गांव में एक इलेक्ट्रिक बाइक में चिंगारी से लगी आग में दो लोगों की जान चली गई थी और कई परिवार प्रभावित हुए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को सुरक्षा निर्देश जारी किए थे।

यूपी-बिहार में अगले 7 दिन तेज बारिश का अलर्ट

मानसून की वापसी- देश के 60 प्रतिशत हिस्से में बादल

नई दिल्ली । देश का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा फिर बादलों से घिर गया है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले सात दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी बीच, जम्मू-कश्मीर में मानसून आने के बाद से पिछले 15 दिनों में 16 बार बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं, और कश्मीर मौसम केंद्र ने आगे ऐसी घटनाओं में वृद्धि की आशंका जाहिर की है।

मौसम विभाग के अनुसार, भूमध्य रेखा के पास भी एक अन्य मौसमी सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिससे 20 से 30 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश सहित उत्तर और मध्य भारत में भी बारिश की संभावना है। वहीं, तमिलनाडु में आज भीषण गर्मी का अलर्ट है, जहां अल नीनो के प्रभाव से जुलाई में भी तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है।

विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून ट्रफ अब अपने सामान्य स्थान पर लौट रही है, जिससे उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी लेकर आ रही हैं, जो बादलों के निर्माण और कई राज्यों में बारिश का प्रमुख कारण बन रही हैं। इसके साथ ही, पूर्वी और मध्य भारत पर बना कम दबाव का क्षेत्र और चक्रवाती सिस्टम मानसूनी हवाओं को बल दे रहा है, जिससे बारिश में वृद्धि हुई है।

अगले सात दिनों के लिए मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। राजधानी दिल्ली-एनसीआर में भी बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

कांग्रेस ने सोनम वांगचुक के अनशन को समर्थन दिया

-केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान इस्तीफा दें

नई दिल्ली,(ईएमएस) कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उनसे अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने की अपील की। वांगचुक नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। कांग्रेस ने वांगचुक के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया, लेकिन साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की।

पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने वांगचुक से अनशन खत्म करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि वांगचुक जिन मुद्दों को लेकर चिंतित हैं, वे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लिए बड़ी चिंता का विषय हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि पार्टी पिछले दो महीनों से लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर कायम है। उन्होंने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 17 जून को कोटा में मांग को सबसे पहले उठाया था और देहरादून में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान भी वे इस विषय पर अपनी बात रखने वाले है।

सोनम वांगचुक 28 जून को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 25 दिनों से अधिक समय से चल रहे विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए थे। सीजेपी भी नीट पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। खेड़ा का यह दौरा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव के विरोध स्थल पर वांगचुक से मिलने के एक दिन बाद हुआ है। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत करने और सीजेपी की मांगों पर ध्यान देने का आग्रह किया था।

आशीष दुबे / 17 जुलाई 2026

ट्रेन की स्कूल वैन से टक्कर,5 की मौत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन ने एक पूल कार (स्कूली गाड़ी) को टक्कर मार दी। अधिकारियों के मुताबिक, टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई है, जिनमें तीन स्कूली छात्र शामिल हैं। गाड़ी रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश कर रही थी। टक्कर में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल में भर्ती कराए गए लोगों में से कुछ की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, जब एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी तब रेलवे क्रॉसिंग बंद थी। लेकिन उसके तुरंत बाद गेट को खोल दिया गया, जबकि वहां से एक पैसेंजर ट्रेन भी गुजरने वाली थी। स्कूल वैन के ड्राइवर ने गेट खुला देखकर गाड़ी को पटरियों के पार ले जाने की कोशिश की। इसी दौरान एक साइकिल सवार भी पटरी पार करने लगा। तभी तेज रफ्तार में आ रही निमतिया-कटवा लोकल ट्रेन ने स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और बच्चे अंदर ही फंस गए।

आंध्रप्रदेश में कोरोना के 12 मामले, 4 मौत

जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजे गए सैंपल, पड़ोसी राज्य कर्नाटक में बरती जा रही सावधानी

अमरावती। आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई के बीच कोरोना संक्रमण के 12 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य सरकार ने वायरस के वैरिएंट का पता लगाने के लिए 5 सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे भेजे हैं। उधर पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी सावधानियां बढ़ा दी गई हैं। आंध्र प्रदेश की स्वास्थ्य सचिव और कमिश्नर वीरा पांडियन के मुताबिक, जिन 4 मरीजों की मौत हुई, वे पहले से ही गंभीर बीमारियों जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज और किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। राज्य में अब तक कुल 339 कोरोना मामले सामने आए हैं, जिनमें से 12 आंध्र प्रदेश के हैं।

आंकड़ों के अनुसार, कडपा में 8, गुंटूर में 2, विशाखापत्तनम और काकीनाडा में 1-1 मामला दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये मामले अलग-अलग इलाकों से हैं और कहीं भी क्लस्टर नहीं बना है। फिलहाल 3 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 2 अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 3 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। विशाखापत्तनम के अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉ. वाणी ने बताया कि

वहां एक मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। लक्षण दिखने पर डॉक्टर ने उसे टेस्ट की सलाह दी थी। निजी लैब में पुष्टि के बाद ्यत्र॥ अस्पताल में भी दोबारा जांच की गई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

प्रशासन की अपील- घबराएं नहीं

आंध्र प्रदेश की स्वास्थ्य सचिव वीरा पांडियन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि राज्यभर के अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। देशभर में 1 जुलाई से अब तक 339 कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं।

पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी सावधानी बरती जा रही

कोराना के नए मामलों को देखते हुए आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी सावधानी बरती जा रही है। तुमकुरु जिले की डिप्टी कमिश्नर शुभा कल्याण ने कहा कि आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। हमारे तुमकुरु जिले की कुछ तहसीलें, जैसे पावागड़ा, आंध्र प्रदेश की सीमा से लगी हुई हैं। इसलिए एहतियात के तौर पर हमने सावधानी संबंधी उपाय लागू करने का फैसला किया है।

131 करोड़ रूपये के कथित अवैध बालू खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, बिहार-दिल्ली-राजस्थान के 8 ठिकानों पर छापेमारी

बांका। बिहार के बांका जिले में 131 करोड़ रूपये के कथित अवैध बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार, दिल्ली और राजस्थान के कुल आठ ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। पटना जोनल कार्यालय की टीम ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की। छापेमारी के बाद अवैध खनन से जुड़े कारोबारी और कथित सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है।

- महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड जांच के केंद्र में

ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई मुख्य रूप से महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े परिसरों पर केंद्रित रही। जांच एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने बांका जिले के विभिन्न बालू घाटों पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और वित्तीय गड़बड़ियां की हैं। कंपनी का संचालन राजस्थान के श्रीगंगानगर निवासी चांदक परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें अशोक चांदक और उनके पुत्र राघव चांदक की प्रमुख भूमिका बताई गई है। ईडी के अनुसार, कंपनी की गतिविधियों और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच की जा रही है। जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि अवैध खनन से अर्जित धन का उपयोग किन-किन माध्यमों से किया गया और उसे किस प्रकार वैध दिखाने का प्रयास किया गया।

- आईआईटी पटना की रिपोर्ट से खुला कथित अवैध खनन का मामला

जांच में सामने आया है कि वित्त वर्ष 2015-16 से 2022-23 के बीच बांका जिले के विभिन्न बालू घाटों पर कथित तौर पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया गया। आरोप है कि यह खनन निर्धारित नियमों और स्वीकृत सीमा से अधिक था तथा इसका पूरा रिकॉर्ड राज्य के खनन विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। मामले में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अक्टूबर 2024 में आईआईटी पटना ने जियोस्पेशियल (सैटेलाइट आधारित) तकनीक से खनन क्षेत्रों का विश्लेषण किया। इस तकनीकी अध्ययन में लगभग ?131 करोड़ के कथित अवैध बालू खनन की बात सामने आई, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लिया।

- तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर

ईडी ने आईआईटी पटना की रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत अपनी रिपोर्ट बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भेजी थी। इसके बाद खान एवं भू-तत्व विभाग ने 21 अगस्त 2025 को इस मामले में औपचारिक एफआईआर दर्ज कराई। इसी एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और अब व्यापक स्तर पर छापेमारी की कार्रवाई की है।

– बिहार, दिल्ली और राजस्थान में एक साथ छापेमारी

ईडी की टीमों ने बिहार के बांका और पटना में दो-दो स्थानों पर, दिल्ली-एनसीआर में एक स्थान पर तथा राजस्थान के श्रीगंगानगर में चार और जयपुर में एक स्थान पर तलाशी अभियान चलाया। बांका जिले के कटोरिया बस स्टैंड के समीप स्थित लाल कोठी, जहां महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड का मुख्य कार्यालय बताया जाता है, वहां भी ईडी ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कार्यालय का मुख्य द्वार बंद रखा गया और जांच एजेंसी की टीम कई घंटों तक दस्तावेजों की जांच करती रही।

– दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त

छापेमारी के दौरान ईडी ने कई महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, डिजिटल रिकॉर्ड, बैंकिंग से जुड़े कागजात और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए हैं। इनकी फॉरेंसिक जांच और वित्तीय विश्लेषण किया जा रहा है ताकि कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और अवैध वित्तीय लेनदेन की पूरी श्रृंखला का पता लगाया जा सके। फिलहाल ईडी ने मामले में किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। जांच एजेंसी का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तीन दिन की हड़ताल खत्म, लेकिन आंदोलन जारी...

अब काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ जताएंगे विरोध

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले तीन दिनों से सामूहिक अवकाश पर चल रहे प्रदेशभर के साथ-साथ बालाघाट जिले के पटवारियों की हड़ताल शुक्रवार 17 जुलाई को समाप्त हो गई। हालांकि, पटवारियों ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि अब यह दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। 18 जुलाई से सभी पटवारी अपने-अपने कार्यस्थलों पर लौटकर राजस्व संबंधी कार्य तो करेंगे, लेकिन विरोध स्वरूप हाथों में काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी दर्ज कराएंगे। यदि इसके बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो अगस्त माह से आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश पटवारी संघ के जिला पदाधिकारी अरुण बिरनवार ने दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश संगठन के आह्वान पर 15 से 17 जुलाई तक सामूहिक अवकाश लेकर प्रदेश के हजारों पटवारियों ने सरकार का ध्यान अपनी वर्षों से लंबित मांगों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था। संगठन को उम्मीद थी कि आंदोलन के दौरान सरकार बातचीत के लिए आगे आएगी और मांगों के समाधान की दिशा में कोई सकारात्मक पहल करेगी, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी शासन की ओर से न तो कोई ठोस आश्वासन मिला और न ही किसी मांग पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय सामूहिक अवकाश की अवधि अब समाप्त हो रही है, इसलिए संगठन ने फिलहाल काम पर लौटने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य आम जनता को अनावश्यक परेशानी से बचाना भी है,

लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि पटवारी अपनी मांगों से पीछे हट गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन अब चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा और सरकार पर दबाव बनाने के लिए अलग-अलग माध्यमों से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अरुण बिरनवार ने बताया कि 18 जुलाई से जिले के सभी पटवारी नियमित रूप से अपने कार्यालयों और हल्कों में कार्य करेंगे, लेकिन पूरे समय अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर सरकार के प्रति विरोध दर्ज कराएंगे। यह विरोध शांतिपूर्ण होगा, ताकि एक ओर राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित न हों और दूसरी ओर शासन तक कर्मचारियों की नाराजगी का संदेश भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश संगठन लगातार शासन के संपर्क में है और उच्च स्तर पर वार्ता की कोशिशें जारी हैं।

2 अगस्त के बाद आंदोलन को दिया जाएगा नया स्वरूप

यदि सरकार ने जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 2 अगस्त के बाद प्रदेश संगठन की बैठक में आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी। उस समय आंदोलन को और व्यापक तथा प्रभावी स्वरूप दिया जाएगा। संगठन इस संबंध में पूरे प्रदेश के पटवारियों से चर्चा कर अंतिम रणनीति तैयार करेगा। पटवारी संघ का कहना है कि उनकी मांगें नई नहीं हैं, बल्कि कई वर्षों से लंबित हैं। इनमें विभागीय परीक्षा शीघ्र आयोजित करना, परीक्षा का पाठ्यक्रम राजस्व विभाग के कार्यों के अनुरूप तय करना, पटवारियों को जज प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में शामिल करना, लंबे समय से लंबित विभिन्न वित्तीय भुगतानों का शीघ्र भुगतान करना तथा पटवारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए नियमित परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करना प्रमुख रूप से शामिल है। संघ का यह भी कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में कई बार न्यायालयीन मामलों में पटवारी केवल प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जबकि अंतिम निर्णय तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा लिया जाता है। इसके बावजूद कई मामलों में सीधे पटवारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में पटवारियों को भी अन्य राजस्व अधिकारियों की तरह कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा संगठन का आरोप है कि प्रदेश के कई जिलों में पटवारियों ने शासन के विभिन्न कार्य अपने निजी संसाधनों और खर्च पर पूरे किए हैं, लेकिन उनका भुगतान आज तक नहीं किया गया। वहीं विभागीय परीक्षाएं लंबे समय से आयोजित नहीं होने के कारण पदोन्नति और सेवा संबंधी अवसर भी प्रभावित हो रहे हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। तीन दिनों तक चली हड़ताल के दौरान जिले में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, भू-अभिलेखों से जुड़े कार्य, फसल संबंधी प्रतिवेदन और अन्य राजस्व सेवाएं प्रभावित हुईं। हालांकि अब 18 जुलाई से पटवारी काम पर लौटने के बाद ये कार्य दोबारा शुरू होंगे, लेकिन आंदोलन की आग अभी शांत नहीं हुई है। अब प्रदेशभर के पटवारियों की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। यदि जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो अगस्त माह में यह आंदोलन एक बार फिर बड़े स्तर पर सामने आ सकता है। फिलहाल पटवारी काम पर लौटकर भी विरोध जारी रखेंगे और काली पट्टी बांधकर सरकार तक अपनी नाराजगी पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

खेलते खेलते खुले कुएं में गिरे भाई-बहन

6 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत, 14 वर्षीय भाई की हालत स्थिर

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। बिरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी सालेटेकरी के ग्राम बहेराभाटा में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। घर के पास खेल रहे भाई बहन अचानक खुले कुएं में गिर गए। इस हादसे में 6 वर्षीय मासूम बालिका की मौत हो गई। जबकि उसका 14 वर्षीय भाई ग्रामीणों की तत्परता से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिसे बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया है घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल निर्मित हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बहेराभाटा निवासी बियासलाल मातरे के पुत्र यानस मातरे 14 वर्ष और पुत्री भूमिका मातरे 6 वर्ष गुरुवार दोपहर लगभग तीन बजे घर के समीप खेल रहे थे। खेलते-खेलते दोनों बच्चे गांव के एक ऐसे कुएं के पास पहुंच गए, जिसके चारों ओर न तो सुरक्षा दीवार जगत बनी थी और न ही फेंसिंग की गई थी। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और दोनों गहरे कुएं में जा गिरे।कुएं से बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए रस्सियों और अन्य उपलब्ध साधनों की मदद से दोनों बच्चों को काफी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा पहुंचाया गया।अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद 6 वर्षीय भूमिका मातरे को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल यानस मातरे का उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी सालेटेकरी की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक पंचनामा कार्रवाई की। पुलिस ने मासूम।बालिका भूमिका का शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस कुएं में यह हादसा हुआ।वह पूरी तरह खुला था और उसके चारों ओर किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कुएं पर सुरक्षा दीवार या फेंसिंग होती तो संभवत: यह दर्दनाक हादसा टल सकता था।इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे बहेराभाटा गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मासूम बेटी की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव सहित आसपास के सभी खुले कुओं की तत्काल पहचान कर उनकी सुरक्षा के लिए जगत और फेंसिंग का निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह की अपूरणीय क्षति का सामना न करना पड़े।

विद्युत करंट से एक कृषक की मौत

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम खजरा में इसी ग्राम के एक कृषक की विद्युत करंट से मौत हो गई। 17 जुलाई को 12:00 बजे करीब यह हादसा उस समय हुआ जब यह कृषक अपने खेत विद्युत मोटर पंप चालू करने के लिए गया था। गढ़ी पुलिस ने मृतक कृषक अशोक पिता शगुन लाल यादव 42 वर्ष का शव पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजनों को सोप दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक यादव अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है। जिसमें अपने खेत की फसल में पानी चलाने के लिए समीप नाले में विद्युत मोटर लगाई थी। 17 जुलाई को अशोक यादव अपने परिवार के साथ कृषि कार्य करने के लिए खेत गया था और कृषि कार्य के दौरान वह नाले में लगी मोटर चालू करने के लिए गया तभी उसे जबरदस्त विद्युत करंट लगा। आवाज सुनकर खेत पड़ोसी और परिवार के लोग दौड़े और अशोक यादव को तुरंत ही गढ़ी की अस्पताल लाये किंतु डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिए। कृषक अशोक यादव की अस्पताल लाते समय ही रास्ते में मौत हो चुकी थी। गढ़ी पुलिस ने मृतक कृषक अशोक यादव का शव अपने कब्जे में लेकर पंचनामा करवाई पश्चात पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजनों को सौंप दिया है और धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मर्ग कायम कर जहां शुरू की है।

18 घंटे से लापता मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति का पेड़ में फांसी पर लटका मिला शव

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। बिरसा थाना क्षेत्र के ग्राम बोरखेड़ा से करीब 18 घंटे से लापता एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव शुक्रवार सुबह ग्राम की फॉरेस्ट नर्सरी में पेड़ से लटका हुआ बरामद हुआ। बिरसा पुलिस ने मृतक संतराम पिता राय सिंह मरावी का शव पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजन को सौंप दिया है

प्राप्त जानकारी के अनुसार संतराम अपने छोटे भाई अंतराम के साथ रहता था और खेती-मजदूरी का काम करता था। परिजनों के मुताबिक संतराम की मानसिक स्थिति कुछ समय से ठीक नहीं थी।16जुलाई की दोपहर करीब 1 बजे संतराम बिना बताए घर से निकला था। रात तक वापस न लौटने पर परिजनों ने गांव और आसपास तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।17 जुलाई की सुबह 5 बजे भैंस चराने गए अमरूद यादव ने घर आकर सूचना दी कि संतराम फॉरेस्ट नर्सरी में पेड़ से लटका हुआ है। सूचना मिलते ही भाई अंतराम परिवार के साथ मौके पर पहुंचा देखा उसका भाई संतलाल महुआ के पेड़ में नायलॉन की रस्सी में फांसी पर लटका हुआ था।सूचना पर बिरसा पुलिस तत्काल बोरखेड़ा पहुंची। पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए बिरसा अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।प्रारंभिक जांच में संतलाल के द्वारा मानसिक अवसाद के चलते आत्मघाती कदम उठाए जाने की संभावना जताई है। बिरसा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाही

सावजी भोजनालय में मिली भारी गंदगी, जैन बेकरी के खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर खाद्य सुरक्षा प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में प्राप्त शिकायतों के आधार पर गर्रा स्थित सावजी भोजनालय और जैन बेकरी में औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान सावजी भोजनालय में गंभीर स्वच्छता संबंधी खामियां सामने आने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया, जबकि जैन बेकरी से खाद्य नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने गर्रा स्थित सावजी भोजनालय का निरीक्षण किया। जांच में प्रतिष्ठान का खाद्य सुरक्षा पंजीयन तो वैध पाया गया, लेकिन किचन और परिसर की हालत बेहद खराब मिली। निरीक्षण के दौरान किचन एवं बर्तन धुलाई क्षेत्र की दीवारें और फर्श जर्जर एवं टूटी-फूटी पाए गए। परिसर में मक्खियों का प्रकोप, गंदगी, अव्यवस्थित रखरखाव तथा अस्वच्छ वातावरण देखने को मिला। अधिकारियों ने इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित भोजनालय के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। इसी तरह, जैन बेकरी के खिलाफ खाद्य पदार्थों में रसायनों एवं कृत्रिम रंगों के उपयोग की शिकायत मिलने पर जांच की गई। कार्रवाई के दौरान डोनट, इंप्रूवर, एनहांसर सहित अन्य खाद्य सामग्री के नमूने एकत्रित कर विधिवत परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में आम नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे। मिलावट, अस्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तेज रफ्तार थार ने बाइक को मारी टक्कर, मां-बेटी घायल

खुरसोडी फोरलेन ओवरब्रिज के पास हुआ हादसा, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुरसोडी स्थित फोरलेन ओवरब्रिज के पास गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार थार वाहन ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां-बेटी घायल हो गईं, जबकि महिला के पति को मामूली चोटें आईं। घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचाया गया। दोनो घायल बालवंती पति गन्नूलाल खैरवार 35 वर्ष और उनकी बेटी रजनी खैरवार 18 वर्ष ग्राम सुरेखा बालाघाट निवासी है।जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालवंती खैरवार निवासी ग्राम सरेखा, अपने परिवार के साथ खेती किसानी का कार्य करती हैं। बुधवार को वह अपनी 18 वर्षीय बेटी रजनी खैरवार और पति गन्नूलाल के साथ किसी कार्य से किरनापुर क्षेत्र के आमगांव गई थीं। गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे तीनों मोटरसाइकिल से अपने घर सरेखा लौट रहे थे।मोटरसाइकिल गन्नूलाल खैरवार चला रहे थे।इसी दौरान ग्राम खुरसोडी फोरलेन के ओवरब्रिज के समीप पीछे से तेज गति से आ रही एक थार ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे में बालवंती खैरवार और उनकी बेटी रजनी घायल हो गईं।जबकि गन्नूलाल को मामूली चोटें आईं।दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और तीनों को जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया। यहां चिकित्सकों ने बालवंती और रजनी को भर्ती कर उपचार शुरू किया।जबकि गन्नूलाल का प्राथमिक उपचार किया गया।जिला अस्पताल पुलिस ने घायल बालवंती खैरवार के बयान दर्ज कर अस्पताल तहरीर तैयार की और अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित ग्रामीण थाना को भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आवश्यकता है
क्वार्क में पेज सेटिंग हेतु
कम्प्युटर ऑपरेटर की आवश्यकता है
संपर्क करें-बालाघाट एक्सप्रेस
पद्मेश सिटी केबल, काली पुतली चौक, बालाघाट

AICTE भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं RGPV & DTE भोपाल से सम्बध्द
सतपुड़ा कॉलेज ऑफ
इंजीनियरिंग एण्ड पॉलिटेक्निक
बी.टेक. पॉलिटेक्निक
JOB SAHi
- कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
- माईनिंग इंजीनियरिंग
- सिविल इंजीनियरिंग
- मैकेनिकल इंजीनियरिंग
- इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
ADMISSION OPEN
नई शिक्षा नीति के तहत किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों का Lateral Entry द्वारा बी.टेक. के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश
सतपुड़ा कैम्पस, लालबर्रा रोड, गर्रा-बालाघाट
6262604111, 9425836824 www.satpudaengineeringcollege.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट(म.प्र.) से प्रकाशित,
प्रधान संपादक : उमेश बागरेचा, मो.नं. :9425138710, , ई-मेल- balaghatexpress@gmail.com पंजीयन क्रं. MPHIN/2009/32311, न्यायलयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट